मेरी खेती

PAGE NO. 1-37 / अगस्त 2022

खेत खलियान
सब्ज़ी
फल
फूल
सरकारी नीतियां
किसान समाचार
औषधीय खेती
पशुपालन-पशुचारा
मिट्टी की सेहत - खाद
प्रगतिशील किसान

WWW.MERIKHETI.COM

श्री छेदालाल पाठक
(संरक्षक मार्गदर्शक)

डॉ. एमसी शर्मा,
सेवानिवृत्त निदेशक एवं कुलपति आईवीआरआई इज्जतनगर

प्रो. ए पी. सिंह
पूर्व कुलपति वेटरनरी विश्वविद्यालय मथुरा

डॉ.एस.के.गर्ग
कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस

डॉ.ओमवीर सिंह
निदेशक [illegible]
(सेवानिवृत्त) उत्तर प्रदेश

डॉ. उदय भान सिंह
डीन कृषि महाविद्यालय कुम्हेर
भरतपुर राजस्थान

श्री सुधीर अग्रवाल
(प्रगतिशील किसान)

दिलीप यादव
(विशेषज्ञ,मशीनरी)

तेजपाल सिंह
(प्रगतिशील किसान)

कृष्ण पाठक
(विशेषज्ञ,मशीनरी)

विषय सूची

खेत खलियान PAGE NO. 1-6

1. किस क्षेत्र में लगायें किस किस्म की मसूर, मिलेगा ज्यादा मुनाफा
2. लोबिया की खेती से किसानों को होगा दोहरा लाभ
3. स्वर्ण शक्ति: धान की यह किस्म किसानों की तकदीर बदल देगी
4. बाजरे की खेती
5. अरहर की खेती
6. लेट मानसून में भी पैदा करना है बंपर सोयाबीन, तो करें मात्र ये काम
7. जानिये कम लागत वाली मक्का की इन फसलों को, जो दूध के जितनी पोषक तत्वों से हैं भरपूर

सब्ज़ी PAGE NO. 7-10

1. मात्र 70 दिन में उगे यह रंग-बिरंगी उन्नत शिमला मिर्च (CAPSICUM)
2. बारिश में लगाएंगे यह सब्जियां तो होगा तगड़ा उत्पादन, मिलेगा दमदार मुनाफा
3. टमाटर की खेती में हो सकती है लाखों की कमाई : जानें उन्नत किस्में
4. अत्यधिक गर्मी से खराब हो रहे हैं आलू और प्याज, तो अपनाएं ये तरीके आज
5. इस तकनीकी से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी 90% सब्सिडी

फल PAGE NO. 11

1. शुगर फ्री और बेहद स्वादिष्ट है मुजफ्फरपुर का यह रंगीन आम
2. इस तरह लगाएं केला की बागवानी, बढ़ेगी पैदावार

फूल PAGE NO. 12

1. कीचड़ में ही नहीं खेत में भी खिलता है कमल, कम समय व लागत में मुनाफा डबल !

सरकारी नीतियां PAGE NO. 13-18

1. बकरी बैंक योजना ग्रामीण महिलाओं के लिये वरदान
2. किसानों के लिए खुशी की खबर, अब अरहर, मूंग व उड़द के बीजों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को क्या है फायदा
4. कुसुम योजना के तहत 60% अनुदान पर किसानों को मिलेगा सोलर पंप
5. राजस्थान सरकार देगी निशुल्क बीज : बारह लाख किसान होंगे लाभान्वित
6. रोका-छेका अभियान : आवारा पशुओं से फसलों को बचाने की पहल
7. कोल्ड स्टोरेज योजना में सरकारी सहायता पच्चास प्रतिशत तक
8. एग्री लोन लें फसल बुवाई पर, चुकाएं किसान कटाई पर : प्रोत्साहन राशि दे रही सरकार उस पर
9. डीएसआर तकनीकी से धान रोपने वाले किसानों को पंजाब सरकार दे रही है ईनाम
10. उत्तर प्रदेश बजट 2.0 में यू.पी. के किसानों को क्या मिला ?
11. अब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ
12. किसानों को भरपूर डीएपी, यूरिया और एसएसपी खाद देने जा रही है ये सरकार
13. किसानों को मिलेगा चार हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान, लगायें ये फसल

किसान समाचार PAGE NO. 19-24

1. कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए किसान कर रहे हैं इस तकनीकी का प्रयोग
2. अब रूस देगा जरूरतमंद देशों को सस्ती कीमतों पर गेंहू, लेकिन पूरी करनी पड़ेगी यह शर्त
3. ONION PRICE: प्याज के सरकारी आंकड़ों से किसान और व्यापारी के छलके आंसू, फायदे में क्रेता
4. फसल बीमा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान शुरू
5. कश्मीर में हुई पहली ऑर्गेनिक मार्केट की शुरुआत, पौष्टिक सब्जियां खरीदने के लिए जुट रही है भारी भीड़
6. इस राज्य में बनने जा रहीं है नंदीशालाएं, किसानों को मिलेगी राहत
7. भारत में 2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा UAE, जानिये इंटीग्रेटेड फूड पार्क के बारे में
8. आजादी के अमृत महोत्सव में डबल हुई किसानों की आय, 75000 किसानों का ब्यौरा तैयार – केंद्र
9. MSP ON CROP: एमएसपी एवं कृषि विषयों पर सुझाव देने वृहद कमेटी गठित, एक संगठन ने बनाई दूरी
10. एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी भारत में बनेगी, कई राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा
11. कुवैत में खेती के लिए भारत से जाएगा 192 मीट्रिक टन गाय का गोबर
12. इस राज्य की सरकार किसानों के साथ कर रही है छलावा या मजाक?
13. कीटनाशक दवाएं महंगी, मजबूरी में वाशिंग पाउडर छिड़काव कर रहे किसान

औषधीय खेती PAGE NO. 25-29

1. घर में ऐसे लगाएं करी-पत्ता का पौधा, खाने को बनाएगा स्वादिष्ट एवं खुशबूदार
2. कैसे करें हल्दी की खेती, जाने कौन सी हैं उन्नत किस्में
3. तितली मटर (अपराजिता) के फूलों में छुपे सेहत के राज, ब्लू टी बनाने में मददगार, कमाई के अवसर अपार
4. घर के गमले में अदरक का पौधा : बढ़ाये चाय की चुस्की व सब्जियों का जायका
5. EUCALYPTUS यानी सफेदा का पौधा लगाकर महज दस साल में करें करोड़ों की सफेद कमाई!
6. घर पर उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन जड़ी बूटियां
7. तुलसी के पौधों का मानव जीवन में है विशेष महत्व

पशुपालन-पशुचारा PAGE NO. 30

1. थनैला रोग को रोकने का एक मात्र उपाय टीटासूल लिक्विड स्प्रे किट
2. भैंस पालन से भी किसान कमा सकते हैं बड़ा मुनाफा

मिट्टी की सेहत - खाद PAGE NO. 31

1. ऐसे करें असली और नकली खाद की पहचान, जानिए विशेष तरीका
2. अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी यूरिया की किल्लत

प्रगतिशील किसान PAGE NO. 32-37

1. एक शख्स जो धान की देसी किस्मों को दे रहा बढ़ावा, किसानों को दे रहा मुफ्त में देसी बीज
2. मध्यप्रदेश के केदार बाँट चुके हैं 17 राज्यों के हजारों लोगों को मुफ्त में देसी बीज
3. वेस्ट फूलों से घर में ही कर सकते हैं अगरबत्ती का बिजनेस
4. पेपर स्ट्रॉ की बढ़ी मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर सकते हैं ये मुनाफे का व्यवसाय
5. कम जमीन हो तो इजराईली तकनीक से करें खेती, होगी मोटी कमाई
6. केमिस्ट्री करने वाला किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग से खेत में पैदा कर रहा मोती, कमाई में कई गुना वृद्धि!
7. जैविक खेती पर इस संस्थान में मिलता है मुफ्त प्रशिक्षण, घर बैठे शुरू हो जाती है कमाई
8. ऑर्गेनिक खेती से रेतीली जमीन उगल रही सोना

आजादी के अमृत महोत्सव में डबल हुई किसानों की आय, 75000 किसानों का ब्यौरा तैयार – केंद्र

परिषद ने पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव में किसानों की सफलता का दस्तावेजीकरण करने का टारगेट तय किया था। इस वर्ग में ऐसे कृषक मित्र शामिल हैं जिनकी आय दोगुनी हुई है या फिर इससे ज्यादा बढ़ी है। परिषद के अनुसार ऐसे 75 हजार किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण कर किसानों का ब्यौरा जारी किया गया है।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आय बढ़ने वाले लाखों किसानों में से 75 हजार किसानों के संकलन का एक ई-प्रकाशन तैयार कर उसे जारी किया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समारोह में कहा कि, देश में कृषि क्षेत्र एवं कृषक मित्रों का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों के समन्वित प्रयास के साथ ही जागरूक किसान भाईयों के सहयोग से किसान की आय में वृद्धि हुई है। परिषद ने 'डबलिंग फार्मर्स इनकम' पर राज्य आधारित संक्षिप्त प्रकाशन भी तैयार किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विमोचन अवसर पर ई-बुक को जारी किया।

कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 94वें स्थापना दिवस पर मंत्री तोमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिकों व किसानों को पुरस्कृत भी किया। पूसा परिसर, दिल्ली में आयोजित समारोह में तोमर ने कहा कि, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आईसीएआर ने पिछले साल, आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे 75 हजार किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिनकी आय दोगुनी या इससे ज्यादा दर से बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि सफल किसानों का यह संकलन भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने आईसीएआर के समारोह में अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उन्होंने आईसीएआर के स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की बात इस दौरान कही।
मंत्री तोमर ने प्रधानमंत्री की विजन आधारित नई शिक्षा नीति का उदय होने की बात कही। उन्होंने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम के समावेश में कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री तोमर ने दलहन, तिलहन, कपास उत्पादन में प्रगति के लिए आईसीएआर (ICAR) और केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)) को अपने प्रयास बढ़ाने प्रेरित किया।

समारोह के पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों से कृषि मंत्री ने ऑनलाइन तरीके से विचार साझा किए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों से हुई चर्चा में सरकारी योजनाओं, संस्थागत सहयोग से किसानों की आय में किस तरह वृद्धि हुई इस बात की जानकारी मिली।

दिलीप यादव
मेरी खेती

NEW HOLLAND
AGRICULTURE
MERIKHETI
सुपर अब है
सुपर प्लस+
50+ Plus
3630 SUPER Plus+
मानसून धमाका ऑफर
₹8 00 000/-
₹7 59 999/-*
डबल क्लच एवं पावर स्टीयरिंग
टायर साईज: 16.9 x 28 inch (0.42 x 0.71 m)
NEW HOLLAND 3630
इंडस्ट्री में पहली बार
6 साल
T- वारंटी
ऑफर
31 जुलाई 2022
तक मान्य
Visit us at - www.newholland.com/in
*यह ऑफर केवल न्यू हॉलैंड के हरियाणा के डीलरों के सौजन्य से। नियम व शर्तें लागू।

ESCORTS

MERIKHETI

FARMTRAC 6037 PLUS

(CHAMPION)

41 HP

खेत खलियान

भारत में बड़ी मात्र में मसूर की खेती होती है. भारत विश्व में मसूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है. महत्वपूर्ण दलहन फसलों में से एक मसूर (LENTIL) को माना जाता है. मसूर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. मसूर में स्टार्च भी उपलब्ध होता है जो छपाई और कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है. इसका उपयोग ब्रेड और केक बनाते समय गेहूं के आटे में मिलाकर किया जाता है.

मसूर के गुण

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, मसूर की दाल ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के साथ ही सुपाच्य भी हैं। इसमें मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व (MICRONUTRIENTS) और प्रीबायोटिक कार्बोहाइड्रेट सेहत के लिए लाभदायक हैं।

एक कप मसूर दाल में लगभग 230 कैलोरी होती है और 15 ग्राम के करीब डाइटरी फाइबर, साथ में 17 ग्राम प्रोटीन होता है. आयरन और प्रोटीन से परिपूर्ण यह दाल शाकाहारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है.

मसूर खून को बढ़ाके शारीरिक कमजोरी दूर करती है, स्पर्म क्वालिटी को दुरुश्त रखती है. पीठ व कमर दर्द में इससे आराम मिलता है. मसूर दाल में मौजूद फोलिक एसिड त्वचा रोगों, जैसे चेहरे के दाग, आंखों में सूजन आदि के लिए रामबाण है।

यही कारण है कि मसूर की मांग और मूल्य हमेशा ज्यादा रहती है. मसूर कि खेती से किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

मसूर की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण

मसूर दाल की खेती के लिये ठंडे वातावरण की जरूरत पड़ती है. यह कठोर सर्दियों और ठंड का सामना आसानी से कर सकता है

मसूर की खेती के लिए उपयुक्त जमीन कैसे हो ?

मसूर की खेती के लिये मिट्टी की बात करें, तो इसे उगाने के लिए सूखी दोमट मिट्टी अच्छी होती है. लेकिन देश में अलग अलग वातावरण और मिट्टी का प्रकार है. इसीलिये, आज राज्यों के वातावरण और मिट्टी के अनुरूप मसूर के किस्मों की जानकारी देंगें, जिससे मसूर की खेती करने वाले किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.

राज्यवार मसूर की अनुशंसित किस्में

पश्चिम बंगाल में मसूर की किस्म
किस्में- WBL-58 WBL-81

बिहार में मसूर की किस्म
किस्में- पंत एल 406, पीएल 639, मल्लिका (के -75), एनडीएल 2, डब्ल्यूबीएल 58, एचयूएल 57, डब्ल्यूबीएल 77, अरुण (पीएल 777-12)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मसूर की किस्म
किस्में- मलाइका (K-75), IPL-81 (नूरी), JL-3, IPL-406, L-4076, IPL316, DPL 62 (शेरी)

गुजरात में मसूर की किस्म
किस्में- मलाइका (K-75), IPL-81 (नूरी), L-4076, JL-3

हरियाणा में मसूर की किस्म
किस्में- पंत एल-4, डीपीएल-15 (प्रिया), सपना, एल-4147, डीपीएल-62 (शेरी), पंत एल-406, पंत एल-639

महाराष्ट्र में मसूर की किस्म
किस्में- जेएल 3, आईपीएल 81 (नूरी), पंत एल 4

पंजाब में मसूर की किस्म
किस्में- PL-639, LL-147, LH-84-8, L-4147, IPL-406, LL-931, PL 7

राजस्थान में मसूर की किस्म
किस्में- पंत एल-8 (पीएल-063), डीपीएल-62 (शेरी), आईपीएल 406 (अंगूरी)

उत्तराखंड में मसूर की किस्म
किस्में- वीएल-103, पीएल-5, वीएल-507, पीएल-6, वीएल-129, वीएल-514, वीएल-133

जम्मू और कश्मीर में मसूर की किस्म
किस्में- वीएल 507, एचयूएल 57, पंत एल 639, वीएल 125, वीएल 125, पंत एल 406

उत्तरभारत में मसूर की किस्म
किस्में- PL-639, मलिका (K-75), NDL-2, DPL-62, IPL-81, IPL-316, L4076, HUL-57, DPL 15

लोबिया की खेती से किसान काफी लाभ कमा सकते हैं। दलहन फसल की श्रेणी के लोबिया की खेती (LOBIA FARMING) से दो तरीके से लाभ होता है। लोबिया की फलियों की सब्जी होती है। इसका प्रयोग पशुचारा और हरी खाद के रूप में किया जाता हैं। इसे बोड़ा, चौला या चौरा, करामणि, काऊपीस – (COWPEA) भी कहा जाता है। यह सफेद रंग का और बड़ा पौधा होता है। इसकी फलियां पतली, लंबी होती हैं और इसके फल एक हाथ लंबे और तीन अंगुल तक चौड़े और कोमल होते है।

लोबिया की खेती के लिए जलवायु

गर्म व आर्द्र जलवायु में 24-27 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान में लोबिया की खेती होती है।

लोबिया की खेती कैसी जमीन में करनी चाहिये ?

- लोबिया की खेती वैसे जमीन में करनी चाहिये, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो।
- क्षारीय भूमि इसकी खेती के लिये के उपयुक्त नहीं होता है।
- इसके मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए।

लोबिया की खेती कब करनी चाहिये ?

लोबिया की बुआई बरसात के मौसम में जून के अंत से लेकर जुलाई माह तक और गर्मी के मौसम में फरवरी-मार्च में की जाती है।

लोबिया की खेती में खाद, खर पतवार नियंत्रण व सिंचाई

- बुवाई के पूर्व लोबिया के बीज का राजजोबियम नामक जीवाणु से उपचार जरूरी होता है।
- खेत में गोबर या कम्पोस्ट की 20 टन मात्रा बुवाई से एक माह पहले डालनी चाहिए। नत्रजन 20 किग्रा, फास्फोरस 60 कि.ग्रा. तथा पोटाश 50 कि.ग्रा. की मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से जुलाई के अंत में मिट्टी में मिलानी चाहिए।
- फसल में फूल आने के समय नत्रजन की 20 कि.ग्रा. की मात्रा फसल में देनी चाहिए।
- लोबिया के पौधों की दो-तीन निराई व गुड़ाई करनी चाहिए ताकि खर पतवार पर नियंत्रण रह सके।
- गर्मी में इसकी फसल को पर 5 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। इसकी सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतर पर करनी चाहिए।

लोबिया – COWPEA(LOBIA/KARAMANI) मंडी भाव

30 जून 2022 को मुंबई मंडी में लोबिया मूल्य 7128 रुपए प्रति क्विंटल था।

लोबिया की उन्नत किस्में

लोबिया की कई उन्नत किस्में हैं। आवश्यकता के अनुसार किस्म का चयन करना चाहिये।

- दाने के लिए लोबिया की उन्नत किस्मों में सी- 152, पूसा फाल्गुनी, अम्बा (वी- 16), स्वर्णा (वी- 38), जी सी- 3, पूसा सम्पदा (वी- 585) और श्रेष्ठा (वी- 37) आदि प्रमुख है।
- चारे के लिए लोबिया की उन्नत किस्मों में जी एफ सी- 1, जी एफ सी- 2 और जी एफ सी- 3 आदि अच्छी किस्में हैं।
- खरीफ और जायद दोनों मौसम में उगाये जाने वाले किस्मों में बंडल लोबिया- 1, यू पी सी- 287, यू पी सी- 5286 रशियन ग्रेन्ट, के- 395, आई जी एफ आर आई (कोहीनूर), सी- 8, यू पीसी- 5287, यू पी सी- 4200, यू पी सी- 628, यू पी सी- 628, यू पी सी- 621, यू पी सी- 622 और यू पी सी- 625 आदि हैं।
- लोबिया की बुवाई के लिए 12-20 कि.ग्रा. बीज/हेक्टेयर उपयुक्त होता है। जबकि बेलदार लोबिया की बीज कम मात्रा में ली जा सकती है।

लोबिया बुवाई के समय ध्यान रखना चाहिए कि इनके बीच की दूरी सही हो

- लोबिया की झाड़ीदार किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45-60 सेमी. तथा बीज से बीज की दूरी 10 सेमी. रखनी चाहिए।
- बेलदार लोबिया के पंक्ति से पंक्ति की दूरी 80-90 सेमी. रखना सही होता है।

लोबिया की तुड़ाई/कटाई कब करें ?

- लोबिया के हरी फलियों की तुडाई बुवाई के 45 से 90 दिन बाद किस्म के आधार पर करनी चाहिये।
- चारे के लिये फसल की कटाई बुवाई के 40 से 45 दिन बाद की जाती है।
- दाने की फसल के लिए कटाई, बुवाई फलियों के पुरे पक जाने पर 90 से 125 दिन बाद करनी चाहिए।
- लोबिया की नर्म व कच्ची फलियों की तुड़ाई 4-5 दिन के अंतराल पर की जा सकती है।

लोबिया की फसल से दाना व चारा की प्राप्ति

- लोबिया की एक हेक्टेयर की फसल से करीब 12 से 17 क्विंटल दाना व 50 से 60 क्विंटल भूसा प्राप्त किया जा सकता है।
- जबकि 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है।
- झाड़ीदार प्रजातियों में 3-4 तुड़ाई तथा बेलदार प्रजातियों में 8-10 तुड़ाई की जा सकती है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार परंपरागत धान की खेती से एक किलोग्राम चावल उपजाने में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में पैदा होने वाले धान की किस्म विकसित की है, जो किसानों के लिए बड़ा उपहार साबित हो सकती है। धान की इस किस्म का नाम है स्वर्ण शक्ति।

स्वर्ण शक्ति धान किस्म

पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र जमुई ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के विज्ञानियों के साथ मिलकर कई सालों के शोध व परिक्षण के बाद स्वर्ण शक्ति किस्म को विकसित किया है। इसे बाजार में उतारने की अनुमति फसल बीज अधिसूचना केंद्र उप समिति व राज्य बीज उप समिति ने दे दी है। खरीफ सीजन से ही किसान इसकी खेती कर सकते हैं। स्वर्ण शक्ति धान कम पानी में या असिंचित क्षेत्र में भी आसानी से उपजाई और अच्छी पैदावार पाई जा सकती है।

स्वर्ण शक्ति किस्म की मुख्य विशेषतायें

- स्वर्ण शक्ति किस्म की धान पर सूखे का असर नहीं होता है।
- स्वर्ण शक्ति किस्म की धान पौधे 15 दिन तक ओलावृष्टि को सहने में सक्षम है।
- यदि बारिश कम होती है तो भी किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
- पानी की खपत कम होगी जिससे खेती की लागत कम होगी।
- स्वर्ण शक्ति मध्यम अवधि की प्रजाति है जो 115-120 दिन में तैयार हो जाती है।
- स्वर्ण शक्ति प्रजाति से 45 से 50 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

भूमि की तैयारी कैसे करें

सबसे पहले खेत की एक गहरी जुताई करनी चाहिए, इससे खरपतवार, कीट और रोगों के प्रबंधन में सहायता मिलती है। धान की सीधी बुआई द्वारा खेती करने के लिए एक बार मोल्ड हल की सहायता से जुताई करके फिर डिस्क हैरो और रोटावेटर चलाने के बाद धान की सीधी बुआई द्वारा खेती करें। ऐसा करने से पूरे खेत में बीजों का एक समान अंकुरण, जड़ों का सही विकास, सिंचाई के जल का एक समान वितरण होने से पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा और अच्छी उपज हासिल होगी।

बुवाई का समय

बुआई का सबसे अच्छा समय जून के दूसरे सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह तक होता है। लेकिन किसान भाई जुलाई माह में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं।

स्वर्ण शक्ति किस्म की बुआई का तरीका

स्वर्ण शक्ति धान की सीधी बुआई हाथ से अथवा बीज-सह-उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा की जा सकती है। करीब 25-30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की बीज दर के साथ 3-5 से.मी. गहरी हल-रेखाओं में 20 से.मी. की दूरी पर पंक्तियों में बुवाई की जाती है।

खाद व उर्वरक की मात्रा

धान के पौधों के उचित विकास के लिए प्रति हैक्टेयर 120 किलोग्राम नाईट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए भूमि की अंतिम तैयारी के समय फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी खुराक और नाईट्रोजन उर्वरक की केवल एक तिहाई मात्रा को खेत में मिला देना चाहिए। बाकि नाईट्रोजन को दो बराबर भागों में बांटकर, एक भाग को बुआई के 40-50 दिनों बाद कल्ले (टिलर) आने के समय तथा दूसरे भाग को बुआई के 55-60 दिनों बाद बाली आने के समय देना चाहिए।

सिंचाई कब कब करें

बिना कीचड़ और बिना जल जमाव किये स्वर्ण शक्ति धान की खेती सीधी बुआई करके की जाती है। स्वर्ण शक्ति सूखा सहिष्णु एरोबिक प्रजाति है, यदि फसल के दौरान सामान्य वर्षा हो और सही रूप से खेत में वितरित हो तो फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सूखे की स्थिति में फसल को विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं जैसे बुआई के बाद, कल्ले निकलते समय, गाभा फूटते समय, फूल लगते समय एवं दाना बनते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी होता है।

कैसे करें खरपतवार नियंत्रण

धान की सीधी बुआई करने पर खेतों में मोथा, दूब, जंगली घास, सावां, सामी आदि खरपतवार का प्रकोप काफी बढ़ जाता है, जिससे फसल को नुकसान होता हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुवाई के एक या दो दिनों के अंदर ही पेंडीमेथलीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व / हैक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद बिस्पैरिबक सोडियम का 25 ग्राम सक्रिय तत्व/ हैक्टेयर की दर से बुआई के 18-20 दिनों के अंदर छिड़काव करना चाहिए। आवश्यक हो तो बुआई के 40 दिनों बाद और 60 दिनों बाद निराई की जा सकती है।

बाजरा भारत की सबसे ज्यादा उत्पादन वाली फसल है। इसीलिए भारत देश में बाजरे को अग्रणी फसलों की श्रेणी में रखा जाता है।भारत देश में करीब 85 लाख से अधिक क्षेत्रों में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरे का उत्पादन करने वाले राज्य कुछ इस प्रकार है जहां बाजरे की खेती की जाती है। जैसे, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में भारी मात्रा में बाजरे का उत्पादन होता है।

बाजरा में मौजूद पोषक तत्व

बाजरे में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं इसीलिए इसे आहार का मुख्य साधन माना जाता है। किसानों के अनुसार भारत देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस फसल को प्रमुख खाद्य भी कहा जाता है।

बाजरा ना सिर्फ मनुष्य अपितु पशुओं के भी पौष्टिक चारे का माध्यम है। बाजरे की खेती किसान पशुओं को चारा देने के लिए भी करते हैं। बाजरा के दानों में प्रोटीन की मात्रा 10.5 से लेकर 14. 5% तक मौजूद होती है। पोषक तत्व की दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही उपयोगी है। बाजरा में लगभग वसा 4 से 8 % होता है वहीं दूसरी ओर कार्बोहाइड्रेट खनिज तत्व कैल्शियम केरोटिन राइबोफ्लेविन, विटामिन बी तथा नायसिन और विटामिन B6 भी भरपूर मात्रा में बाजरे में मौजूद होते हैं।गेंहू और चावल के मुकाबले बाजरे में अधिक मात्रा में लौह तत्व मौजूद होते हैं। बाजरे में

भरपूर मात्रा में ऊर्जा मौजूद होती है इसी कारण इसका सेवन सर्दियों में ज़्यादा करते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम फास्फोरस, और खनिज लवण,
हाइड्रोरासायनिक अम्ल, बाजरे में उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है।

पूसा संस्थान की पूसा कम्पोजिट 612, पूसा कंपोजिट्स 443, पूसा कम्पोजिट 383, पूसा संकर 415, एचएचबी 67, आर एस बी 121, MH169 जैसी अनेक क्षेत्रीय किसमें देश में मौजूद हैं।

बाजरे की फसल के लिए भूमि का चयन

बाजरे की फसल के लिए किसान सभी प्रकार की भूमि को उपयुक्त बताते हैं, परंतु बलुई दोमट मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है।

बाजरे की फसल के लिए जल निकास की व्यवस्था को उचित बनाए रखना आवश्यक होता है। बाजरे की फसल के लिए अधिक उपजाऊ भूमि की कोई जरूरत नहीं पड़ती हैं। क्योंकि भारी भूमि कम अनुकूलित होती है।

बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु

बाजरे की खेती के लिए गर्म जलवायु सबसे उपयोगी होती है।बाजरे की खेती 400 से 600 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 32 से 37 सेल्सियस बेहतर माना जाता है। बाजरे की फसल का उत्पादन करने के लिए। कभी-कभी ऐसा होता है जब बाजरे पुष्पन अवस्था में हो और बारिश हो जाएगा। यह आप पानी के फव्वारों के जरिए सिंचाई कर दे। तो बाजारों के दाने धुल जाते हैं और बाजरे का उत्पादन नहीं हो पाता है।

बाजरे की फ़सल के लिए (फसल चक्र की व्यवस्था)

बाजरे की फसल के लिए, फसल चक्र की व्यवस्था बनाना बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से मिट्टियों की उर्वरता बनी रहती है। यह फसल चक्र आपको एकवर्षीय बनाने की आवश्यकता होती है। या फसल चक्र कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं जैसे: गेहूं और जौ, बाजरा सरसों और तारामीरा, या फिर बाजरा चना, मटर या मसूर, बाजरा गेहूं, सरसों, ज्वार, मक्का चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथा बाजरा, सरसों ग्रीष्मकालीन, मूंग आदि फसल चक्र बनाए जाते हैं।

बाजरे की फसल के लिए खेत को तैयार करें

बाजरे की फसल को बोते समय खेत को भली प्रकार से तैयार करने की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में खेतों को गहरी अच्छी जुताई की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उत्तम जल निकास की व्यवस्था खेतों में बनाना आवश्यक होता है। खेत जोतने के बाद, खेतों को अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए। बाजरे की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल द्वारा मिट्टी को अच्छी तरह से पलटे, दो से तीन बार जताई करें फिर उसके बाद बीज रोपण करें। बाजरे की फसल को सुरक्षित रखने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के प्रकोप जैसे, दीमक और लट से बचाने के लिए आख़िरी जुताई के दौरान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से फोरेट का इस्तेमाल कर खेतों में डाले। बाजरे की खेती के लिए शून्य जुताई विधि किसान उत्तम बताते हैं। इसके लिए आपको खेत समतल करना होता है मिट्टी को फसल के लिए अवशेषों तथा वानस्पतिक अवशेषों का आवरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। किसान इस प्रक्रिया को खेत के लिए सबसे लाभप्रद बताते हैं।

बाजरे की फसल के लिए खरपतवार प्रबंधन करना

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बाजरे की फसल के लिए खरपतवार प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आपको लगभग 1 किलोग्राम एट्राजीन या पेंडिमिथालिन 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव की आवश्यकता होती है।

छिड़काव की यह प्रक्रिया बुवाई के बाद या फिर अंकुरण आने से पहले करते हैं। बाजरे की फसल बुवाई के बाद लगभग 25 से 30 दिनों के बाद खुरपी या कसौला की सहायता से खरपतवार को निकालना उपयोगी होता है।

बाजरे की फ़सल के लिए (फसल चक्र की व्यवस्था)

- बाजरे की फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए आपको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस की जरूरत पड़ती है। क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल आप को जड़ों में और जब थोड़ी हल्की बारिश हो तब मिट्टियों में मिलाकर अच्छी तरह से बिखेर देना चाहिए।
- तना मक्खी, जैसी समस्याओं और गिडारें और इल्लियां की शुरुआती अवस्था में पौधों की बढ़वार को काटकर अलग कर देना। इस अवस्था में पौधे सूख जाते हैं इस प्रकोप की रोकथाम करने के लिए आपको लगभग 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फॉरेट 25 किलोग्राम, फ्यूराडोन, 3%और मैलाथियान, 5% 25 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से खेतों में डालना उपयोगी होता है।
- सफेद लट बाजरे की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपको फ्यूराडॉन 3% फॉरेट 10% दानों को करीब 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे की बुवाई करते टाइम मिट्टियों में मिलाना आवश्यक होता है।

आहार की दृष्टिकोण से देखे तो अरहर की दाल बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं जैसे: खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अरहर की दाल को रोगियों को खिलाना लाभदायक होता है। लेकिन जिन लोगों में गैस कब्ज और सांस जैसी समस्या हो उनको अरहर दाल का सेवन थोड़ा कम करना होगा। अरहर की दाल शाकाहारी भोजन करने वालो का मुख्य साधन माना जाता है शाकाहारी अरहर दाल का सेवन बहुत ही चाव से करते हैं।

अरहर दाल की फसल के लिए भूमि का चयन

अरहर की फ़सल के लिए सबसे अच्छी भूमि हल्की दोमट मिट्टी और हल्की प्रचुर स्फुर वाली भूमि सबसे उपयोगी होती है। यह दोनों भूमि अरहर दाल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। बीज रोपण करने से पहले खेत को अच्छी तरह से दो से तीन बार हल द्वारा जुताई करने के बाद, हैरो चलाकर खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लेना चाहिए। अरहर की फ़सल को खरपतवार से सुरक्षित रखने के लिए जल निकास की व्यवस्था को बनाए रखना उचित होता है। तथा पाटा चलाकर खेतों को अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए। अरहर की फसल के लिए काली भूमि जिसका पी.एच .मान करीब 7.0 – 8. 5 सबसे उत्तम माना जाता है।

अरहर दाल की प्रमुख किस्में

अरहर दाल की विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई जाती है जो निम्न प्रकार है:

- 2006 के करीब, पूसा 2001 किस्म का विकास हुआ था। या एक खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है। इसकी बुवाई में करीब140 से लेकर 145 दिनों का समय लगता है। प्रति एकड़ जमीन में या 8 क्विंटल फ़सल की प्राप्ति होती है।
- साल 2009 में पूसा 9 किस्म का विकास हुआ था। इस फसल की बुवाई खरीफ रबी दोनों मौसम में की जाती है। या फसल देर से पकती है 240 दिनों का लंबा समय लेती है। प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 क्विंटल फसल का उत्पादन होता है।
- साल 2005 में पूसा 992 का विकास हुआ था। यह दिखने में भूरा मोटा गोल चमकने वाली दाल की किस्म है।140 से लेकर 145 दिनों तक पक जाती है प्रति एकड़ भूमि 6.6 क्विंटल फसल की प्राप्ति होती है। अरहर दाल की इस किस्म की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश दिल्ली तथा राजस्थान में होती है।
- नरेंद्र अरहर 2, दाल की इस किस्म की बुवाई जुलाई मे की जाती हैं। पकने में 240 से 250 दिनों का टाइम लेती है। इस फसल की खेती प्रति एकड़ खेत में 12 से 13 कुंटल होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश में इस फसल की खेती की जाती।
- बहार प्रति एकड़ भूमि में10 से 12 क्विंटल फसलों का उत्पादन होता है। या किस्म पकने में लगभग 250 से 260 दिन का समय लेती है।
- दाल की और भी किस्म है जैसे, शरद बी आर 265, नरेन्द्र अरहर 1और मालवीय अरहर 13,

आई सी पी एल 88039, आजाद आहार, अमर, पूसा 991 आदि दालों की खेती की प्रमुख है।

अरहर दाल की फ़सल बुआई का समय

अरहर दाल की फसल की बुवाई अलग-अलग तरह से की जाती है। जो प्रजातियां जल्दी पकती है उनकी बुवाई जून के पहले पखवाड़े में की जाती है विधि द्वारा। दाल की जो फसलें पकने में ज्यादा टाइम लगाती है। उनकी बुवाई जून के दूसरे पखवाड़े में करना आवश्यक होता है। दाल की फसल की बुवाई की प्रतिक्रिया सीडडिरल यह फिर हल के पीछे चोंगा को बांधकर पंक्तियों द्वारा की जाती है।

अरहर दाल की फसल के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार

जल्दी पकने वाली जातियों की लगभग 20 से 25 किलोग्राम और धीमे पकने वाली जातियों की 15 से 20 किलोग्राम बीज /हेक्टर बोना चाहिए। जो फसल चैफली पद्धति से बोई जाती हैं उनमें बीजों की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है। फसल बोने से पहले करीब फफूदनाशक दवा का इस्तेमाल 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम कार्बेन्डेजिम यह फिर वीटावेक्स का इस्तेमाल करे, लगभग 5 ग्राम ट्रयकोडरमा प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। उपचारित किए हुए बीजों को रायजोबियम कल्चर मे करीब 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद खेतों में लगाएं।

अरहर की फसल की निंदाई-गुडाई

अरहर की फसल को खरपतवार से सुरक्षित रखने के लिए पहली निंदाई लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर दे, फूल आने के बाद दूसरी निंदाई शुरू कर दें। खेतों में दो से तीन बार कोल्पा चलाने से अच्छी तरह से निंदाई की प्रक्रिया होती है। तथा भूमि में अच्छी तरह से वायु संचार बना रहता है। फसल बोने के नींदानाषक पेन्डीमेथीलिन 1.25 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व / हेक्टर का इस्तेमाल करे। नींदानाषक का इस्तेमाल करने के बाद नींदाई करीब 30 से 40 दिन के बाद करना आवश्यक होता है।

अरहर दाल की फसल की सिंचाई

किसानों के अनुसार यदि सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है, तो वहां एक सिंचाई फूल आने से पहले करनी चाहिए। तथा दूसरे सिंचाई की प्रक्रिया खेतों में फलिया की अवस्था बन जाने के बाद करनी चाहिए। इन सिंचाई द्वारा खेतों में फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है।

अरहर की फसल की सुरक्षा के तरीके

कीटो से फसलों की सुरक्षा करने के लिए क्यूनाल फास या इन्डोसल्फान 35 ई0सी0, 20 एम0 एल का इस्तेमाल करें। फ़सल की सुरक्षा के लिए आप क्यूनालफास, मोनोक्रोटोफास आदि को पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को अपनाने से खेत कीटो से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।

देश में इस साल मानसून की असामान्य गतिविधि देखी जा रही है। कहीं पानी तो कहीं गर्मी सूखे के कारण, कृषक तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो फसल कब और कौन सी बोएं। आम तौर पर मानसून आधारित औसतन कम पानी की जरूरत वाली खरीफ की फसलों में शामिल, सोयाबीन की किस्मों पर किसान यकीन करते हैं।

असामान्य स्थिति

बारिश जनित असमान्य स्थितियों के कारण इस साल सोयाबीन खेती आधारित पैदावार क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा के आगमन एवं फैलाव में स्थितियां पिछले सालों की तुलना में अलग हैं।

कुछ जगहों के कृषक मित्र सोयाबीन की खेती शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ इलाकों के किसान सोयाबीन की बुआई के लिए अभी भी पर्याप्त वर्षा जल का इंतजार कर रहे हैं। मतलब इन इलाकों की सोयाबीन बुआई फिलहाल अभी रुकी हुई है।

मानसून में हो रही देरी के कारण कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के बीजों के चयन, उनको बोने एवं आवश्यक ध्यान रखने के बारे में कुछ सलाह जारी की हैं।

बुआई के लिए

मानसून की देरी से परेशान ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक सोयाबीन की बुवाई नहीं की है, या फिर अभी 3 से 4 दिन पहले ही सोयाबीन बोया है तो उनके लिए यह सलाह काफी अहम है।

आम तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक का समय सोयाबीन बोवनी के लिए उपयुक्त होता है। इसमें देरी होने पर कृषक ख्याल रखें कि बोवनी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा (100 मि.मी.) होने पर ही सोयाबीन कि बुवाई का वे जोखिम उठाएं।

सोयाबीन की किस्म

इस बारे में कृषकों को सलाह दी गई है कि, वे एक ही किस्म की सोयाबीन बोवनी की बजाए खेत में विभिन्न समयावधि में पकने वाली किस्मों की बोवनी करें। इसमें 2 से 3 अनुशंसित किस्मों की सोयाबीन खेती को प्राथमिकता दी जा सकती है।

बीज दर का गणित

बीज ऐसा चुनें जिसकी गुणवत्ता न्यूनतम 70% अंकुरण की हो। इस आधार पर ही बोए जाने वाले बीज दर का भी प्रयोग करें। अंकुरण परीक्षण से सोयाबीन बोवनी हेतु उपलब्ध बीज का अंकुरण न्यूनतम 70 फीसदी सुनिश्चित करने से भी कृषक अपने बीज का परीक्षण कर सकते हैं।

पद्धति का चुनाव

सोयाबीन के लिए विपरीत माने जाने वाली सूखे कि स्थिति, अतिवृष्टि आदि से संभाव्य नुकसान कम करने सोयाबीन की बोवनी बी.बी.एफ. पद्धति या रिज एवं फरो विधि (RIDGE AND FURROW) से करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने दी है।

सोयाबीन बीज उपचार

बोवनी के समय बीज को अनुशंसित तरीके से उपचारित कर थोड़ी देर छाया में सुखाएं | फिर इसके बाद अनुशंसित कीटनाशक से भी उपचारित करें |

कृषक रासायनिक फफूंद नाशक के स्थान पर बीजों में जैविक फफूंद नाशक ट्रायकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते है। इसे जैविक कल्चर के साथ मिलकर प्रयोग किया जा सकता है।

खाद का संतुलन

किसान सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर की पूर्ति केवल बोवनी के वक्त करें।

बोवनी वक्त दूरी

सोयाबीन की बोनी के लिए 45 से.मी. कतारों की दूरी अनुपालन की अनुशंसा की जाती है। बीज को 2 से 3 से.मी. की गहराई पर बोते हुए पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेमी रखने की सलाह कृषि वैज्ञानिक देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि, सोयाबीन बीज दर 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से बेहतर पैदावार होगी।

जी हां बात बिलकुल सही है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) के भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (ICAR-VIVEKANANDA PARVATIYA KRISHI ANUSANDHAN SANSTHAN, ALMORA) ने यह उपलब्धि हासिल की है।

संस्थान ने बायो-फोर्टिफाईड मक्का (MAIZE) की नई किस्में जारी की हैं, जो पोषक तत्वों से

अंतर के कारण

मक्का की चलन में उगाई जाने वाली दूसरी किस्मों में अमीनो अम्ल (AMINO ACID) मुख्य तौर पर प्रोटीन (पोषक तत्व) जैसे ट्रिप्टोफैन व लाइसीन की कमी होती है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक एवं सहायक चयन विधि के माध्यम से इस कमी को पूरा किया है।

ग्लास फुल दूध जितना हेल्दी !

संस्थान ने गुणवत्ता युक्त प्रोटीन से लैस मक्का की इन खास किस्मों में विशिष्ट अमीनो अम्ल की मात्रा में सुधार किया है। इन विकसित किस्मों में इसकी मात्रा सामान्य मक्का से 30-40 फीसदी तक ज्यादा है। मतलब उन्नत प्रजाति के मक्के में पोषण की मात्रा लगभग स्वस्थ जीव के दूध के बराबर है!

क्यूपीएम प्रजाति (QPM – QUALITY PROTEIN MAIZE)

विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने मक्के के जिन खास किस्मों को विकसित किया है, उनको समितियों का भी अनुमोदन मिला है। संस्थान में विकसित की गई एक क्यूपीएम प्रजाति को केंद्रीय प्रजाति विमोचन समिति ने उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों, जबकि दो क्यूपीएम प्रजातियों को राज्य बीज विमोचन समिति ने जारी किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की जैविक दशाओं को ध्यान में रखकर अप्रैल '2022 में इन्हें जारी किया गया था।

मक्का कार्यशाला के परिणाम

कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रजातियों में शामिल, वीएल क्यूपीएम हाइब्रिड 45 मक्का प्रजाति (VL QPM HYBRID 45 MAKKA) की पहचान अप्रैल 2022 में हुई थी। दी गई जानकारी के अनुसार, 65 वीं वार्षिक मक्का कार्यशाला में इन्हें तैयार किया गया।

इन प्रदेशों की जलवायु का ध्यान

उत्तर पश्चिमी पर्वतीय अंचल (जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड) एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र खास तौर पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा की जलवायु के हिसाब से इनको तैयार किया गया था।

बीमारियों से लड़ने में कारगर

संस्थान की इस प्रजाति में टर्सिकम व मेडिस पर्ण झुलसा तरह की बीमारियों के लिए मध्यम प्रतिरोधकता भी है।

अगेती की प्रकृति वाली प्रजाति

वीएल क्यूपीएम हाइब्रिड 61 (VL QPM HYBRID 61) अगेती यानी जल्द मुनाफा देने वाली प्रजाति है, जो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है।

परीक्षणों के परिणाम

जांच परीक्षणों की बात करें तो राज्य-स्तरीय समन्वित परीक्षणों में इसके बेहतर परिणाम मिले हैं। जांच में इसकी औसत उपज लगभग साढ़े चार हजार किलोग्राम है, जिसमें ट्रिप्टोफैन, लाइसीन व प्रोटीन की मात्रा क्रमश: 0.76, 3.30 व 9.16 प्रतिशत है। तो किसान भाई, आप भी हो जाएं तैयार, दुग्ध जितने पोषण से लैस, कम लागत वाली मक्के की इन फसलों से हेल्दी मुनाफा कमाने के लिए !

सब्ज़ी

मात्र 70 दिन में उगे यह रंग-बिरंगी उन्नत शिमला मिर्च

किसान वर्ग के लिए बात है, न तीखी न फीकी, ऐसी चीज की, जिसका रंग ऐसा की व्यंजन को रंगदार बना दे। जी हां, बात है, लाल-पीली-हरी रंग-बिरंगी शिमला मिर्च (CAPSICUM) की, जिसके जायके का तड़का भारतीय रसोई से लेकर दुनिया भर की तमाम रेसिपी में शुमार है।

कैप्सिकम वैराइटी (CAPSICUM VARIETY), यानी शिमला मिर्च की शीर्ष किस्मों में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं, जो महज ढ़ाई माह के भीतर ही किसान को मुनाफा दे सकती हैं। मतलब 78 से 80 दिन में किसान रंग-बिरंगी शिमला मिर्च को बेचकर हरे नोट गिन सकता है।

भारत में कैप्सिकम पैदावार की संभावनाएं

भारत के अधिकतर उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ही कर्नाटक के आसपास के प्रदेशों में कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च की पैदावार का प्रचलन ज्यादा है।

कम समय और अच्छा बाजार

फास्ट-फूड कल्चर (FAST FOOD CULTURE) जैसे चाइनीज व्यंजनों के साथ ही देसी तड़के में उपयोग की जाने वाली शिमला मिर्च की भारत समेत विदेशी बाजारों में खासी मांग है। ऐसे में महज 2 से 3 महीने में आय का विकल्प, शिमला मिर्च की खेती कृषक मित्रों के लिए अच्छी आय का जरिया बन सकती है।

शिमला मिर्च की प्रमुख किस्में और पैदावार की जानकारी

भारत में शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों (VARIETY OF CAPSICUM IN INDIA) की बात करें तो इसमे इंद्रा, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर आदि किस्म की शिमला मिर्चों के नाम शामिल हैं। इन मिर्चों की खासियत क्या है और इन्हें कैसे उगाया जाता है जानते हैं गूढ़ राज को।

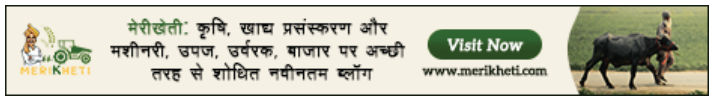

इंद्रा शिमला मिर्च

इंद्रा शिमला मिर्च मध्यम लंबी और तेजी से पनपने वाले झाड़ीदार पौधों में से एक किस्म की प्रजाति है।पहचान की बात करें तो इसके गहरे हरे पत्ते मिर्च के फल को आधार प्रदान करते हैं। इस प्रजाति की शिमला मिर्च गहरी हरी, मोटे आवरण के साथ ही चमकदार होती हैं।

खरीफ सीजन में इंद्रा शिमला मिर्च की अच्छी पैदावार हीती है। मूल तौर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात के साथ ही राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं कलकत्ता, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, पंजाब इंद्रा शिमला मिर्च (INDRA CAPSICUM) का तगड़ा पैदावार क्षेत्र है।

बोवनी की बात करें तो बुवाई के महज 70 से 80 दिनों के भीतर इंद्रा शिमला मिर्च की प्रजाति परिपक्व हो जाती है, जिसे तोड़कर किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं।

भारत शिमला मिर्च

भारत शिमला मिर्च की प्रजाति के पौधे तेजी से पनपते हैं। यह गहरे हरे रंग के होते हैं। भारत शिमला मिर्च की प्रजाति की पैदावार के लिए सूखी एवं लाल दोमट मिट्टी अनिवार्य है।

जून से दिसम्बर यानी सात महीनों तक का मौसम इसकी पैदावार के लिए अनुकूल माना गया है। इसे बोने के लगभग 90 से 100 दिनों यानी तीन माह से कुछ अधिक दिनों के बाद भारत शिमला मिर्च की तुड़ाई किसान कर सकते हैं।

कैलिफोर्निया वंडर शिमला मिर्च

कैलिफोर्निया वंडर शिमला मिर्च (CALIFORNIA WONDER CAPSICUM) भारत में पैदावार की जाने वाली उन्नत किस्मों में से एक है। कैलिफोर्निया वंडर शिमला मिर्च का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। हरे रंग के फल इसकी पहचान हैं।

इसे बोने के करीब 75 दिनों उपरांत इसके पौधों से मिर्च के फल तोड़े जा सकते हैं। प्रति एकड़ जमीन के मान से तकरीबन 72 से 80 क्विंटल शिमला मिर्च पैदा होने की संभावना है।

येलो वंडर शिमला मिर्च

चटख पीले रंग की येलो वंडर शिमला मिर्च (YELLOW WONDER CAPSICUM) के पौधों की बात करें तो चौड़े पत्तों वाले इन प्लांट्स की ऊंचाई मध्यम आकर की होती है।

बीजारोपण के करीब 70 दिनों उपरांत येलो वंडर शिमला मिर्च (YELLOW WONDER CAPSICUM) की पैदावार तैयार हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों में प्रति एकड़ भूमि पर लगभग 48 से 56 क्विंटल येलो वंडर शिमला मिर्च (YELLOW WONDER CAPSICUM) की पैदावार संभव है।

पूसा दीप्ती शिमला मिर्च

पूसा दीप्ती शिमला मिर्च (PUSA DEEPTI CAPSICUM) हाइब्रिड प्रजाति की शिमला मिर्च है। इसका पौधा भी मध्यम आकार का झाड़ीनुमा होता है।

पूसा दीप्ति कैप्सिकम (PUSA DEEPTI CAPSICUM) के फलों का रंग शुरुआत में हल्का हरा होता है, जो फल के पकने के उपरांत गहरे लाल रंग में तब्दील हो जाता है। बीजारोपण के महज ढ़ाई माह, यानी कि मात्र 70 से 75 दिनों के उपरांत इसके फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं।

बारिश में लगाएंगे यह सब्जियां तो होगा तगड़ा उत्पादन मिलेगा दमदार मुनाफा

बारिश के मौसम में खेतों में जहां पानी की समस्या नहीं रहती, वहीं ज्यादा बारिश की स्थिति में पैदावार के नष्ट होने का भी खतरा मंडराने लगता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बारिश के मौसम में कम समय, अल्प लागत में पनपने वाली ऐसी सब्जियों की जिनसे किसान वर्ग दमदार उत्पादन के साथ तगड़ा मुनाफा कमा सकता है। आम जन भी इससे अपने घरेलू खर्च में बचत कर सकते हैं।

देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ ही वेजिटेबल फार्मिंग (VEGETABLE FARMING) यानी सब्जियों की पैदावार का भी बढ़िया वक्त आ चुका है।

मानसून का मौसम खरीफ की किसानी के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो बारिश के पानी की मदद से तेजी से वृद्धि करती हैं। सिंचाई की लागत कम होने से ऐसे में किसान के लिए मुनाफे के अवसर बढ़ जाते हैं। तो फिर जानें कौन सी हैं वो सब्जियां और उन्हें किस तरह से उगाकर किसान लाभ हासिल कर सकते हैं।

ककड़ी (खीरा) और मूली

किसानों के लिए सलाद के साथ ही तरकारी में उपयोग की जाने वाली ककड़ी (खीरा) और मूली बारिश में कमाई का तगड़ा जरिया हो सकती है। इन दोनों के पनपने के लिए बारिश का मौसम एक आदर्श स्थिति है।

इतना ही नहीं इसकी पैदावार के लिए किसान को ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि छोटी सी जगह पर किसान मात्र 21 से 28 दिनों के भीतर बेहतर कमाई कर सकते हैं।

ककड़ी (खीरा) और मूली

जी हां हरी-भरी बीन्स जैसे कि सेम, बरबटी लगाकर भी किसान कम समय में अच्छे उत्पादन के साथ बढ़िया आमदनी कर सकते हैं।फलीदार सब्जियों के पनपने के लिए जुलाई और अगस्त का महीना सबसे अनुकूल माना गया है। बेलदार पौधे होने के कारण इन्हें लगाने के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं होती।

पेड़ या दीवार के सहारे फलीदार सब्जियों की पैदावार कर किसान रुपयों की बेल भी पनपा सकते हैं। मानसूनी जलवायु फलीदार पौधों के विकास के लिए आदर्श स्थिति भी है।

कड़वा नहीं कमाऊ है करेला

कड़वाहट की बात आए तो भारत में यह जरूर कहते हैं कि, करेला वो भी नीम चढ़ा, लेकिन किसान के लिए कमाई के दृष्टिकोण से करेला मिठास घोल सकता है।

दरअसल करेला कड़वा जरूर है, लेकिन यह कई तरीकों से औषधीय गुणों से भी भरपूर है। करेला मनुष्य को कई तरह की बीमारियों से बचाव करने में भी सहायक है।

विविध व्यंजनों एवं औषधीय रूप से महत्वपूर्ण करेले की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। तो किसान बारिश के कालखंड में बेलदार करेले की पैदावार कर अल्प अवधि में बड़ा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं।

हरी मिर्च की खनक और धनिया की महक

कहते हैं न साग-तरकारी का स्वाद हरी मिर्च और धनिया की रंगत के बगैर अधूरा है। खास तौर पर बारिश के मौसम में बाजार में हरी मिर्च और धनिया की मांग और दाम उफान पर रहते हैं।

किसान के खेत की मिट्टी बलुआ दोमट या लाल हो तो यह फिर सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी। ये दोनों ही मिट्टी इनकी पैदावार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। बारिश के मौसम किसान खेत में, जबकि इसके स्वाद के दीवाने लोग अपने किचन या फिर छत एवं बाग-बगीचे में मिर्च और धनिया को उगा सकते हैं। किचन में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की जालीदार टोकनियों में भी पानी की मदद से हरा-भरा धनिया तैयार किया जा सकता है।

भटा, टमाटर की पैदावार

वैसे तो बैंगन यानी की भटा और टमाटर की पैदावार साल भर की जा सकती है। लेकिन बारिश का मौसम इन दोनों सब्जियों की पैदावार के लिए बहुत अनुकूल माना गया है।

सर्दी में भी इनकी खेती की जा सकती है। तो क्या तैयार हैं आप अपने खेत, छत या फिर बगीचे में ककड़ी, मूली, फलीदार सब्जियों, धनिया-मिर्च और भटा-टमाटर जैसी किफायती सब्जियों को उगाने के लिए।

पंचसितारा का हो प्लेट या घर की थाली, हर जगह मिलेगी टमाटर की लाली. टमाटर सब्जी या अन्य व्यंजनों में स्वाद का खट्टा मीठा तड़का ही नहीं, फ्लेवर भी देता है. टमाटर को स्वास्थ्य के लिये भी जाना जाता है.

अगर किसान टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह किसानों के लिए सबसे बढ़िया फसल हो सकती है। टमाटर की खेती से किसान बहुत लाभ कमा सकते हैं. टमाटर की खेती कैसे और कब करें इसके बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जबकि टमाटर की खेती कर किसान लाखों कमा सकते हैं।

टमाटर की उन्नत किस्में

किसी भी फसल की अच्छी पैदावार और अच्छी कमाई अच्छे बीज पर निर्भर करती है. टमाटर की खेती के लिये भी उन्नत बीज का चुनाव करना होगा. टमाटर की उन्नत किस्में निम्नलिखित हैं:

अर्का रक्षक

भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले बीज में सबसे अच्छा अर्का रक्षक है। इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है. इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होता है. अर्का रक्षक की बेहतर क्वालिटी के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत रहती है. अर्का रक्षक किसानों का सबसे पसंदीदा बीज माना जाता है.

पूसा शीतल

टमाटर की अच्छी पैदावार के लिये पूसा शीतल किस्म को माना जाता है. यह देशी किस्म का बीज है.

पूसा सदाबहार

पूसा सदाबहार की फसल की पैदावार लगभग 300 क्विंटल से लेकर 450 क्विंटल तक होती है।

अर्का विकास

देशी बीजों में अच्छे उत्पादन के लिये अर्का विकास बीज माना जाता है.

पूसा हाइब्रिड-1

टमाटर की पूसा हाइब्रिड किस्म के बीजों का बहुत सारे किसानो द्वारा फसल लगाया जाता है. यह भी एक उत्तम पैदावार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बीज है.

रश्मि

टमाटर के हाईब्रिड बीजों में रश्मि बीज का नाम भी शामिल है.

टमाटर की खेती का सही समय

मार्च से जुलाई के समय टमाटर काफी जल्दी बड़े होते हैं. उपयुक्त समय पर टमाटर की फसल लगाने से अच्छी पैदावार मिलती है. इसलिए आपको हम टमाटर की खेती करने के सही समय से जुड़ी जानकारी दे देते है.

टमाटर की खेती उत्तरी मैदानी भाग में शरद और वसंत ऋतु में की जाती है.

जबकि दक्षिणी भारत में टमाटर की खेती का सही समय जून – जुलाई, अक्टूबर – नवंबर और जनवरी – फरवरी होता है.

पंजाब के किसानों के लिये बसंत से ग्रीष्म ऋतु का मौसम टमाटर की खेती के लिए सही समय है.

उत्तम जलवायु टमाटर की खेती के लिये बहुत जरूरी है. हालाँकि टमाटर की खेती गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में की जाती है। टमाटर की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच होना सबसे उपयुक्त माना जाता है.

टमाटर की खेती के लिए भूमि कैसे तैयार करें

टमाटर की खेती के लिए भूमि को अच्छे से खेती के लिए तैयार करना जरूरी होता है. भूमि के अंदर तोता हल की मदद से अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिये और पाटा की मदद से जमीन को समतल कर क्यारियां बना देनी चाहिये. इस भूमि पर हल्का हल्का पानी लगा देना है और उस जमीन की कल्टीवेटर हल से जोत देना चाहिये. फिर से पाटा लगाकर जमीन को अच्छे तरीके से समतल कर देनी चाहिये जिससे मिट्टी समतल और भूरभूरी हो जाएगी. इसके बाद जमीन टमाटर के पोधों की रोपाई के लिए तैयार है.

बीज की मात्रा

टमाटर की खेती के लिये बीज न ही कम मात्रा में डालना है और न ही ज्यादा मात्रा में. अगर आप हाईब्रीड क़िस्मों के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज एक हेक्टेयर में डाल सकते हैं. वहीं अन्य क़िस्मों के बीज की बात की जाए तो आप एक हेक्टेयर में 350 से 400 ग्राम बीज एक हेक्टेयर में इस्तेमाल करें

चिलचिलाती धूप और उमस भरी तेज गर्मी से आम जनमानस परेशान हैं। गर्मी से जीव-जन्तु भी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे में अगर अत्यधिक गर्मी के कारण आपके आलू या प्याज खराब हो रहे हैं, तो आप इन आसान तरीकों को अपनाएं और अपने आलू व प्याज को गलन व सड़न से बचाएं।

प्रति वर्ष खराब होता है 12%आलू और 10% प्याज

जानकारों की मानें तो कोल्ड स्टोरेज में रखने के बावजूद भी प्रतिवर्ष, 12 फीसदी आलू और 10 फीसदी प्याज गलने व सड़ने से खराब हो जाती है। आलू व प्याज के भाव में गिरावट होने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, जिससे सीधे तौर पर किसानों का नुकसान होता है।

अत्यधिक गर्मी में अपनाएं ये तरीके आज, बचा लें अपने आलू और प्याज

■आलू और प्याज को एक साथ स्टोर न करें

आलू और प्याज में अलग-अलग तरह की गंध होती है। हल्की सी तापमान में भी दोनों एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कभी भी आलू और प्याज को एक साथ स्टोर नहीं करना चाहिए।

■भीगे हुए आलू और प्याज की सफाई

आलू हो या प्याज, अगर आपने भीगे हुए आलू-प्याज को स्टोर में रख दिया, तो इनमें बहुत ही जल्दी गलन शुरू हो जाएगी, जो काफी नुकसानदायक है। भीगे हुए आलू और प्याज को अच्छे सूती कपड़े से साफ करें, फिर सूखा के स्टोर करें।

■आलू और प्याज को हवादार जगह रखें

प्याज को जालीदार बाँस की खुली टोकरी या ऐसी जगह रखें जो हवादार हो, तो इनमें फफूंदी लगने की सम्भावना कम हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से बचें, क्यूंकि वेंटिलेशन के अभाव में प्याज़ जल्दी खराब हो सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार इनके बीच वेंटिलेशन रखनी चाहिए।

■कागज में रखना ज्यादा कारगर

आलू और प्याज को कागज के लिफाफे में रखकर स्टोर करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों ही सब्जियां अधिक समय तक खराब नहीं होतीं हैं। अंधेरा और ठंडी जगह इनके लिए सबसे उत्तम

हरियाणा राज्य सरकार ने बांस और जालियों के सहारे सब्जियां उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत देने का एलान किया है। बांस और जालियों के सहारे सब्जियों की खेती करने पर राज्य सरकार 90% सब्सिडी देगी। इस नई तकनीकी का इस्तेमाल करने पर सरकार ने किसानों को आर्थिक अनुदान देने का ऑफर दिया है। सब्जियों की खेती में बॉस और स्टैकिंग विधि का इस्तेमाल करने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस विधि से किसानों की खेती में लागत कम होगी, और सरकार से अनुदान मिलने के बाद मुनाफा भी काफी अच्छा रहेगा।

क्या है यह नई तकनीकी "स्टैकिंग"

इस तकनीकी को छोटे खेतों में प्रयोग किया जाता है। जिनमें सब्जियां उगाई जाती हैं। या विधि में बांस या लोहे के डंडे, रस्सी या तार के सहारे बाड़ बनाई जाती है। शुरुआत में सब्जियों की अच्छी बढ़वार के लिए बेल और लताओं के बांस, रस्सी अथवा तार के जाल का सहारा दिया जाता है। कुछ दिन बाद सब्जियों की बेल व लताएं खुद ही इनसे लिपट जाती हैं। इस तकनीकी में सब्जियां जमीन को नहीं छू पातीं। कीट-रोगों से सुरक्षित रहने के साथ-साथ सब्जियों में जलन-सड़न नहीं होती है।

कैसे और किन किसानों को मिलेगी सब्सिडी?

हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों को स्टैकिंग तकनीकी से सब्जियों उगाने वाले किसानों को 50% से 90% तक सब्सिडी देने की बात कही है। इस योजना में एक किसान के पास 2.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। और वह किसान स्टैकिंग तकनीकी से खेती करे। तब सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

स्टैकिंग तकनीकी पर कितना होगा खर्च?

एक एकड़ खेत में लोहे की स्टैकिंग लगाने में करीब 1 लाख 40 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें सरकार द्वारा 75 हजार से लेकर 1 लाख 25 हजार तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।

कैसे व कहां करें आवेदन?

सबसे पहले किसानों को अपनी जमीन का पंजीकरण 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर करवाना होगा। बांस स्टैकिंग व लोहे की स्टैकिंग पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिये हरियाणा कृषि विभाग के बागवानी पोर्टल HTTP://HORTHARYANASCHEMES.IN/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहें तो अपने जिले के कृषि और बागवानी कार्यालय में जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

हरियाणा के किसानों को स्टैकिंग विधि पर सब्सिडी लेने के लिए आवदेन फार्म के साथ इन दस्तावेजों की जरूरत होगी।

1- निवास प्रमाण पत्र
2- आधार कार्ड
3- जमीन के कागजात
4- बैंक खाते की पासबुक
5- दो पासपोर्ट साइज फोटो
6- किसान का मोबाइल नम्बर

नोट: यह सूचना सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है। MERIKHETI.COM किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले सही जांच कर लें।

फल

इस तरह लगाएं केला की बागवानी, बढ़ेगी पैदावार

केले की प्रोसेसिंग से आज कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जैसे चिप्स, पापड़ । केले के तने और पत्ते से पत्तल, दोना, कपड़े के लिए रेसा आदि । अगर आप भी केला की खेती करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो केला की बागवानी का यह तरीका अधिक फायदेमंद साबित होगा। अपने देश में केला की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। किसानों में भी केला की खेती को लेकर जबरदस्त उत्साह है। किसान केला की फसल से बंपर पैदावार ले रहे हैं।

फलों के राजा आम की बात ही निराली है। आम के सीजन में बाजार में ठेले पर रखे एक से एक सुंदर आम देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है।

इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर का रंगीन आम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। रंग बदलने वाला यह शुगर फ्री आम कम मीठा व स्वादिष्ट है। हालांकि बिहार का मुजफ्फरपुर लाह की चूड़ियां और मीठी लीची के लिए मशहूर है। लेकिन इस सीजन यहां एक खास प्रकार के आम उगे हैं, जो इन दिनों काफी चर्चा में हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले किसान भूषण सिंह के बागान में यह खास किस्म का आम उगा है। आम के इस बगीचे के निकट होकर गुजरने वाला हर व्यक्ति इस आम को देखकर चर्चा जरूर करता है, क्योंकि यह कम मीठा होते हुए भी स्वादिष्ट है। इस आम की वेरायटी का नाम अमेरिकन ब्यूटी है। बताया जा रहा है कि यह आम 100 फीसदी शुगर फ्री है।

बंगाल से आया है यह आम का पौधा

मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव मुशहरी के रहने वाले भूषण सिंह आम के इस रंगीन पौधे को करीब 6 साल पहले बंगाल से लेकर आये थे। और अपने बगीचे में लगाया था। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह पौधा इतना चर्चित होगा।

16 बार रंग बदलता है यह खास आम

बगीचे में पौधा लगाने के दो साल बाद आम के इस पौधे पर फल आना शुरू हो जाता है। फल के मंजर और दाने तो सामान्य आम की तरह ही होते हैं। लेकिन आम पकने तक यह 16 बार रंग बदलता है।

रंग बदलने वाले आम की नर्सरी बनाने की तैयारी

इस खास किस्म के आम ने काफी सुर्खियां बटोरीं हैं। जिसके चलते आम के पौधों की मांग बढ़ गई है। कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने भी आम की गुणवत्ता एवं स्वाद की प्रसंशा की है। बताया जा रहा है कि इस सीजन इस खास किस्म के आम की वैरायटी की नर्सरी तैयार करने की पहल की जा रही है।

केला की इस प्रजाति के पौधे लगाएं

प्रत्येक पेड़-पौधों के लिए प्रजाति का बड़ा महत्व होता है। अच्छी और बेहतर क्वालिटी के पेड़-पौधों की प्रजाति हमेशा फायदेमंद रहती है। केला की रोबस्टा एवं बसराई प्रजाति के पौधे ज्यादा कारगर होते हैं। इस प्रजाति के पौधों से अधिक उत्पादन होता है।

इस तकनीकी से लगाएं केला बागवानी

तमिलनाडु विश्वविद्यालय में हुए एक विशेष शौध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि केला की बागवानी लगाने के लिए प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी 2×3 मीटर और उतनी ही दूरी पर पौधे से पौधा लगाया जाए। एक हेक्टेयर खेत में तकरीबन 5000 पौधे लगाए जाएं। इसमें पोटाश, नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाए। इस विधि से उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है। इस तरह आप केला की प्रथम फसल केवल 12 महीने में ही ले सकते हैं। और इसमें उपज भी बेहतर मिलेगी।

बीटिंग एंड ब्लास्ट रोग से चिंतित हैं केला किसान

केला की खेती करने वाले किसानों को विभिन्न सावधानी बरतने की जरूरत होती है। केला में एक विशेष प्रकार के रोग के कारण केरल और गुजरात के किसानों की चिंता बढ़ गई है। केला में बीटिंग एंड ब्लास्ट नाम के रोग ने किसानों को चिंतित किया है। इससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

कैसे मिलेगी केला में रोग से निजात

केला में होने वाले बीटिंग एंड ब्लास्ट रोग से निजात पाने के लिए किसानों को फिलहाल कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। केला में पाए जाने वाले इस रोग से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में जरुरी है कि इस रोग का बचाव सही समय पर किया जाए। यदि केले की फसल में इस रोग का प्रकोप हो जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाज़ार में मिलने वाले फफूंदनाशक में से कोई भी एक का चयन कर घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में 2 बार पौधों पर छिड़क दें। ध्यान रहे कि छिड़काव केले के फलों के बंच को निकालने के बाद ही करना चाहिए। इस तरह आप बीटिंग एंड ब्लास्ट रोग से फसल का बचाव कर सकते हैं।

फूल

जमा तौर पर माना जाता है कि तालाब झील या जल-जमाव वाले गंदे पानी, दलदल आदि में ही कमल पैदा होता, पनपता है।
लेकिन आधुनिक कृषि विज्ञान का एक सच यह भी है कि, खेतों में भी कमल की खेती संभव है। न केवल कमल को खेत में उगाया जा सकता है, बल्कि कमल की खेती में समय भी बहुत कम लगता है। अनुकूल परिस्थितियों में महज 3 से 4 माह में ही कमल के फूल की पैदावार तैयार हो जाता है।

कमल के फूल का राष्ट्रीय महत्व

भारत के संविधान में राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा रखने वाले कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो नुसिफेरा (NELUMBO NUCIFERA, ALSO KNOWN AS INDIAN LOTUS OR LOTUS) है। भारत में इसे पवित्र पुष्प का स्थान प्राप्त है। भारत की पौराणिक कथाओं, कलाओं में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति के शुभ प्रतीक कमल को उनके रंगों के हिसाब से भी पूजन, अनुष्ठान एवं औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। सफेद, लाल, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के कमल पुष्प एवं उसके पत्तों, तनों का अपना ही महत्व है।

भारतीय मान्यताओं के अनुसार कमल का उद्गम भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से हुआ था। बौद्ध धर्म में कमल पुष्प, शरीर, वाणी और मन की शुद्धता का प्रतीक है। दिन में खिलने एवं रात्रि में बंद होने की विशिष्टता के अनुसार मिस्र की पौराणिक कथाओं में कमल को सूर्य से संबद्ध माना गया है।

कमल का औषधीय उपयोग

अत्यधिक प्यास लगने, गले, पेट में जलन के साथ ही मूत्र संबंधी विकारों के उपचार में भी कमल पुष्प के अंश उत्तम औषधि तुल्य हैं। कफ, बवासीर के इलाज में भी जानकार कमल के फूलों या उसके अंश का उपयोग करते हैं।

खेत में कमल कैसे खिलेगा ?

हालांकि जान लीजिये कमल की खेती के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। खास तौर पर नमीयुक्त मिट्टी इसकी पैदावार के लिए खास तौर पर अनिवार्य है। यदि भूमि में नमी नहीं होगी तो कमल की पैदावार प्रभावित हो सकती है।

मतलब साफ है कि खेत में भी कमल की खेती के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा जरूरी है। ऐसे में मौसम के आधार पर भी कमल की पैदावार सुनिश्चित की जा सकती है।

खास तौर पर मानसून का माह खेत में कमल उगाने के लिए पूरी तरह से मददगार माना जाता है। मानसून में बारिश से खेत में पर्याप्त नमी रहती है, हालांकि खेत में कम बारिश की स्थिति में वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था भी रखना जरूरी है।

खेत में कमल खिलाने की तैयारी

खेत में कमल खिलाने के लिए सर्व प्रथम खेत की पूरी तरह से जुताई करना जरूरी है। इसके बाद क्रम आता है जुताई के बाद तैयार खेतों में कमल के कलम या बीज लगाने का।

इस प्रक्रिया के बाद तकरीबन दो माह तक खेत में पानी भर कर रखना जरूरी है। पानी भी इतना कि खेत में कीचड़ की स्थिति निर्मित हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कमल के पौधों का तेजी से सुगठित विकास होता है।

भारत के खेत में मानसून के मान से पैदा की जा रही कमल की फसल अक्टूबर माह तक तैयार हो जाती है। जिसके बाद इसके फूलों, पत्तियों और इसके डंठल (कमलगट्टा) को उचित कीमत पर विक्रय किया जा सकता है।

मतलब मानसून यानी जुलाई से अक्टूबर तक के महज 4 माह में कमल की खेती किसान के लिए मुनाफा देने वाली हो सकती है।

कमल के फूल की खेती की लागत और मुनाफे का गणित

एक एकड़ की जमीन पर कमल के फूल उगाने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं। इतनी जमीन पर 5 से 6 हजार पौधे लगाकर किसान मित्र वर्ग भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं।

बीज एवं कलम आधारित खेती के कारण आंकलित जमीन पर कमल उपजाने, खेत तैयार करने एवं बीज खर्च और सिंचाई व्यय मिलाकर 25 से 30 हजार रुपयों का खर्च किसान पर आता है।

1 एकड़ जमीन, 25 हजार, 4 माह

पत्ता, फूल संग तना (कमलगट्टा) और जड़ों तक की बाजार में भरपूर मांग के कारण कमल की खेती हर हाल में मुनाफे का सौदा कही जा सकती है। कृषि के जानकारों के अनुसार 1 एकड़ जमीन में 25 से 30 हजार रुपयों की लागत आती है। इसके बाद 4 महीने की मेहनत मिलाकर कमल की पैदावार से अनुकूल स्थितियों में 2 लाख रुपयों तक का मुनाफा कमाया जा सकता है।

MERI KHETI

असली हीरो की ताक़त, भरोसे की विरासत!

NEW HOLLAND AGRICULTURE

जान भी, शान भी!

TX

3037 | 39 HP

ERGP Series | 29.08 kW

मानसून धमाका ऑफर

आकर्षक फायनेंस

स्कीम के साथ उपलब्ध*

6 साल T- वारंटी

इंडस्ट्री में पहली बार

ऑफर 31 जुलाई 2022 तक मान्य

सरकारी नीतियां

भारत देश में कृषि और पशुपालन एक दुसरे के पूरक रहे हैं. हमारे ज्यादातर किसान भाई-बहन खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं. ज्यादातर घरेलु या छोटे स्तर पर पशुपालन के कार्य को महिलाएं कुशलता के साथ संभाल रही हैं.

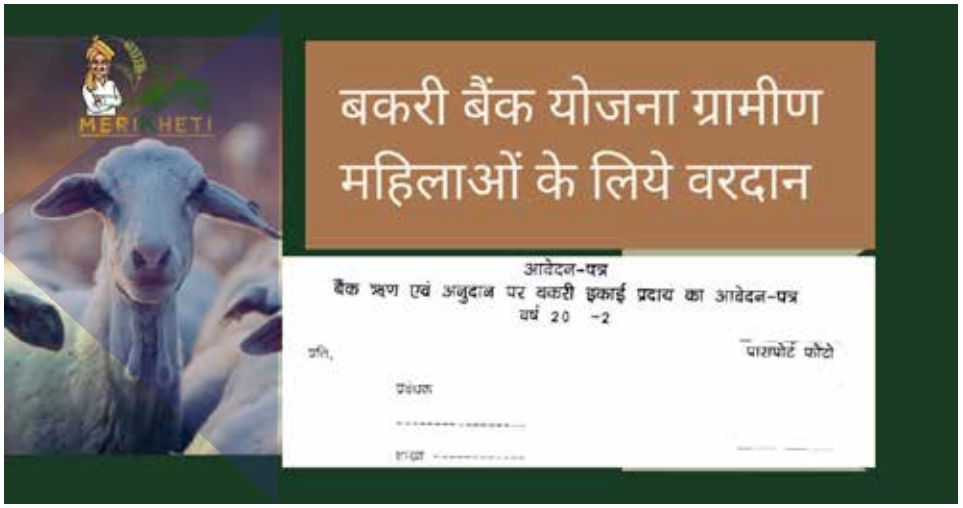

ग्रामीण इलाकों में लगभग हर छोटे और मध्यम किसानों के घर में बकरी पालन किया जाता है, क्योंकि इसमें खर्च कम और मुनाफा अधिक होता है. बकरी के लिये आहार की उपलब्धता भी आसान है, वहीं खर्च भी कम होता है. बकरी पालन के लिये किसी बड़ी तकनीक की भी जरूरत नहीं होती है. कोई भी किसान आसानी से बकरी पालन कर लाभ कमा सकता है. इसीको देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बकरी पालन पर योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम बकरी बैंक योजना है. इस योजना में महिलाओं को बकरी पालने के लिए कम मूल्य पर बकरी उपलब्ध करवाई जाएगी. यही नहीं सरकार के इस बकरी पालन योजना में महिलाओं को बकरी पालन का उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

बकरी बैंक योजना का उद्देश्य

बकरी बैंक योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है. इससे बकरी पालन के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इस व्यवसाय से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगी. अमूमन देखा जाता है कि ग्रामीण महिलाएं अपने घर आंगन में बकरी पालती हैं. लेकिन आबकारी खरीदने के लिये धनाभाव होता है, जिसके कारण चाह के भी वो बकरी नहीं पाल सकती हैं. इस योजना के तहत वैसी महिलाओं को बकरी उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे वो घर में रहते हुये बकरी पाल सकेंगी और इससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा. सबसे बड़ी बात यह है की बकरी के लिये महिलाओं को आसानी से चारा उपलब्ध हो जाता है और बीमा तथा टीकाकरण का खर्च भी सरकारी स्तर पर उठाया जायेगा.

कैसे मिलेगा महिलाओं को बकरी बैंक योजना का लाभ

बकरी बैंक योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा. बकरी बैंक योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को 2 हजार रुपए में एक गर्भवती बकरी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को बैंक में 2 हजार रुपए और साथ ही जितने बकरी के बच्चें होंगे उसमें से एक बच्चा बैंक को देना होगा. इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद बकरी महिलाओं के नाम कर दी जाएगी. बकरी बैंक योजना के तहत बकरी का बीमा और उनके लिए टीकाकरण का खर्च भी बैंक द्वारा वहां किया जायेगा.

बकरी बैंक योजना में निशुल्क होगा पंजीकरण

सरकार के इस योजना का लाभ उठाने के लिये इच्छुक महिलाओं को इसके लिए 1200 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा. इसके बाद बकरी के लिये ऋण के नियमों के तहत महिलाओं को बकरी उपलब्ध कराई जायेगी.

बैंक नियमानुसार, 40 महीने के समय के अंदर योजना के तहत बकरी प्राप्त करने वाली महिलाओं को 4 बकरी के बच्चे बैंक को देने होंगे. इसके बाद ही बकरी पर महिला का पूर्ण अधिकार होगा. इसके पूर्व बकरी बैंक की ही मानी जाएगी.

NEW HOLLAND AGRICULTURE

किसानों के लिए खुशी की खबर

कृषि विभाग ने खरीफ फसल की बुआई से पहले फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है. कृषि विभाग के इस कदम से किसान कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे.

किसानों के लिए कृषि विभाग ने अरहर, मूंग और उड़द के उन्नतशील बीजों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का वादा किया है. जिससे कारण किसान बहुत खुश है. पहले जहां किसानों को मंहगे दामों पर भी अच्छे बीज नही मिलते थे. वही कृषि विभाग के इस फैसले से किसानों को आधे दाम में बढ़िया क्वालिटी के बीज मिलेंगे.

यहां तक कि किसानों को निः शुल्क अरहर, मूंग व उड़द के बीज मिनी किट में उपलब्ध कराए जा रहे है. यह काम शुरुआत हो चुकी है, जिले में 31 क्विंटल 85 किलोग्राम अरहर, 32 क्विंटल उड़द और 9 क्विटल मूंग के बीज सब्सिडी के साथ उपलब्ध करवाए गए है. इसके साथ ही किसान निः शुल्क मिनी किट जो की चार चार किग्रा की होती है, उन्हें भी किसान राजकीय बीज भंडार से ले सकता है. मिनी किट के रूप में अरहर 15 क्विंटल, उड़द 18 क्विंटल और मूंग चार क्विंटल बीज है.

उच्च क्वालिटी के मक्के के बीज प्रदर्शन के लिए आए है

150 क्विंटल मक्के के बीज प्रदर्शन के लिए आए, जिन्हें 750 हेक्टेयर तक की भूमि पर बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ खाद और खरपतवार नाशक दवाइयां भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी.

राजकीय बीज भंडारों से किसान सब्सिडी के साथ बीज ले सकते है

सत्येंद्र चौहान जो की उप कृषि निदेशक है, उन्होंने बताया कि राजकीय बीज भंडारों पर बीज उपलब्ध करवा दिए गए है. जो भी किसान सब्सिडी के साथ बीज लेना चाहता है. वह राजकीय बीज भंडार में आकर ले सकता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद है की जो भी किसान फसल नुकसान से जूझ रहे है, उन्हें आर्थिक मदद देकर उनका हौसला कायम रखे. किसानों को आधुनिक उपकरणों के इस्तमाल के लिए प्रेरित करना.

इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने फसल बीमा जागरूकता सप्ताह कि शुरुआत की. जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर 15 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में बताने के लिए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस बीमा योजना से जोड़ने के लिए रवाना किया गया है. 15 जुलाई तक जागरूकता रथ पूरे राज्य में भ्रमण कर किसानों को बीमा योजना से जुड़ने के लिए जागरूक करेगा.

रविद्र चौबे जी के अनुसार 2021-22 में 1063 करोड़ बीमा दावा राशि का भुगतान राज्य के 5 लाख 66 हजार किसानों को मिला.

किसानों को कितने प्रीमियम में कितना मिल चुका है लाभ ?

डेढ़ लाख किसानों को खरीफ सीजन शुरू होने से पहले उनके द्वारा दी गई प्रीमियम 15 करोड़ 96 लाख रुपए की एवज में 304 करोड़ 38 लाख की क्लेम राशि भुगतान की गई. 4 लाख से अधिक किसानों को 157 करोड़ 65 लाख रुपए के प्रीमियम के एवज में 758 करोड़ 43 लाख तक का क्लेम भुगतान किया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम कितना देना होगा ?

इस बीमा योजना में किसानों को बीमा प्रीमियम का सिर्फ डेढ प्रतिशत राशि देनी होती है. जबकि मौसम पर आधारित फसल जैसे की बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का देना होता है और बाकी बचा हुआ सरकार देती है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास दो तरीके है -

ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको pmfby.gov.in में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा

ऑफलाइन आवेदन
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको कृषि विभाग जाकर फॉर्म लेना होगा और वही भरकर देना होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास बैंक खाता, खेत का खसरा नंबर, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदनकर्ता का निवास प्रमाण पत्र, यदि खेत किराए पर है तो मालिक के साथ इकरार नामा की कॉपी, फसल बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख, ये सारे दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक है

राजस्थान सरकार देगी निशुल्क बीज

राजस्थान सरकार पहली बार कृषि के उत्थान के लिए अलग से कृषि बजट लाई है. इस बजट में मिलेट प्रमोशन मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके तहत फसल सुरक्षा मिशन के जरिए एक करोड़ पच्चीस लाख मीटर मे तारबंदी के लिए सहायता दी जाएगी, वहीं फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए हर गांव में एक नंदी शाला बनाने की योजना भी लाई गई है.

जैविक खेती मिशन शुरू की जाएगी और साथ ही कस्टम हायरिंग सेंट्रल को 1000 ड्रोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

राजस्थान के कृषि बजट में की गई घोषणाओं को लेकर सरकार किसानों के बीच जा रही है और पूरी जानकारी दे रही है. जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में बजट की घोषणाओं को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. कार्यक्रम में किसानों को जानकारी दी गई कि अभी तक 15000 मूंग और 42000 संकर बाजरा के बीजों का निशुल्क वितरण किसानों के बीच किया गया है.

कार्यक्रम में जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि किस प्रकार अलग से पेश किए गए इस बजट के प्रावधानों का किसानों को लाभ मिलेगा और इससे उत्पादकता बढ़ेगी. खेती किसानी को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 12 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को निशुल्क बीज मुहैया कराई जानी है. इसके तहत 8 लाख संकर मक्का मिनीकट, १० लाख बाजरा, २.७४ लाख मूंग, 26314 मोठ, 31275 उड़द एवं 1 लाख ढेंचा बीज का किसानों के बीच मुफ्त में वितरण किया जाना है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों के बीज को लेकर हो रही परेशानी समाप्त हो जाएगी. साथ ही खेती की लागत में भी कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी.
रबी या खरीफ किसी भी सीजन में किसानों को अच्छी बीज प्राप्त करने में काफी समस्या आती है. पैसा खर्च करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हें नकली बीज मिलता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती और किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है.

मौके पर कृषि पदाधिकारियों ने बताया कि 2022 - 23 के कृषि बजट में किसान कल्याण कोष की रकम को दो हजार करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रूपया कर दिया गया है. कृषि साथी योजना के अंतर्गत ११ मिशन चलाए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है. कई काम आरंभ भी किए जा चुके हैं.

फार्म पॉन्ड और डिग्गी निर्माण में किसान रुचि ले रहे हैं. वही ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लोड टलन के लिए भी बड़ी मात्रा में किसानों का आवेदन प्राप्त हो रहा है.

भारत सरकार द्वारा देश भर में इसके लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प पर सब्सिडी देने के लिए किसानों से आवेदन माँगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कर इच्छुक किसान सोलर पम्प की बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करने के बाद किसानों को चालान के माध्यम से अपने अंश की राशि बैंक शाखा में जमा करानी होगी।

सोलर पम्प पर दिया जाने वाला अनुदान

किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की लागत का कुल 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी. किसानों को लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा स्वयं देना होगा।

सोलर पम्प की क़ीमत एवं अनुदान

- सरकार ने 2 एचपी डीसी और एसी सर्फेस पम्प के लिए 1 लाख 44 हजार 526 रूपये मूल्य निर्धारित किया है। जिसमें किसानों को मात्र 57 हजार 810 रूपये देना होगा, शेष राशि सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दी जाएगी।
- वहीं 2 एचपी. डीसी सबमर्सिबल पम्प का मूल्य 1 लाख 47 हजार 131 रुपए निर्धारित है। इस पर किसानों को 88 हजार 278 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और किसानों का अंशदान 58 हजार 835 रूपये होगा.
- 2 एचपी. एसी सबमर्सिबल की लागत मूल्य 1 लाख 46 हजार 927 रूपये, सब्सिडी 88 हजार 756 रूपये और किसानों के अंशदान की राशि 59 हजार 71 रूपये होगा.
- 3 एचपी एसी एवं डीसी सबमर्सिबल की क़ीमत सरकार ने 1 लाख 94 हजार 516 रुपए रखी है। इसमें किसानों को 1 लाख 16 हजार 710 रूपये का सब्सिडी मिलेगा जबकि शेष राशि 77 हजार 806 रूपये किसानों को अंशदान के रूप नें देना होगा.
- वहीं 3 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए सोलर पम्प की लागत 1 लाख 93 हजार 460 रूपये निर्धारित है. इस पर सरकार किसानों को 1 लाख 16 हजार 076 रूपये सब्सिडी देगी। जबकि शेष राशि अंशदान के रूप में किसानों को 77 हजार 384 रूपये देना होगा |
- 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल की क़ीमत कुसुम योजना के तहत 2 लाख 73 हजार 137 रूपये लागत मूल्य तय है. 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल पर सरकार 1 लाख 63 हजार 882 रूपये का अनुदान देगी, जबकि अंशदान के रूप में किसानों को शेष राशि 1 लाख 09 हजार 255 रूपये देना होगा.
- 7.5 एचपी.एसी सबमर्सिबल की क़ीमत सरकार नें 3 लाख 72 हजार 126 रूपये तय किया है. इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 23 हजार 276 रूपये अनुदान देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 48 हजार 850 रुपए किसानों को देना होगा।
- 10 एचपी.एसी सबमर्सिबल की लगत मूल्य 4 लाख 64 हजार 304 रूपये निर्धारित है. इस पर किसानों को 2 लाख 78 हजार 582 रूपये अनुदान मिलेगा, जबकि शेष राशि 1 लाख 85 हजार 722 रुपए किसानों को देना होगा।
- सिचाई के लिये पम्प के लिये इच्छुक किसानों के खेतों में बोरिंग होना आवश्यक है. राज्य उन्हीं किसानों को योजना का लाभ देगी जिनके खेत में बोरिंग उपलब्ध होगा.

इसके लिए कुछ नियम बनायें हैं

- 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच का बोरिंग होना चाहिए.
- किसानों को बोरिंग स्वयं करानी होगी.
- 22 फिट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फिट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एचपी सबमर्सिबल तथा 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एवं 10 एचपी के सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं.
- जलस्तर के अनुसार किसान पंप का चयन करेंगे.

किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagriculture.com पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा. ऑनलाइन बुकिंग और टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इण्डियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

हरियाणा में सरकार किसानों के लिए एक अच्छी योजना बनाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान फसल बुवाई के समय एग्री लोन लेकर, कटाई के समय उस लोन को चुकता करेंगे। क्योंकि फसल बुवाई के दौरान किसान के हाथ में पैसा कम होता है और खर्चा बहुत ज्यादा, जबकि फसल कटाई के समय किसान के हाथ में पैसा होता है, इसीलिए यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी।

समय पर एग्री लोन लेकर समय से ही जमा करने वाले किसानों को सरकार ने एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक (हरको) (The Haryana State Co-op Apex Bank Ltd (HARCO)) की समीक्षा में बैठक में यह बातें कहीं। अगर बैंक सीएम का सुझाव मानते हैं तो किसानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।

पैक्स की जगह वैक्स को करेंगे प्रभावी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता वाली बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया, जिसमें पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी) (Primary Agricultural Credit Society (PACS)) के एकाधिकार को खत्म करके वैक्स, यानी ग्राम कृषि प्राथमिक सहकारी समितियों (Village Agriculture primary Cooperative Societies (VACS)) को बनाने का फैसला लिया गया है। वैक्स में गांव-देहात के पढ़े-लिखे युवा किसान भी शामिल होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा और किसान भाई ही वैक्स का संचालन करेंगे।

हर जिले में खोले जाएं हरको बैंक

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं के नियंत्रण हरको बैंक ही रखते हैं। वर्तमान में हरियाणा के चंडीगढ़ व पंचकूला में ही हरको बैंक की शाखाएं संचालित हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के हर जिले में हरको बैंक खोलने की संभावना तलाशी जाएं। भले की हरको बैंक का सीधा संबंध पैक्स से नहीं होता है, लेकिन हरको बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं पर तो नियंत्रण रखते ही हैं।

हर साल भण्डारण की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों के लाखों करोड़ों का कृषि उत्पाद नष्ट हो जाता है. किसानों को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है और काफी आर्थिक क्षति होती है. विगत वर्ष देश के कई क्षेत्रों में किसानों को फल सब्जियां औने पौने दाम में बेचना पड़ा और कई जगहों पर प्याज, टमाटर सहित अन्य फल और सब्जियों को नाले और कूड़े पर फेंकते देखा गया था. इस बर्बादी को बचाने और किसानों के कृषि उत्पाद के सही ढंग से भण्डारण के लिए केंद्र सरकार एक योजना लाई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके. इस योजना का नाम है एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)).

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) खोलने के लिए सरकार किसानों को 50 फीसदी अनुदान देती है. कृषि व किसान कल्याण विभाग, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी के कार्यों के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है

कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी

किसानों में यह भ्रम होता है की कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार लोन देती है. लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है की सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए कोइ लोन नहीं देती है. इसके लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) दी जाती है. इस सब्सिडी में भी क्षेत्रवार अंतर होता है. मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी में भिन्नता होती है.

मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाती है. पूर्वोत्तर इलाकों में एक हजार मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता वाली परियोजना को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.

कोल्ड स्टोरेज के लिए कितना मिलता है अनुदान ?

- 15 लाख रुपए तक के कोल्ड रूम (स्टेंटिक) यूनिट के लागत पर 5.25 लाख रुपए
- कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 यूनिट लागत 4 करोड़ रुपए पर 1.40 करोड़ रुपए
- कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 (अनुसूचित क्षेत्र) लागत 4 करोड़ रुपए पर 2 करोड़ रुपए
- कोल्ड स्टोरेज टाइप-2 (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामान्य क्षेत्र) लागत 35 लाख रुपए पर 12.25 लाख रुपए

कोल्ड स्टोरेज के लिए पात्रता

- किसान व्यक्ति,उपभोक्ताओं/उत्पादकों का समूह, किसान उत्पादक संगठन
- स्वामित्व/ भगीदारी फर्म, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कम्पनियाँ, निगम.
- कृषि उत्पादन विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/ समितियां, नगर निगम, समितियां, कृषि
- उद्योग निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संघ एवं अन्य सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास संगठन.

कोल्ड स्टोरेज के लिए कितना मिलता है अनुदान ?

- स्व-सत्यापित पैन कार्ड/ वोटर कार्ड
- स्व-सत्यापित आधार कार्ड
- कम्पनी/ सोसाईटी/ ट्रस्ट/ पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र और एसटी के लिए स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र
- व्यक्तिगत किसान के लिए परियोजना भूमि आवेदक किसान के नाम से होना आवश्यक होगा.
- आवेदक परियोजना भूमि में संयुक्त मालिकों में से एक होगा, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र
- साझेदारी फर्म के लिए यदि भूमि की मल्कियत साझेदारों में से किसी एक की हो, तो भूमि
- मालिक साझेदार की ओर से शपथ पत्र देगा की परियोजना की जमीन वापस नहीं लेगा,
- बिक्री या हस्तानान्तरण नहीं करेगा.
- भूमि पर कब्ज़ा प्रमाण पत्र
- परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट

कोल्ड स्टोरेज के लिए कहाँ करें आवेदन ?

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए आवेदन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन के जिला कार्यालय में पदस्थापित उप संचालक, सहायक संचालक उद्यान से बृहत् जानकारी ली जा सकती है. आवेदन प्रस्ताव जिला कार्यालय में जमा करना होगा. प्राप्त प्रस्ताव आवेदन को 'पहले आओ पहले पाओ ' के आधार पर स्वीकार किया जाता है. योजना में आवेदन के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://nhb.gov.in/OnlineApplication/Registration-Form.aspx पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

फसलों को आवारा पशुओं से काफी नुक्सान होता है. देश के विभिन्न राज्यों में यह समस्या काफी विकराल होती जा रही है. उत्तर प्रदेश के किसान आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए रात रात भर खेतों की रखवाली के लिए मजबूर हैं. किसानों ने सरकार से फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए गुहार भी लगायें हैं. बिहार में नीलगाय (घोड्परास) के आतंक से त्रस्त हैं. सरकार ने भी इस ओर कड़े कदम उठाते हुये इन्हें मारने की इजाजत दी है और इसके लिए बाहर से शूटर भी मंगाए गए हैं. कहने का तात्पर्य यह है की कमोबेश आवारा पशु फसल के लिए अभिशाप बने हुये हैं

रोका – छेका अभियान

छत्तीसगढ़ के किसान भी आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद किये जाने को लेकर परेशान हैं. इसके कारण किसानों को काफी नुक्सान सहना पड़ता है. फसलों को आवारा पशुओं से बचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.

आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोका – छेका अभियान (Roka Cheka Abhiyan) चलाई जा रही है. 10 जुलाई से 20 जुलाई तक चालु खरीफ के समय ये अभियान चलाई जा रही है. इसको लेकर सरकार द्वारा किसानों से सहयोग की अपील की गयी है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से कहा है कि रोका – छेका हमारी परम्परा में है. योजना को सफल बनाने की अपील करते हुये उन्होंने कहा, किसान संकल्प लें कि चराई के लिए पशुओं को खुले में नहीं छोड़ें. घर, खलिहान या गौठानों (गौशाला) में पशुओं को रखें और उनके चारा पानी का इंतजाम करें.

रोका छेका का काम, अब गांव में गौठानों के बनने से सरल हो गया है। गौठानों में पशुओं की देखभाल और उनके चारे-पानी का प्रबंध समितियां कर रही हैं. खरीफ फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए पुरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा.

पशुओं के किये स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने के लिए रोका-छेका अभियान के तहत ढिंढोरा पीटकर प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है. गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधान एवं टीकाकरण किया जा रहा है. पशुओं में बरसात के मौसम में गलघोंटू या घरघरा रोग और एकटंगिया की बीमारी होती है। पशुओं को इन दोनों बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टीका लगाया जा रहा है. गोठानों में लगने वाले इस शिविर में किसान अपने पशुओं का स्वस्थ्य जांच और टीकाकरण भी करा सकते हैं। खुरपका और मुंहपका रोग के रोकथाम की कवायद तेज की गयी।

पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था

राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल हो सके इसी उद्देश्य से गांव में गौठानों का निरमान कराया जा रहा है. सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 10,624 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है, जिसमें से 8408 गौठान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है.

चारागाहों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है, ताकि गौठानों में आने वाले पशुओं को सुखा चारा के साथ हरा चारा भी उपलब्ध कराई जा सके. राज्य के 1200 से अधिक गौठानों में हरे चारे का उत्पादन भी पशुओं के लिए किया जा रहा है।

12 हजार हेक्टेयर जमीन में डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने का शासन ने दिया है लक्ष्य

पंजाब सरकार कृषि विभाग डीएसआर तकनीकी (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक) या सीधी बिजाई से धान की खेती करने वाले किसानों को ईनाम दे रही है। इस तकनीकी से धान की रोपाई करने से 35 फीसदी पानी की बचत होती है। जिसे ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पूरे राज्य के किसानों को 12 लाख हेक्टेयर जमीन में डीएसआर तकनीकी से धान की फसल करने का लक्ष्य दिया है। हालांकि अभी 77 हजार हेक्टेयर में ही डीएसआर तकनीकी से धान की खेती की जा रही है, जो लक्ष्य से काफी पीछे है। राज्य सरकार ने इस तकनीकी से धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए ईनाम देने की घोषणा की है।

बढ़ा दी गई है डीएसआर से खेती करने की तारीख

कृषि विभाग ने धान की सीधी बुवाई करने के लिए पहले 30 जून तक का समय दिया था। लेकिन लक्ष्य से पीछे रहने के कारण इसकी तारीख अब 4 जुलाई कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि अभी इसका समय और बढ़ाया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर डीएसआर तकनीकी से धान की फसल हो सके।

जानें क्या है डीएसआर तकनीकी?

यहां किसानों को यह समझने की जरूरत है कि आखिर डीएसआर तकनीकी क्या है? डीएसआर तकनीकी में धान के बीज को सीधे खेत में लगाया जाता है। इसमें धान की नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे प्रसारण बीज विधि (डीएसआर) कहा जाता है। इसके लिए खेत की जमीन समतल होनी चाहिए।

'प्रसारण बीज विधि' के फायदे एवं नुकसान

प्रसारण बीज विधि (डीएसआर) के तहत धान की फसल करने वाले किसानों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस विधि से खेती करने के कितने फायदे एवं नुकसान हैं।

फायदे

डीएसआर तकनीकी से धान की फसल को सीधे ड्रिल किया जाता है। इससे पानी की 35% तक बचत होती है। इसमें बासमती किस्म के धान की अच्छी रोपाई होती है। इस विधि से धान की खेती करने पर सरकार से ईनाम दिया जा रहा है।

नुकसान

डीएसआर तकनीकी से धान की फसल करने से खेत में खरपतवार होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। धान रोपाई की अपेक्षा फसल लेट हो सकती है। किसानों के लिए पानी की सप्लाई भी बेहतर ढंग से करना मुश्किल हो सकता है।

खरीफ की फसल के सीजन में किसानों को भरपूर बीज एवं खाद देने की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान सरकार ने समस्त अधिकारियों को खाद व बीज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि किसानों को इन दोनों कृषि इनपुट की दिक्कत न हो। इसके लिए कृषि विभाग डीएपी, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) फर्टिलाइजर का स्टॉक प्रचुर मात्रा में रखें। किसान भाई इस वर्ष खाद की चिंता न करें।

आंकड़ो के अनुसार राजस्थान में 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य के विपरीत अब तक 66.05 लाख हेक्टेयर बुवाई हो चुकी है।

उच्च क्वालिटी की पाइप लाइन बिछाने के निर्देश

सरकार ने किसानों के खेतों में बिछाई जाने वाली पाइप लाइन की क्वालिटी उच्च रखने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि पाइपलाइनों को जमीन के भीतर डालने की अपेक्षा जमीन के ऊपर बिछाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे किसानों को पाइपलाइन में लीकेज की जानकारी का सही व जल्दी पता चल सके। इसके अलावा खेतों में बनने वाले किसान फार्म पौंड स्कीम (Farm pond (Khet talai)) पर सुरक्षा की व्यावक व्यवस्था करने के लिए भी सख्ती से निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में 15 लाख बीज किट वितरित

राजस्थान सरकार ने इस साल करीब 25 लाख किसानों को मुफ्त में बीज देने का लक्ष्य रखा है। जिसमें अब तक 15 लाख मिनिकिट्स वितरित किए जा चुके हैं। किसानों को बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द व सोयाबीन के बीज दिए जा रहे हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

जैविक खेती के लिए किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग

राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को जैविक खेती के क्रियान्वयन के लिए ट्रेनिंग देने जा रही है। जैविक खेती के क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार में अधिक से अधिक प्रगतिशील एवं युवा किसानों को शामिल किया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान किसानों को कृषि ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा।

देश में दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन कम एवं माँग अधिक है. यही कारण है कि किसानों को इन फसलों के अच्छे मूल्य मिल जाते हैं. वहीं दलहन या तिलहन की खेती में धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है।

यही कारण है कि अलग-अलग राज्य सरकारें किसानों को धान की फसल छोड़ दलहन एवं तिलहन फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को दलहन और तिलहन की खेती करने के लिय प्रोत्साहित करती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है की भारत खाद्य पदार्थों जैसे, धान, गेहूं आदि में तो आत्मनिर्भर है, पर दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। आज भी देश में बाहर से दलहन का आयात करना पड़ता है। स्वाभाविक है की राज्य सरकारें दलहन और तिलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है। इसी नीति के तहत हरियाणा सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों पर अनुदान देने का निर्णय लिया है।

दलहन फसलों जैसे मूँग एवं अरहर और तिलहन फसलों जैसे अरंडी व मूँगफली की फसल लगाने पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान का प्रावधान किया है. हरियाणा सरकार के अनुदान के फैसले के पीछे बड़ा उद्देश्य यह भी है की इससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके. इस योजना का दोहरा लाभ किसानों को होगा. क्योकि एक तो दलहन और तिलहन फसलों की कीमत भी किसानों को अधिक प्राप्त होगा और साथ ही साथ अनुदान की राशि भी सहायक हो सकेगा. सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को अनुदान के रूप में प्रति एकड़ चार हजार रुपए देने का निर्णय लिया है।

सात ज़िले के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार की ओर से झज्जर सहित दक्षिण हरियाणा के सात जिलों का चयन इस अनुदान योजना के लिये किया गया है. इन सात जिलों में झज्जर भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व नूंह शामिल है. हरियाणा सरकार नें इन सात जिलों के दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को चार हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कितना अनुदान मिलेगा किसानों को ?

हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत दलहन व तिलहन की फसल उगाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह योजना दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों: झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ, रेवाड़ी, हिसार तथा नूंह में खरीफ मौसम 2022 के लिये लागू की जायेगी।
हरियाणा सरकार नें प्रदेश में खरीफ मौसम 2022 के दौरान एक लाख एकड़ में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार नें इस योजना के तहत दलहनी फसलें मूँग व अरहर को 70,000 एकड़ क्षेत्र में और तिलहन फसल अरण्ड व मूँगफली को 30,000 एकड़ में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

किसान यहाँ करें आवेदन

चयनित सातों ज़िलों के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जाकर सबसे पहले पंजीकरण कराना होगा। वित्तीय सहायता फसल के सत्यापन के उपरान्त किसानों के खातों में स्थानान्तरण की जाएगी।

किसान समाचार

महाराष्ट्र में इस सीजन कपास की खेती का रकबा बढ़ना तय है। क्योंकि बीते साल कपास की खेती किसानों के लिए सफेद सोना साबित हुई थी। कपास से किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया था, जिसके चलते इस सीजन कपास की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन कपास के किसानों के किये गुलाबी सुंडी कीट सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पहले भी पिंक बॉलवर्म (Pink bollworm) की बढ़ती घटनाओं के कारण कपास उत्पादन घटता रहा है। इस खतरनाक कीट से अन्य दूसरी फसलें भी प्रभावित होती हैं।

कपास के लिए सबसे खतरनाक बने इस गुलाबी सुंडी कीट से बचाव के लिए किसान मेटिंग डिस्टर्बन्स तकनीकी (Mating disruption (MD) pest management technique) का उपयोग कर रहे हैं। यह तकनीकी कपास का उत्पादन करने वाले महाराष्ट्र के 23 जिलों में लागू हो चुकी है। इसके लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया गया है। और इसकी शुरुआत खरीफ सीजन से होने जा रही है

जैविक खेती के लिए किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग

कपास की फसल के साथ-साथ अन्य फसलों में गुलाबी सुंडी के प्रकोप को रोकने के लिए सल्फर रसायनों का उपयोग किया जाएगा। गंधक को पौधे के एक विशिष्ट भाग में लगाने के बाद नर कीट मादा कीट की गंध से आकर्षित होंगे और बार-बार आने के बावजूद वे वापस लौट आएंगे। क्योंकि उन्हें मादा पतंग नहीं मिलेगी। ऐसे में वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे और अंडे देने की प्रक्रिया में रुकावट के कारण नए कीटों का उत्पादन नहीं होगा। इससे कीटों के अत्यधिक बढ़ते प्रकोप को रोका जा सकता है।

इस वर्ष कपास उत्पादन करने वाले 23 जिलों में यह प्रयोग शुरू किया जा रहा है। कपास अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ कृष्ण कुमार के बताए अनुसार यह प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन इसे प्रभावी माना जाता है। इससे किसानों में कुछ सन्तोष दिखाई दे रहा है।

गुलाबी सुंडी के प्रकोप के चलते कपास की खेती छोड़ चुके थे किसान

बीते कई वर्षों से कपास की खेती में गुलाबी सुंडी कीट का भारी प्रकोप रहा है। पिंक बॉलवर्म के प्रकोप के चलते किसान कपास की खेती छोड़ चुके थे। लेकिन पिछले सीजन में कपास की खेती ने किसानों की बल्ले-बल्ले कर दी। बाजार में कपास का अच्छा भाव मिला और किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया। यही कारण है कि इस बार कपास का रकबा बढ़ने जा रहा है।

कपास के साथ-साथ सोयाबीन का बढ़ेगा रकबा

महाराष्ट्र में कपास की खेती के साथ-साथ सोयाबीन का रकबा बढ़ना तय है। कृषि विभाग भी इसकी भविष्यवाणी कर चुका है। पिछले साल कपास और सोयाबीन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिला था। इसके अलावा राज्य में बारिश के सक्रिय होने के कारण खरीफ की बुवाई में तेजी आई है। दलहन की जगह किसान कपास और सोयाबीन की खेती पर जोर दे रहे हैं।

भारत पिछले 40 दिनों से जरूरतमंद देशों को बिना शर्त ही सस्ता गेंहू उपलब्ध करा रहा है, क्यूंकि इस साल गेंहू की कम पैदावार के चलते वैश्विक बाजार में गेंहू का भारी संकट है।

रूस ने भी भारत की तरह जरूरतमंद देशों को सस्ता गेंहू देने की योजना बनाई है। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी है कि गेंहू खरीद का भुगतान केवल उसकी अपनी मुद्रा रूबल में ही करना होगा। इसके पीछे पहली वजह ये है कि प्रतिबंध की वजह से रूस डालर को रूबल से एक्सचेंज नहीं कर सकता है। दूसरी वजह है कि रूबल में भुगतान होने की सूरत में उसकी मुद्रा अधिक मजबूत होगी। इस तरह रूस ने वैश्विक बाजार में बड़ा पासा फेंक दिया है। रूस ने यह निर्णय अपने देश का निर्यात बढाने के लिए भी लिया है।

यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के चलते रूस कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अब अपने गेंहू की नई पैदावार को नुकसान से बचाने के लिए रूस ने एक बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत उसने ग्रेन एक्सपोर्ट टैक्स को कम करने का फैसला किया है। इसका सीधा रूस से होने वाले गेहूं निर्यात पर पड़ेगा। रूस की मंशा भी यही है। यह भी बता दें कि रूस विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। कई जरूरतमंद देश रूस से ही अपनी गेहूं की जरूरत को पूरा भी करते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है।

टैक्स में भी किया है बदलाव

टैक्स की नई दरें छह जुलाई से लागू हो जाएंगी। रूसी कृषि मंत्रालय के अनुसार इस गर्मी के मौसम में रूस में गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। इसके कारण निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध रहेगा। रूस ने टैक्स घटाकर 4,600 रूबल (86 डालर) प्रति टन कर दिया है। रूस इसी टैक्स दर पर अपने परंपरागत ग्राहक पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों को गेहूं की आपूर्ति करेगा।

दुनियाभर में गेहूं की सप्लाई करते हैं रूस और यूक्रेन

रूस और यूक्रेन दुनियाभर में गेहूं की सप्लाई करते हैं। दोनों देश खाद्यान्न और खाद्य तेल समेत दूसरे खाद्य पदार्थों के बड़े निर्यातक हैं। दोनों देश यूरोप के 'ब्रेड बास्केट' (Breadbasket of Europe) कहे जाते हैं। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29 और मक्के में 19 फीसदी की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। रूस का नंबर दूसरा है। एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स (S&P Global Platts) के मुताबिक दोनों मिल कर सूरजमुखी तेल के उत्पादन में 60 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन लड़ाई की वजह से कुछ फ्यूचर एक्सचेंजों में तो कमोडिटी के भाव 14 साल के शिखर पर पहुंच गए।

ओनियन प्राइज (Onion Price), यानी भारतीय स्वादिस्ट व्यंजनों में तड़के की अहम कारक, प्याज के दामों में फिर असमंजस की छौंक लगी है।
इस बार प्याज की कीमतों के उन आंकड़ों को लेकर विरोधाभास पैदा हुआ है, जिसे सरकार ने जारी किया है।

प्याज के उत्पादन और विक्रय मूल्य पर निर्मित असमंजस से जुड़े आंकड़ों में इस बार सवाल उपजा है, कि क्या किसानों को फिर से प्याज़ का भाव कम मिलेगा ?

मतांतर की वजह

एक टीवी चैनल पर जाहिर किसान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के विचारों के बाद यह विषय प्रकाश में आया है। मामला प्याज उत्पादन संबंधी पिछले साल के मुकाबले 50 लाख मीट्रिक टन अधिक होने के अनुमान से जुड़ा है।

इस डेटा पर असमंजस

केंद्र सरकार के प्याज उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को किसानों ने खारिज कर दिया है।

किसानों की राय में इस अनुमान के अनुसार तो इससे प्याज के दामों में गिरावट होगी। किसानों का दावा कि अभी वे 50 पैसे से लेकर 5 रुपये प्रति किग्रा तक के दाम पर प्याज बेचने को विवश हैं।

आंकड़ों ने बढ़ाई धड़कन

बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान संबंधी केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जो आंकड़े जारी किये हैं उस पर ही किसानों को असमंजस है।

उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान संबंधी सरकारी आंकड़ों के मान से प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक होने का अनुमान है।

आशंका बाजार में गफलत की

किसानों का मानना है कि, इन आंकड़ों के मान से जब पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बाजार में प्याज के दामों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

एक आशंका यह भी है कि, मंडियों में किसानों को फिलहाल मिल रहे प्याज के दामों में इन अनुमानित आंकड़ों से और गिरावट हो सकती है।
प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र सरकार से इन आंकडों के बारे में सरकारी स्तर पर गणित को समझाने की मांग की है। किसान नेताओं ने फसलों के अग्रिम अनुमान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।

महाराष्ट्र का हवाला

इस बारे में महाराष्ट्र का हवाला महाराष्ट्र किसान संगठनों ने दिया है। बताया जा रहा है कि, बीते तीन माह से महाराष्ट्र में प्याज के दाम 50 पैसे से लेकर 5 रुपये किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंचे हैं। किसान प्याज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

आंकड़े यह भी

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में साल 2021-22 के दौरान सवा तीन करोड़ से अधिक (3,17,03,000) मीट्रिक टन प्याज पैदा होने का अनुमान है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2020-21 में महज 2,66,41,000 मीट्रिक टन प्याज उत्पादित हुई। इस मान से बीते साल से 50 लाख 62000 मीट्रिक टन अधिक प्याज का उत्पादन का अनुमान है। 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक होने का अनुमान है।

आंकड़ों का आधार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों का आधार रिकॉर्ड बुवाई बताया गया है। इस वर्ष 2021-22 में 19,40,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई थी। साल 2020-21 में 16,24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बोवनी हुई। अर्थात 3,16,000 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में बुवाई हुई थी।

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्याज उत्पादन के आंकड़ों पर संशय जताया है।

एक डिजिटल टीवी नेटवर्क से चर्चा में उन्होंने डेटा को हकीकत से परे बताया है। उन्होंने प्याज उत्पादन लागत पर लाभ जोड़कर, प्याज का एक न्यूनतम रेट तय करने की मांग की है, ताकि अनुमानित आंकड़ों से किसानों को संभाव्य अनुमानित भारी नुकसान न हो।

खरीफ सीजन की बुआई के साथ ही पुरे देश में फसलों का बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीयन करने का काम शुरू हो गया है। फसल बीमा योजना का लाभ किसानो को अधिक से अधिक मिले, इसके लिये सरकारी स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

अधिक से अधिक किसान योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाएँ, इसी को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) को लेकर जागरूकता अभियान के तहत ही देशभर में 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है।

जागरूकता अभियान के तहत फसल बीमा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

शुक्रवार को राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने 35 फसल बीमा वाहनों को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कृषि मंत्री श्री कटारिया नें कहा कि इस वैन केम्पेन द्वारा राज्य के दूर-दराज के गांवों एवं किसानों तक कृषक बीमा पॉलिसी का प्रचार-प्रसार किया जायेगा और जानकारी पहुंचाई जाएगी।

किसानों को फसल बीमा क्लेम 15 हजार 800 करोड़ रूपये का भुगतान

कृषि मंत्री श्री कटारिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पिछले साढे तीन वर्षों में अनावृष्टि, अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए 149 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को तकरीबन 15 हजार 800 करोड़ रूपये का फसल बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं। फसल बीमा क्लेम में खरीफ 2021 में 39 लाख 56 हजार तथा रबी 2021-22 में 25 लाख कृषक बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया है।

कृषि मंत्री श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 में गांव-गांव में कैम्प लगाकर पॉलिसी वितरित करने के निर्णय लिया गया था।
इसकी प्रशंसा करते हुए केन्द्र सरकार ने भी पूरे देश में फसल पॉलिसियां वितरण करने के लिये एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का नाम "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" ('Meri Policy Mere Haath' Campaign) है। उन्होंने बताया कि 2022 खरीफ में कुल 284 वाहनों के माध्यम से राज्य के सभी गाँव और तहसीलों में किसानों को फसल बीमा की जानकारियां दी जायेंगी।

इसी अभियान के तहत सभी जिलों कलेक्टरों द्वारा 204 फसल बीमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बीमा रथ के माध्यम से किसानों को सरल भाषा में पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा। वहीँ किसान पाठशाला के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अभियान के दौरान 1 से 31 जुलाई तक किसानों को बीमा राशि, बीमित फसलों के प्रकार तथा कुल बीमित क्षेत्र आदि की जानकारी दी जाएगी।

ऑर्गेनिक मार्केट के शुरुआत के ही दिनों में लोगों की काफी भीड़ यहां जुटने लगी है. आश्चर्य ये है कि बाजार में बिक्री शुरू होने के कुछ घंटों में ही काउंटर खाली हो जा रहे हैं.

श्रीनगर: हर जगह इस समय जैविक खाद्य पदार्थ या आम भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक फूड (Organic Food) की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. इसी कारण कश्मीर कृषि विभाग ने ऑर्गेनिक फूड की मांग को देखते हुए श्रीनगर में ऑर्गेनिक बाजार की शुरुआत की है, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां और फल बेचे जा रहे हैं.

यह बाजार कृषि कार्यालय में लगाया जा रहा है और शुरुआत के ही दिनों में यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी है. आश्चर्य की बात यह है कि बाजार में बिक्री शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर ही काउंटर खाली हो जाते हैं.

साधारण खेत को ऑर्गेनिक बनाने में लगता है 3 साल का समय

कश्मीर के कृषि कहते हैं कि हमने तीन साल पहले खेतो को ऑर्गेनिक करने का कार्यक्रम शुरू किया था. उन्होंने बताया कि किसी भी साधारण खेत को ऑर्गेनिक रूप में बदलने के लिए लगभग तीन साल का समय लग जाता है तब जा कर चौथे वर्ष में उस खेत को ऑर्गेनिक माना जाता है.

ऑर्गेनिक खेती से किसानों को मिल रहा है बेहतर लाभ

किसान जावेद अली कहते हैं कि हम फसलों को उगाने के लिए किसी भी तरह का केमिकल, फर्टिलायजर उपयोग नहीं करते हैं. महंगी खाद की जगह हम इसमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं और इसका हमें बेहतर लाभ भी मिलता है. उन्होंने बताया कि फल और सब्जियों की बिक्री कर के वो रोजाना लगभग 500 रुपये तक कमा लेते हैं.

कश्मीर में 1100 हेक्टर भूमि है ऑर्गेनिक खेती के लिए उपलब्ध

कश्मीर में अभी तक 1100 हेक्टर भूमि ऑर्गेनिक खेती के लिए उपलब्ध है, जिसमें 300 हेक्टर को सर्टिफाइड किया गया है. कश्मीर कृषि विभाग को यह उमीद है की ऑर्गेनिक खेती कश्मीर में किसानों को नई दशा और दिशा के साथ बुलंदियों तक ले जाएगी.की जानकारियां दी जायेंगी।

खुले में घूम रहे गोवंश किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान खुले में घूम रहे गोवंश की समस्या से जूझ रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके तहत ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर नंदीशालाएं (गौशाला) बनाई जाएंगी। जिससे किसानों की फसल को खुले में घूमने वाले पशुओं के नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को नंदीशालाएं बनाने के लिए 48 हजार रुपये देने जा रही है।

20 बीघा की जगह अब 10 बीघा खेत की जरुरत

राजस्थान सरकार ने नंदीशालाएं बनाने के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब किसान को 20 बीघा की जगह 10 बीघा खेत में ही नंदीशालाएं खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इन नंदीशालाओं का संचालन ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

अपाहिज व अंधे गोवंश के भरण पोषण को अतिरिक्त अनुदान

जो किसान अपनी नंदीशाला में अपाहिज व अंधे गोवंश की सेवा करेंगे, सरकार ने उनके लिए अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था बनाई है। अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था एवं अतिरिक्त अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।

किसानों को तारबंदी की मिली है छूट

नंदीशालाओं के संचालन के बाद भी यदि निराश्रित और खुले में घूम रहे गोवंश से फसल को नुकसान हो रहा है, तो किसान स्वंय ही अपने खेत की तारबंदी कर सकते हैं। जिन किसानों के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है, तो उन किसानों को तारबंदी के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। अधिक भूमि वाले किसान अपने ही खर्चे पर तारबंदी कर सकते हैं।

भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क बनाने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (United Arab Emirates – UAE) ने 2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को I2U2 की बैठक में भारत में निवेश से जुड़ी जानकारी प्रकाश में आई। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट के जरिये इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलप की जाएगी।

अव्वल तो यह I2U2 की बैठक क्या है, मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) क्या है, इसके क्या फायदे हैं, भारत में वर्तमान में इस संदर्भ में क्या स्थिति है, इन सवालों के जानिये जवाब मेरीखेती पर।

संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलपमेंट से जुड़े निवेश के बारे में बयान I2U2 की संयुक्त बैठक में दिया गया।

गौरतलब है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के पीएम यायर लापिड (Yair Lapid) और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हैं। इस सम्मेलन में ये लीडर्स संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं पर चर्चारत हैं।

I2U2 का अर्थ

आईटूयू2 (I2U2) भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई द्वारा मिलकर बनाया गया एक समूह है। दरअसल, I2U2 नाम में आई-2 का मतलब इंडिया (भारत) और इस्राइल से, जबकि यू-2 का उपयोग यूएस और यूएई के लिए किया गया है।

I2U2 समूह की अवधारणा विगत 18 अक्टूबर को चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई थी। गौरतलब है कि बीते तीन सालों में भारत के संबंध समूह के अन्य तीन देशों के साथ मजबूत हुए हैं। समूह 12U2 का प्रमुख उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं फूड सिक्योरिटी अर्थात खाद्य सुरक्षा जैसे छह क्षेत्रों में मिलकर निवेश एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा एवं मदद देना है। इस I2U2 वर्चुअल सम्मेलन में प्रमुख चर्चा का विषय यूक्रेन-रूस गतिरोध, वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा का संकट हैं।

मेगा फूड पार्क (MEGA FOOD PARK) किसे कहते हैं ?

मेगा फूड पार्क में एग्री प्रोडक्ट्स (कृषि उत्पाद) के भंडारण और उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था रहती है। इस व्यवस्था तंत्र में इन प्रॉडक्ट्स की प्रोसेसिंग के जरिये इनका मूल्य संवर्धन किया जाता है। इसके लिए व्यवस्थित तंत्र के तहत कच्चे माल को उच्च क्वालिटी की ऊंची कीमत वाले उत्पादों में बदला जाता है।

यानी मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार वह व्यवस्थित तंत्र है, जिसमें खेत की फसलों के भंडारण के साथ ही उससे तैयार उत्पादों के भंडारण और उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उन्हें बाजार उपलब्ध कराने तक की सारी व्यवस्था निहित है।
मौजूदा तौर पर भारत में किसान और किसानी हित में लागू मंडी क्रय-विक्रय व्यवस्था के मुकाबले यह तंत्र इसलिए सफल कहा जा सकता है क्योंकि, इसमें फसल के उच्चतम उपभोग से लेकर उसके उचित एवं उच्चतम दाम प्राप्त करने का सार भी समाहित है। किसानों को उपज की सही कीमत मिले, बाजार को जरूरी प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट्स मिले, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया था। वर्तमान में, देश में 22 मेगा फूड पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री पटेल ने दी जानकारी

संसद में शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) ने देश में स्वीकृत 38 मेगा फूड पार्कों को दी गई अंतिम मंजूरी के बारे में जानकारी प्रदान की।

फूड पार्कों में 6.66 लाख रोजगार सृजित

केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल का जवाब में बताया कि, एक मेगा फूड पार्क से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर 5 हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन होता है। यहां यह ध्यान रहे कि बिजनेस प्लान के आधार पर प्रोजेक्ट्स में सृजित रोजगार संख्या भिन्न भी हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में संचालित 22 मेगा फूड पार्कों से लगभग 6,66,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य सभा में लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि, ये 22 मेगा फूड पार्क- असम, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में संचालित किए जा रहे हैं।

मेगा फूड पार्क में उपलब्ध व्यवस्थाएं

मेगा फूड पार्क एक ऐसा बड़ा तंत्र है जहां कृषि उत्पादित फसल (एग्री प्रॉडक्ट्स), फल-सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होती है। यहां इन प्रॉडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रॉडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही इन मेगा फूड पार्क का सड़क, रेल एवं जल मार्ग से जुड़ने का भी बेहतर नेटवर्क होता है। यहां निर्मित वस्तुओं को कम समय में देश के अन्य राज्यों के साथ ही निर्यात के तौर पर विदेशों तक अल्प समय में पहुंचाया जा सकता है।

किसानों को मिलने वाले फायदे

कृषि उत्पादित फसल के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में फल-सब्जियों के सड़ने का खतरा रहता है। मेगा फूड पार्क में एग्री प्रॉडक्ट्स के भंडारण की व्यवस्था के साथ ही प्रोसेसिंग तंत्र की सुलभता के कारण फल-सब्जियों के सड़ने के बजाए, कीमत बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

कच्चे माल के सुरक्षित भविष्य के कारण किसान, उद्योग, व्यापारी के मुनाफे के साथ ही जिले एवं राज्य के राजस्व में भी सकारात्मक वृद्धि होती है।

फल-सब्जियों जैसी फसलों की प्रोसेसिंग के विकल्प न होने से, दूरदराज तक भेजने के चक्कर में व्यापारी व किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे में जिन राज्यों, जिलों में किसी फसल की यदि प्रधानता है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो फसल सड़ने से बचेगी, किसान का भला होगा, व्यापारी भी नुकसान से बच जाएगा।
इसे टमाटर से समझा जा सकता है, अल्प काल तक खाद्य योग्य टमाटर उत्पादित क्षेत्र में, टोमैटो सॉस बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट यदि विकसित की जाए, तो किसान व किसानी सभी का कल्याण होगा।

काम करने का तंत्र

मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) करती है। जो संस्था अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत कॉरपोरेट निकाय है। राज्य सरकार, राज्य सरकार की संस्थाओं एवं सहकारिताओं को मेगा फूड पार्क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पृथक रूप से एसपीवी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

यहां संचालित हो रहे मेगा फूड पार्क

प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार संचालित किए जा रहे 22 मेगा फूड पार्क इस प्रकार हैं :

1. स्रीनी मेगा फूड पार्क, चित्तूर, आंध्र प्रदेश
2. गोदवारी मेगा एक्वा पार्क, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश
3. नॉर्थ इस्ट मेगा फूड पार्क, नलबाड़ी, असम
4. इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, रायपुर, छत्तीसगढ़
5. गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क, सूरत, गुजरात
6. क्रेमिका मेगा फूड पार्क, ऊना, हिमाचल प्रदेश
7. इंटिग्रेटेड मेगा फूड पार्क, तुमकुर, कर्नाटक
8. केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (KINFRA) मेगा फूड पार्क, पलक्कड़, केरल
9. इंडस मेगा फूड पार्क, खरगौन, मध्य प्रदेश
10. अवंती मेगा फूड पार्क, देवास, मध्य प्रदेश
11. पैथन मेगा फूड पार्क, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
12. सतारा मेगा फूड पार्क, सतारा, महाराष्ट्र
13. ज़ोरम मेगा फ़ूड पार्क, कोलासिब, मिज़ोरम
14. एमआईटीएस मेगा फूड पार्क, रायगढ़, ओडिशा
15. इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क, फज्जिलका, पंजाब
16. सुखजीत मेगा फूड पार्क, कपूरथला, पंजाब
17. ग्रीनेटक मेगा फूड पार्क, अजमेर, राजस्थान
18. स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क, निजामाबाद, तेलंगाना
29. त्रिपुरा मेगा फूड पार्क, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा
20. पतंजली फूड एंड हर्बल पार्क, हरिद्वार, उत्तराखंड
21. हिमालयन मेगा फूड पार्क, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड
22. जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल।

भारत में यूएई द्वारा इन्वेस्ट की जा रही बड़ी राशि से निश्चित ही उम्मीद की जा सकती है कि, इससे I2U2 के उद्देश्य पूरे होंगे और भारत के कृषि उत्पादन, विनिर्माण एवं बाजार तंत्र में कसावट आने से उचित परिणाम मिलेंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव में डबल हुई 75000 किसानों की आय का ब्यौरा तैयार – केंद्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले साल तय अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया है।

परिषद ने पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव में किसानों की सफलता का दस्तावेजीकरण करने का टारगेट तय किया था। इस वर्ग में ऐसे कृषक मित्र शामिल हैं जिनकी आय दोगुनी हुई है या फिर इससे ज्यादा बढ़ी है। परिषद के अनुसार ऐसे 75 हजार किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण कर किसानों का ब्यौरा जारी किया गया है।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आय बढ़ने वाले लाखों किसानों में से 75 हजार किसानों के संकलन का एक ई-प्रकाशन तैयार कर उसे जारी किया गया।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने किया विमोचन

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समारोह में कहा कि, देश में कृषि क्षेत्र एवं कृषक मित्रों का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों के समन्वित प्रयास के साथ ही जागरूक किसान भाईयों के सहयोग से किसान की आय में वृद्धि हुई है। परिषद ने 'डबलिंग फार्मर्स इनकम' पर राज्य आधारित संक्षिप्त प्रकाशन भी तैयार किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विमोचन अवसर पर ई-बुक को जारी किया।

पुरस्कार से नवाजा

कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 94वें स्थापना दिवस पर मंत्री तोमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिकों व किसानों को पुरस्कृत भी किया। पूसा परिसर, दिल्ली में आयोजित समारोह में तोमर ने कहा कि, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आईसीएआर ने पिछले साल, आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे 75 हजार किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिनकी आय दोगुनी या इससे ज्यादा दर से बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि सफल किसानों का यह संकलन भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने आईसीएआर के समारोह में अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उन्होंने आईसीएआर के स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की बात इस दौरान कही।

कृषि क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे रोजगार अवसर

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि, कृषि प्रधान भारत देश में निरंतर कार्य की जरूरत है। इस क्षेत्र में आने वाली सामाजिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय चुनौतियों के नित समाधान की जरूरत भी इस दौरान बताई।

उन्होंने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के मामले में तकनीक के समन्वित इस्तेमाल का जिक्र अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गांव और गरीब-किसानों के जीवन में बदलाव आए। मंत्री तोमर ने ग्रामीण क्षेत्र में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर, कृषि का मुनाफा बढ़ाने के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के कार्यों पर इस दौरान प्रकाश डाला।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से की जा रही फंडिंग

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नव रोजगार सृजन के लिए हितग्राही योजनाएं लागू कर उचित फंडिंग की जा रही है। ग्रामीण नागरिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर कृषि में रोजगार के ज्यादा अवसर निर्मित करने का सरकार का लक्ष्य है।

जलवायु परिवर्तन चिंतनीय

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आईसीएआर की स्थापना के 93 साल पूर्ण होने के साथ ही वर्ष 1929 में इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक संस्थान द्वारा जारी की गईं लगभग 5,800 बीज-किस्मों पर गर्व जाहिर किया। वहीं इनमें से वर्ष 2014 से अभी तक 8 सालों में जारी की गईं लगभग दो हजार किस्मों को उन्होंने अति महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन की स्थिति को चिंतनीय कारक बताकर कृषि वैज्ञानिकों, साथियों से इसके सुधार की दिशा में रोडमैप बनाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

नई शिक्षा नीति का उदय

मंत्री तोमर ने प्रधानमंत्री की विजन आधारित नई शिक्षा नीति का उदय होने की बात कही। उन्होंने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम के समावेश में कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री तोमर ने दलहन, तिलहन, कपास उत्पादन में प्रगति के लिए आईसीएआर (ICAR) और केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)) को अपने प्रयास बढ़ाने प्रेरित किया।

समारोह के पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों से कृषि मंत्री ने ऑनलाइन तरीके से विचार साझा किए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों से हुई चर्चा में सरकारी योजनाओं, संस्थागत सहयोग से किसानों की आय में किस तरह वृद्धि हुई इस बात की जानकारी मिली।

कृषि मंत्रालय ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)(MSP), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण एवं अन्य प्रमुख विषयों पर सुझाव देने के लिए 29 सदस्यीय एक वृहद कमेटी का गठन करने की जानकारी दी है।

इन्होंने किया किनारा

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग करने वाले किसान संगठनों ने समिति में शामिल होने के लिए नाम प्रस्तावित नहीं किया है।
हालांकि इसके बाद भी सरकार ने घोषित की गई समिति में संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) के तीन सदस्यों के लिए स्थान खाली रखा है।

सचिव होंगे अध्यक्ष

यदि भविष्य में मोर्चा की तरफ से नाम आता है तो इन्हें समिति में जोड़ा जाएगा। अधिसूचित समिति द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के बारे में भी स्पष्ट किया गया है। इसके लिए तीन प्रमुख विषयों को स्पष्ट किया गया है। बताया गया है कि इस समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल करेंगे।

समिति में शामिल दिग्गज नाम

वृहद कमेटी में नीति आयोग सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री डॉ. सीएससी शेखर, आईआईएम अहमदाबाद के डॉ. सुखपाल सिंह के अलावा उन्नत किसान भारत भूषण त्यागी के नाम शामिल हैं।

किसान प्रतिनिधियों के रूप में तीन स्थान संयुक्त किसान मोर्चा के लिए खाली रखे गए हैं। अन्य किसान संगठनों में भारतीय कृषक समाज अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटिल, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश व सैय्यद पाशा पटेल का नाम दर्ज है।

समिति में इनको जगह

सहकारिता क्षेत्र से इफको चेयरमैन दिलीप संघानी, विनोद आनंद के अलावा सीएसीपी के सदस्य नवीन पी. सिंह को समिति में शामिल किया गया है।
कृषि विश्वविद्यालय व संस्थानों से डॉ. पी चंद्रशेखर, डॉ. जेपी शर्मा (जम्मू) और जबलपुर के डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन का नाम शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों में कृषि सचिव, आइसीएआर के महानिदेशक, खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव, वस्त्र सचिव और चार राज्य सरकारों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिवों की समिति में भूमिका रहेगी।

प्रभावी एमएसपी व्यवस्था बनाने देगी सुझाव

संयुक्त सचिव (फसल) को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही इसमें समिति के गठन का उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया है। समिति के गठन का उद्देश्य प्राथमिकता के तौर पर एमएसपी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। अतः समिति भारत के किसानों के हित में लागू एमएसपी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने पर अपना सुझाव देगी।

बाजार अवसर का लाभ उठाने पर फोकस

कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समिति देश और दुनिया में बदल रहे परिदृश्य के अनुसार लाभ के तरीकों पर ध्यान आकृष्ट कर अपनी राय रखेगी। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना होगा।

कौशल विकास
समिति प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के तौर तरीकों पर भी अपनी सलाह प्रदान करेगी। इसके लिए किसान संगठनों को शामिल कर इसमें मूल्य श्रृंखला विकास और भविष्य की जरूरतों के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक खेती के विस्तार पर सुझाव दिए जाएंगे।

अनुसंधान संस्थानों व कृषि विज्ञान केंद्रों को ज्ञान केंद्र बनाने और कृषि शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक खेती प्रणाली के पाठ्यक्रम और कौशल विकास की कार्यनीतियों पर भी सुझाव देना समिति की भूमिका का हिस्सा होगा।

फसल विविधीकरण
फसल विविधीकरण (क्राप डायवर्सिफिकेशन) के लिए भी समिति का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसमें समिति, उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के मध्य जरूरतों के हिसाब से समन्वय के उपाय सुझाने का कार्य करेगी।

कृषि विविधीकरण और नवीन फसलों के विक्रय के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के तरीकों पर भी समिति अपनी सलाह प्रस्तुत करेगी। यह समिति सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा के साथ इसमें सुधार एवं किसान हितैषी सुधारों को भी प्रस्तुत करेगी।प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश व सैय्यद पाशा पटेल का नाम दर्ज है।

अब खेती में भी आधुनिकीकरण के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीक और नई किस्म इस्तेमाल में लाई जा रहीं हैं। किसान भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर स्मार्ट फार्मिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। भारत में भी कृषि-विस्तार तेजी से चल रहा है।

अब जल्दी ही भारत में एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी शुरू होने जा रही है। जिससे देश के 15 से ज्यादा राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

देश में अब तक बड़े पैमाने पर खेती की जाती रही है। बाजार में भाव ज्यादा अच्छा नहीं मिल सका है। लेकिन अब सरकार ने किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार अपने ही देश मे तैयार कर दिया है।
एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी हरियाणा के गन्नौर में बनने जा रही है। जिसमें किसानों को बहुत ही जल्द फल-फूल, सब्जी और अनाजों का एकल बाजार मुहैया कराया जाएगा। इस पहल से देश के 15 से ज्यादा राज्यों के करोड़ों किसान बिना किसी तनाव के अपनी उपज बेचकर अच्छी बचत कर सकेंगे।

कब होगी एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी की शुरुआत ?

माना जा रहा है कि साल 2022 के सितंबर माह में एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी की शुरुआत होने जा रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से कृषि मंडी की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

कृषि मंडी बनाने में कितनी लागत आई है ?

हरियाणा में बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी में करीब 8 हजार करोड़ की लागत आई है। मंडी में मुख्यरूप से बागवानी फसलें जैसे फल-फूल, सब्जियों के साथ-साथ डेयरी उत्पादों को बड़ी मात्रा में खरीदा व बेचा जाएगा।

कृषि मंडी के प्रमुख उद्देश्य

1- इस कृषि बाजार को सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, रेल परिवहन और ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाओं से भी जोड़ा जायेगा।
2- बाजार के अंदर ही किसानों और मंडी में काम करने वाले लोगों के लिये ठहरने, लोडिंग वाहनों की पार्किंग, व्यापारियों के लिये सुविधाजनक दुकानें और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों का प्रबंधन भी होगा।
3- इस मंडी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार मानकों के अनुसार निर्यात के लिये भी कृषि जिंसों की खरीद-बिक्री की जायेगी।
4- करोड़ टन की क्षमता वाली इस मंडी में फल, फूल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रॉडक्ट्स का व्यापार किया जा सकेगा.
इस कृषि बाजार में मछलियों के लिए अलग से एयर कंडिशनिंग बाजार बनाया जायेगा

गोवंश पालकों के लिए खुशखबरी है। अब गोवंश का गोबर बेकार नहीं जाएगा। सात समुंदर पार भी गोवंश के गोबर को अब तवज्जो मिलेगी। अब पशुपालकों को गाय के गोबर की उपयोगिता समझनी पड़ेगी।

पहली बार देश से 192 मीट्रिक टन गोवंश का गोबर कुवैत में खेती के लिए जाएगा। गोबर को पैक करके कंटेनर के जरिए 15 जून से भेजना शुरू किया जाएगा। सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला के सनराइज ऑर्गेनिक पार्क (sunrise organic park) में इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

कुवैत में जैविक खेती मिशन की शुरुआत होने जा रही है।

भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ (Organic Farmer Producer Association of India- OFPAI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता ने बताया कि जैविक खेती उत्पादन गो सरंक्षण अभियान का ही नतीजा है। जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली खेप में 15 जून को कनकपुरा रेलवे स्टेशन से कंटेनर रवाना होंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि कुवैत के कृषि विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद फसलों के लिए गाय का गोबर बेहद उपयोगी माना गया है। इससे न केवल फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जैविक उत्पादों में स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। सनराइज एग्रीलैंड डवलेपमेंट को यह जिम्मेदारी मिलना देश के लिए गर्व की बात है।

राज्य सरकारों की भी करनी चाहिए पहल

गाय के गोबर को उपयोग में लेने के लिए राज्य सरकारों को भी पहल करनी चाहिए। जिससे खेती-किसानी और आम नागरिकों को फायदा होगा। साथ ही स्वास्थ्यवर्धक फसलों का उत्पादन होगा। प्राचीन युग से पौधों व फसल उत्पादन में खाद का महत्वपूर्ण उपयोग होता हैं। गोबर के एंटीडियोएक्टिव एवं एंटीथर्मल गुण होने के साथ-साथ 16 प्रकार के उपयोगी खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। गोबर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सभी राज्य सरकारों को इसका फायदा लेना चाहिए।

गाय के गोबर का उपयोग

प्रोडक्ट विवरण पारंपरिक भारतीय घरों में गाय के गोबर के केक का उपयोग यज्ञ, समारोह, अनुष्ठान आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसे घी के साथ जलते समय ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कहा जाता है। गाय के गोबर को उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
इस कृषि बाजार में मछलियों के लिए अलग से एयर कंडिशनिंग बाजार बनाया जायेगा

NEW HOLLAND AGRICULTURE

1- बायोगैस, गोबर गैस : गैस और बिजली संकट के दौर में गांवों में आजकल गोबर गैस प्लांट लगाए जाने का प्रचलन चल पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, कोयला व गैस तो सब प्राकृतिक स्रोत हैं, किंतु यह बायोगैस तो कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। जब तक गौवंश है, अब तक हमें यह ऊर्जा मिलती रहेगी। एक प्लांट से करीब 7 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है जिससे करीब साढ़े 3 करोड़ पेड़ों को जीवनदान दिया जा सकता है। साथ ही करीब 3 करोड़ टन उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड को भी रोका जा सकता है।

2- गोबर की खाद : गोबर गैस संयंत्र में गैस प्राप्ति के बाद बचे पदार्थ का उपयोग खेती के लिए जैविक खाद बनाने में किया जाता है। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता था। इसी अमृत के कारण भारत भूमि सहस्रों वर्षों से सोना उगलती आ रही है। गोबर फसलों के लिए बहुत उपयोगी कीटनाशक सिद्ध हुए हैं। कीटनाशक के रूप में गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के लिए अनुसंधान केंद्र खोले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बिना खेतिहर उत्पादन बढ़ाने की अपार क्षमता है। इसके बैक्टीरिया अन्य कई जटिल रोगों में भी फायदेमंद होते हैं।

3- गौमूत्र अपने आस-पास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। कृषि में रासायनिक खाद्य और कीटनाशक पदार्थ की जगह गाय का गोबर इस्तेमाल करने से जहां भूमि की उर्वरता बनी रहती है, वहीं उत्पादन भी अधिक होता है। दूसरी ओर पैदा की जा रही सब्जी, फल या अनाज की फसल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जुताई करते समय गिरने वाले गोबर और गौमूत्र से भूमि में स्वतः खाद डलती जाती है।

4- कृषि में रासायनिक खाद्य और कीटनाशक पदार्थ की जगह गाय का गोबर इस्तेमाल करने से जहां भूमि की उर्वरता बनी रहती है, वहीं उत्पादन भी अधिक होता है। दूसरी ओर पैदा की जा रही सब्जी, फल या अनाज की फसल की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जुताई करते समय गिरने वाले गोबर और गौमूत्र से भूमि में स्वतः खाद डलती जाती है।

5- प्रकृति के 99% कीट प्रणाली के लिए लाभदायक हैं। गौमूत्र या खमीर हुए छाछ से बने कीटनाशक इन सहायक कीटों को प्रभावित नहीं करते। एक गाय का गोबर 7 एकड़ भूमि को खाद और मूत्र 100 एकड़ भूमि की फसल को कीटों से बचा सकता है। केवल 40 करोड़ गौवंश के गोबर व मूत्र से भारत में 84 लाख एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है।

6- गाय के गोबर का चर्म रोगों में उपचारीय महत्व सर्वविदित है। प्राचीनकाल में मकानों की दीवारों और भूमि को गाय के गोबर से लीपा-पोता जाता था। यह गोबर जहां दीवारों को मजबूत बनाता था वहीं यह घरों पर परजीवियों, मच्छर और कीटाणुओं के हमले भी रोकता था। आज भी गांवों में गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने, आंगन लीपने एवं मंगल कार्यों में लिया जाता है।

7- गोबर के कंडे या उपले : वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के गोबर में विटामिन बी-12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है। आम मान्यता है कि गाय के गोबर के कंडे से धुआं करने पर कीटाणु, मच्छर आदि भाग जाते हैं तथा दुर्गंध का नाश हो जाता है। कंडे पर रोटी और बाटी को सेंका जा सकता है।

8- गोबर का पाउडर के रूप में खजूर की फसल में इस्तेमाल

सत्ता हांसिल करने के लिए नेता तरह-तरह की सियासी गोटियां बिछाते हैं। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बातें भी किसानों की होती हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद नेताओं के बोल कैसे बदल जाते हैं। फिर वही नेता किसान हितों को भूलकर अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

ताजा मामला मध्यप्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। यहां की सरकार ने किसानों के लिए सोयाबीन बीज की कीमतों में 2600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके 2000 की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यानि कि पहले 2600 रूपए जमा कराए जाएंगे, फिर 2000 रु. वापिस मिलेंगे। यह वापिस कब मिलेंगे यह भी निर्धारित नहीं किया गया है।

ऐसे में किसानों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ छलावा कर रही है अथवा मजाक। सरकार के इस फैसले से किसानों में रोष है। किसानों के साथ ही यह सीधे तौर पर छलावा ही है।

आम तौर पर जब सोयाबीन बेची जाती है तो पांच हजार से छह हजार के बीच भाव रहता है। छह हजार का भाव भी इस बार सालों बाद आया है। अब उसी सोयाबीन को फिल्टर कर 10 हजार 100 रुपए क्विंटल में यहां बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे खेती लाभ का धंधा बन पाएगी? किसानों का कहना है कि हमसे खरीदते समय किसी को भाव बढ़ाने की याद नहीं आती, अब जब बोवनी की जाना है तो स्वत: ही भाव बढ़ा दिए गए।

बीज प्राप्ति की रसीद व पावती नहीं मिलेगी

सरकार द्वारा सोयाबीन बीज की कीमतों में वृद्धि और सब्सिडी देने वाले प्रावधान में एक निर्णय और लिया गया है। इसके तहत बीज प्राप्त करने वाले किसान को न कोई रसीद दी जाएगी और न ही पावती प्रति मिलेगी। जिससे किसान समय पर अपना तर्क रख सकें।

सोयाबीन की ये वैरायटी उपलब्ध हैं

सोयाबीन बीज की दो वैरायटी कृषि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

1- 2034- SOYA
2- 9560- SOYA

इस प्रकार तय हुए हैं सोयाबीन बीज के रेट

प्लांट पर सोयाबीन के 7500 प्रति क्विंटल
– किसानों के लिए 10100 रुपए प्रति क्विंटल
– 2000 रुपए सब्सिडी
सोयाबीन प्रति बीघा खेत में 20 से 25 किलो बीघा के हिसाब से डाली जाती है।

बढ़ती महंगाई का असर अब कीटनाशक दवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। कीटनाशक दवाओं पर म्हंगैबक चलते किसान वाशिंग पाउडर का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने को मजबूर हैं।

इन दिनों मूंग और उड़द की फसल लहलहा रही है। लेकिन कीट-पतंगे फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कीड़े और गिडार फसल को खा रहीं हैं। कीटनाशक दवाओं मूल्यों पर अचानक हुई वृद्धि से किसान परेशान हैं। मजबूरन किसान कीटनाशक की जगह पानी में वाशिंग पाउडर का घोल बनाकर मूंग व उड़द की फसल पर छिड़काव कर रहे हैं।

गांव हसनपुर निवासी किसान ललित चौधरी व दीपू फौजदार बताते हैं कि उन्होंने अपने खेत में मूंग कि उड़द की फसल बो रखी है। फसल को कीड़े व गिडार कहा रहे हैं। कीटनाशक दवाओं के रेट अचानक बढ जाने के कारण पानी में वाशिंग पाउडर का घोल बनाकर छिड़काव कर रहे हैं। हालांकि इसका असर कम ही दिखाई दे रहा है।

क्या कहते हैं दुकानदार

विकास कीटनाशक भंडार कोलाहर के दुकानदार मनोज चौधरी ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कीटनाशक दवाओं के रेट महंगे हुए हैं। बीते दो महीने में कीटनाशक दवाओं के रेट दोगुने तक हो गए हैं।

"मौसम काफी गर्म है ऐसे में फसल पर वाशिंग पाउडर के घोल का छिड़काव फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। किसानों को कोराजिन व मार्शल लिक्विड का छिड़काव करना चाहिए। जो सस्ता व कारगर साबित होगा।"
– एसडीओ कृषि, सुबोध कुमार सिंह

इन गांवों के किसान हैं प्रभावित

हसनपुर, ईखू, मसंदगढ़ी, पालखेड़ा, रायकरनगढ़ी, भूरेखा, मरहला, नावली, सामंतागढ़ी सहित कई गांवों के किसानों की फसल कीट-पतंगों से प्रभावित हो रहीं हैं।

इतीन महीने पहले की कीमत

– एक्सल की मीरा 71 100 ML की कीमत 60 रुपए थी, जो अब 130 रुपए है।
– नागार्जुना 65 रुपए कीमत थी जो अब 125 रुपए हो गई है

एक एकड़ में 60 एमएल कोराजिन दवा का छिड़काव होता है। जिसकी कीमत 850 रुपए है।

MERIKHETI

MASSEY FERGUSON

9500E

50 HP

आकर्षक ऑफर्स के लिए क्लिक करें

Mahabali RX 42

सबसे कम डीजल में
सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार

42 HP

MERIKHETI

SONALIKA
LEADING AGRI EVOLUTION

औषधीय खेती

तमाम औषधीय गुणों में निपुण है करी-पत्ता का पौधा

सब्जियों में अक्सर दिखने वाला वो पत्ता जो खाने को स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देता है। इसे कढ़ी पत्ता या मीठी नीम की पत्तियां भी कही जाती हैं क्यूंकि इसकी पत्तियां देखने में कड़वे नीम की पत्तियों से मिलती-जुलती हैं। करी-पत्ता के पौधे को घर के गमले में लगाना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ते ही इसके पत्तों को सब्जियों में डाल दें। सभी प्रकार की सब्जियों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

गमले से बाहर भी लगा सकते हैं करी-पत्ता का पौधा

जरूरी नहीं है कि करी-पत्ता का पौधा आप गमले में ही लगाएं। करी-पत्ता के पौधे को सीडलिंग के तौर पर किसी गहरे व छोटे साइज वाले कंटेनर में लगाएं। इसके बाद आप इन्हें अच्छे से जर्मिनेट करें। और 7-8 दिन बाद ये बीज ये बीज जर्मिनेट होने लगेंगे। इसके बाद आप इसमें सामान्य पानी डालकर भी विकसित कर सकते हैं। घर में पौधा उगाने के यह तरीका बहुत ही अच्छा है।

गमले में कैसे लगाएं करी-पत्ता का पौधा

■ आप इसे सीधे गमले में लगा सकते हैं। पहले आप तीन-चार बीज एक साथ ग्रो करें। सिर्फ एक ही बीज से नहीं बल्कि अच्छी पत्तियों वाला पौधा कई सारे बीज एक साथ लगाने पर ही उगता है।साथ में अगर खाद की उचित व्यवस्था हो तो वो भी मिट्टी में मिलाएं, नहीं तो मिट्टी और थोड़ी सी रेत मिलाकर इस पौधे को लगाएं। आप थोड़ा सा सूखा गोबर भी खाद की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।

■ करीब 45 दिन बाद आप देखेंगे कि ये पौधा कितनी अच्छी तरह से उग गया है। अब आप इसमें अच्छे से खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालें। आप घर में बनाई हुई खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां हवा और धूप अच्छे से दिख रही हो।

■ बीस दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां आने लगी हैं। इन्हें आप अभी गमले में शिफ्ट कर सकती हैं। अगर सीधे गमले में लगाया है तो आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस इसे दो हफ्ते में एक बार खाद और रोज़ थोड़ा सा पानी देते रहिए।

करी-पत्ता को सब्जियों डालने के फायदे

1- करी पत्ता में पर्याप्त मात्रा में विटामिन A होता है। विटामिन A आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से आंखों की रोशनी कम होना जैसी कई समस्या हो सकती है। तो विटामिन A की कमी को पूरा करने के लिए भी आपको करी पत्ते का सेवन करना चाहिए।

2- करी पत्ते में आयरन तथा फोलिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। इसलिए यह शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है।

3- करी पत्ते में बालों को मॉइश्चराइजिंग करने वाले कई गुण मौजूद होते हैं। जो बालों को गहराई से साफ करते हैं और इन्हें बढ़ाने के साथ-साथ मजबूत भी बनाते हैं। करी पत्ते की सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर तिल या नारियल के तेल में मिला लें, फिर इस तेल को थोड़ा गर्म करके सिर में मसाज करें। इसे रातभर रखें और फिर सुबह शेंपू कर लें। इस प्रकार मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे और वह मजबूत भी होंगे।

4- करी पत्ता के पौधे में औषधीय गुण होते हैं। करी पत्ता लीवर को सशक्त बनाता है। यह लीवर को बैक्टीरिया तथा वायरल इंफेक्शन से बचाता है। इसके अलावा यह फ्री रेडिकल्स, हेपेटाइटिस, सिरोसिस जैसी कई बीमारियों से भी बचाता है।

हल्दी (HALDI (TURMERIC)) का मसाला फसलों में विशेष स्थान है. अपने औषधिय गुणों के कारण इसकी अलग पहचान है. हल्दी से रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की इम्युनिटी बढ़ती है. कोरोना काल में घरेलु इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े के अलावा हल्दी को औषधी के रूप में काफी उपयोग किया गया था.

इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में, पेट दर्द व एंटीसेप्टिक व चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है. यह रक्त शोधक होती है. चोट सूजन को ठीक करने का काम कच्ची हल्दी करती है. जीवाणु नाशक गुण होने के कारण इसके रस का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी होता है. प्राकृतिक एवं खाद्य रंग बनाने में भी हल्दी का उपयोग होता है।

हल्दी का धार्मिक महत्व भी है. हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है. तांत्रिक पूजा में भी महत्व बताया गया है. इसी कारण से हल्दी की बाजार में बहुत मांग रहती है और अच्छे भाव मिलते हैं. खरीफ सीजन में अन्य फसलों के साथ हल्दी की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. हल्दी को खेत की मेड़ों पर भी लगाया जा सकता है.

हल्दी के प्रकार

हल्दी दो प्रकार की होती है, पीली हल्दी और काली हल्दी.

पीली हल्दी का प्रयोग मसालों के रूप में सब्जी बनाने में किया जाता है, वहीं काली हल्दी का प्रयोग पूजन में किया जाता है.

हल्दी की उन्नत किस्में

आर एच 5

आर एच 5 किस्म के हल्दी के पौधे की ऊँचाई करीब ८० से १०० सेंटीमीटर होती है। इसके तैयार होने में करीब २१० से २२० दिन लगते है. इसकी पैदावार २०० से २२० क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है.

राजेंद्र सोनिया

इसके पौधे की ऊंचाई ६० से ८० सेंटीमीटर होती है. फसल तैयार होने में १९५ से २१० दिन लगता है. १६० से १८० क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से उपज प्राप्त की जा सकती है।

पालम पीताम्बर

यह अधिक पैदावार देने वाली हल्दी की किस्मों में से एक है. गहरे पीले रंग के इसके कांड होते हैं. इस किस्म से १३२ क्विंटल/एकड़ तक उपज प्राप्त की जा सकती है.

सोनिया

इसके तैयार होने में २३० दिन का समय लगता है. इससे उपज ११० से ११५ क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है.

सुगंधम

सुगंधम किस्म २१० दिनों में तैयार हो जाती है और करीब ८० से ९० क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. इसके कंद आकर में लंबे और हल्की लाली लिए हुए पीले रंग के होते हैं.

सोरमा

सोरमा किस्म की हल्दी के कंद अंदर से नारंगी रंग के होते हैं. यह २१० दिन में तैयार हो जाता है. इस किस्म से प्रति एकड़ करीब ८० से ९० क्विंटल तक उपज प्राप्त हो सकती है.

सुदर्शन

इसके कंद आकर में छोटे होते हैं. १९० दिनों बाद इसकी खुदाई की जा सकती है.

अन्य किस्में

हल्दी की कई ओर उन्नत किस्में भी होती हैं. जिनमें सगुना, रोमा, कोयंबटूर, कृष्णा, आर. एच 9/90, आर.एच- 13/90, पालम लालिमा, एन.डी.आर 18, बी.एस.आर 1, पंत पीतम्भ आदि किस्में शामिल हैं.

गमले में कैसे लगाएं करी-पत्ता का पौधा

आप इसे सीधे गमले में लगा सकते हैं। पहले आप तीन-चार बीज एक साथ ग्रो करें। सिर्फ एक ही बीज से नहीं बल्कि अच्छी पत्तियों वाला पौधा कई सारे बीज एक साथ लगाने पर ही उगता है।साथ में अगर खाद की उचित व्यवस्था हो तो वो भी मिट्टी में मिलाएं, नहीं तो मिट्टी और थोड़ी सी रेत मिलाकर इस पौधे को लगाएं। आप थोड़ा सा सूखा गोबर भी खाद की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।

करीब 45 दिन बाद आप देखेंगे कि ये पौधा कितनी अच्छी तरह से उग गया है। अब आप इसमें अच्छे से खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालें। आप घर में बनाई हुई खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां हवा और धूप अच्छे से दिख रही हो।

बीस दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां आने लगी हैं। इन्हें आप अभी गमले में शिफ्ट कर सकती हैं। अगर सीधे गमले में लगाया है तो आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस इसे दो हफ्ते में एक बार खाद और रोज़ थोड़ा सा पानी देते रहिए।

बुवाई का तरीका

15 मई से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी की बुआई की जा सकती है. सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर हल्दी की बुआई अप्रैल, मई माह में भी की जा सकती है.

करीबन 2500 किलोग्राम प्रकंदों की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए होती है.
बुआई से पहले हल्दी के कंदों को बोरे में लपेट कर रखने से अंकुरण आसानी से होता है.
बुआई के लिए मात्र कंद एवं बाजू कंद प्रकंद का उपयोग किया जा सकता है.
ध्यान रहे की प्रत्येक प्रकंद पर दो या तीन ऑखें हों.
बुआई से पहले कंदों को 0.25 प्रतिशत एगालाल घोल में 30 मिनट तक उपचार करना चाहिए.
हल्दी की बुआई समतल चार बाई तीन मीटर आकार की क्यारियों में मेड़ों पर करना चाहिए.
लाइन से लाइन की दूरी 45 से.मी. व पौधों से पौधों की दूरी 25 से.मी. रखें.
रेतीली भूमि में इसकी बुआई 7 से 10 से.मी. ऊंची मेड़ों पर करनी चाहिए.

रंगबिरंगी तितली किसके मन को नहीं भाती, लेकिन हम बात कर रहे हैं, प्रमुख दलहनी फसलों में से एक तितली मटर के बारे में। आमतौर पर इसे अपराजिता (BUTTERFLY PEA, BLUE PEA, APRAJITA, CORDOFAN PEA, BLUE TEA FLOWERS OR ASIAN PIGEONWINGS) भी कहा जाता है।

इंसान और पशुओं के लिए गुणकारी

बहुउद्देशीय दलहनी कुल के पौधों में से एक तितली मटर यानी अपराजिता की पहचान उसके औषधीय गुणों के कारण भी दुनिया भर में है। इंसान और पशुओं तक के लिए गुणकारी इस फसल की खेती को बढ़ावा देकर, किसान भाई अपनी कमाई को कई तरीके से बढ़ा सकते हैं।
लाइन से लाइन की दूरी 45 से.मी. व पौधों से पौधों की दूरी 25 से.मी. रखें.
रेतीली भूमि में इसकी बुआई 7 से 10 से.मी. ऊंची मेड़ों पर करनी चाहिए.

ब्लू टी की तैयारी

तितली मटर के फूल की चाय (BUTTERFLY PEA FLOWER TEA)

बात औषधीय गुणों की हो रही है तो आपको बता दें कि, चिकित्सीय तत्वों से भरपूर अपरजिता यानी तितली मटर के फूलों से अब ब्लू टी बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

ब्लू टी से ब्लड शुगर कंट्रोल

जी हां परीक्षणों के मुताबिक तितली मटर (अपराजिता) के फूलों से बनी चाय की चुस्की, मधुमेह यानी कि डायबिटीज पीड़ितों के लिए मददगार होगी। जांच परीक्षणों के मुताबिक इसके तत्व ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं।

पशुओं का पोषक चारा

इंसान के स्वास्थ्य के लिए मददगार इसके औषधीय गुणों के अलावा तितली मटर (अपराजिता) का उपयोग पशु चारे में भी उपयोगी है।
चारे के रूप में इसका उपयोग भूसा आदि अन्य पशु आहार की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं पाचन शील माना जाता है।
तितली मटर (अपराजिता) के पौधे का तना बहुत पतला साथ ही मुलायम होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी और अधिक संख्या में होने से पशु आहार के लिए इसे उत्तम माना गया है।

एशिया और अफ्रीका में उत्पत्ति

तितली मटर (अपराजिता) की खेती की उत्पत्ति का मूल स्थान मूलतः एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र एवं अफ्रीका में माना गया है। इसकी खेती की बात करें तो मुख्य रूप से अमेरिका, अफीका, आस्ट्रेलिया, चीन और भारत में इसकी किसानी का प्रचलन है।

मददगार जलवायु

■ इसकी खेती मुख्यतः प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों में प्रचलित है। मध्यम खारी मृदा इलाकों में इसका पर्याप्त पोषण होता है।
■ तितली मटर प्रतिकूल जलवायु जैसे–सुखा, गर्मी एवं सर्दी में भी विकसित हो सकती है।
■ ऐसी मिट्टी, जिनका पी–एच मान 4.7 से 8.5 के मध्य रहता है में यह भली तरह विकसित होने में कारगर है।
■ मध्यम खारी मिट्टी के लिए भी यह मित्रवत है।
■ हालांकि जलमग्न स्थिति के प्रति यह बहुत संवेदनशील है। इसकी वृद्धि के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सेहतकारी माना जाता है।

तितली मटर के बीज की अहमियत

कहावत तो सुनी होगी आपने, बोए बीज बबूल के तो फल कहां से होए। ठीक इसी तरह तितली मटर (अपराजिता) की उन्नत फसल के लिए भी बीज अति महत्वपूर्ण है। कृषक वर्ग को इसका बीज चुनते समय अधिक उत्पादन एवं रोग प्रतिरोध क्षमता का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए।

तितली मटर की कुछ उन्नत किस्में

तितली मटर की उन्नत किस्मों की बात करें तो काजरी–466, 752, 1433, जबकि आईजीएफआरआई की 23–1, 12–1, 40 –1 के साथ ही जेजीसीटी–2013–3 (बुंदेलक्लाइटोरिया -1), आईएलसीटी–249 एवं आईएलसीटी-278 इत्यादि किस्में उन्नत प्रजाति में शामिल हैं।

तितली मटर की बुवाई के मानक

अनुमानित तौर पर शुद्ध फसल के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम मानी गई है। मिश्रित फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम, जबकि 4 से 5 किलोग्राम बीज स्थायी चरागाह के लिए एवं 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हैक्टेयर अल्पावधि चरण चरागाह के लिए आदर्श पैमाना माना गया है।
तय मान से बुवाई 20–25 × 08 – 10 सेमी की दूरी एवं ढ़ाई से तीन सेमी की गहराई पर करनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक उपचारित बीजों की भी सलाह देते हैं। अधिक पैदावार के लिए गर्मी में सिंचाई का प्रबंधन अनिवार्य है।

तितली मटर की कटाई का उचित प्रबंधन

मटर के पके फल खेत में न गिर जाएं इसलिए तितली मटर की कटाई समय रहते कर लेना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान भी रखना अनिवार्य है कि मटर की फसल परिपक्व हो चुकी हो। जड़ बेहतर रूप से जम जाए इसलिए पहले साल इससे केवल एक कटाई लेने की सलाह जानकार देते हैं।

तितली मटर के उत्पादन का पैमाना

उपज बरानी की दशा में स्थितियां अनुकूल रहने पर लगभग 1 से 3 टन सूखा चारा और 100 से 150 किलो बीज प्रति हेक्टेयर मिल सकता है।
इतनी बड़ी ही सिंचित जमीन पर सूखा चारा 8 से 10 टन, जबकि बीज पांच सौ से छह सौ किलो तक उपज सकता है।

पोषक तत्वों से भरपूर खुराक

तितली मटर में प्रोटीन की मात्रा 19-23 फीसदी तक मानी गई है। क्रूड फ़ाइबर 29-38, एनडीफ 42-54 फीसदी तो फ़ाइबर 21-29 प्रतिशत पाया जाता है। पाचन शक्ति इसकी 60-75 फीसदी तक होती है।

चाय में अदरक का अपना अलग ही महत्व होता है। बिना अदरक वाली चाय की चुस्की आनंददायक नहीं होती है। अदरक (GINGER (जिंजर)) को सब्जियों में डालने से सब्जियों का जायका भी बढ़ जाता है और चाय में डालने से चाय की चुस्की आनंदित कर देती है। अदरक हर घर की जरूरत है।

आप अपने घर के गमले में अदरक का पौधा लगाकर कर सकते हैं अपने जीवन को आनंदित। अदरक का उपयोग हम सभी अपने-अपने घरों में करते हैं। कुछ लोग इसका उपयोग मसाले के तौर पर करते हैं, तो कुछ गार्निशिंग के लिए। इसके अरोमा और फ्लेवर से खाने का स्वाद चार गुना बढ़ जाता है।

घर में कैसे उगाएं अदरक ?

लोगों की सेहत के लिए अदरक का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है और यह घरेलु इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े में मौजूद तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। यह हमारे तनाव को कम करने में भी मदद करता है। इस प्रकार यदि हम घर पर ही शुद्ध व ताजी अदरक उगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आसान से तरीके हैं।

– सर्वप्रथम हमें बाजार से अदरक की जड़ें लेकर आना चाहिए। फिर उन्हें घर पर गमले अथवा घर के आस-पास बगीचे में लगा देना चाहिए, फिर वह धीरे-धीरे अंकुरित होगी और कुछ समय बाद अदरक का पौधा बनने लगेगा।

– दूसरी प्रकिया के मुताबिक, बीज के रूप में हम गमले या बगीचे में अदरक के लगभग 2 से 2.5 इंच लंबे टुकड़ों को मिट्टी में गाड़ देंगे, जिससे धीरे धीरे अदरक का पौधा अंकुरित होगा और यह पौधा बड़ा हो जाएगा।

२० से २५ दिन में तैयार हो जाता है अदरक

अच्छी तरह से नियमित देखभाल एवं समय-समय पर छिड़काव करने से अदरक का पौधा तेजी से विकास करता है। एक स्वस्थ पौधा करीब २० से २५ दिन में अदरक तैयार कर देता है।

अदरक के पौधे की सुरक्षा एवं रखरखाव

जी हां परीक्षणों के मुताबिक तितली मटर (अपराजिता) के फूलों से बनी चाय की चुस्की, मधुमेह यानी कि डायबिटीज पीड़ितों के लिए मददगार होगी। जांच परीक्षणों के मुताबिक इसके तत्व ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं।

पशुओं का पोषक चारा

1- घर पर ही गमले में अदरक उगा रहे हैं, तो हमें गमले को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसे समय-समय पर धूप और जल मिल सके।
2- बगीचे में अगर अदरक उगा रहे हैं, तो पौधे को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां धूप पड़ती हो और जल आसानी से मिल सके।
3- ध्यान रहे कि अदरक के पौधे में जल अधिक नहीं डालना चाहिए। अधिक जल से पौधे में सड़न आ सकती है।
4- अदरक के पौधे वाले गमले अथवा बगीचे में जल निकास की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
5- अदरक के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना ज्यादा रहती है।
6- नियमित पौधे की देखभाल एवं समय-समय पर छिड़काव करना चाहिए।
7- नीबूं पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से कीटों से निजात मिलती है।

महंगी होती किसानी के बीच, किसान अपने खेत में यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफेदा या नीलगिरी (NILGIRI) के नाम से भी जाना जाता है, का पौधा लगाकर कम लागत में करोड़ों रुपये कमा सकते हैं!

यूकेलिप्टस की कीमत क्या है? इसका पौधा कितने दिन में परिपक्व पेड़ बन जाता है? क्या यूकेलिप्टस धरती से पानी सोख लेता है? और क्या करोड़ों रुपये की हैसियत रखने वाले इस पेड़ को लगाने के नुकसान भी हैं? सारे सवालों के जवाब जानें साथ-साथ।

पहली बात यह कि, महज एक एकड़ के खेत में लगाए गए नीलगिरी (यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS)) के पेड़ दस साल बाद, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का मुनाफा देने में कारगर हैं। वो ऐसे कि सफेदा यानी नीलगिरी या फिर कहें कि यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) का पेड़ पूर्णतः विकसित होने में लगभग दशक भर का समय लेता है।

दीर्घ और अल्पकालिक कमाई

ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए आदर्श तरीकों से, इन पेड़ों के बीच की जमीन पर अल्प अवधि में लाभदायक फसल, साग सब्जियां आदि लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में, दीर्घकाल में लाभकारी सफेदा का पेड़ जब तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक खेत में लगाई गई अन्य फसलों से नियमित लाभ हासिल किया जा सकता है। मतलब, दशक भर में कटाई के लिए तैयार होने वाले सफेदा के पेड़ों के बीच हल्दी, अदरक, साग-भाजी लगाकर कमाई की जा सकती है। तो हुई न, हींग लगे न फिटकरी, रंग आए चोखा वाली बात!

सफेदा (SAFEDA)/नीलगिरी (NILGIRI)/यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) का उपयोग

आम तौर पर भारत में पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में सफेदा के पेड़ों की व्यापक तौर पर फार्मिंग हो रही है।

मजबूती, लचीलेपन के कारण पसंद की जाने वाली यूकेलिप्टस की लकड़ियों का मुख्य तौर पर उपयोग फर्नीचर बनाने से लेकर भवन निर्माण आदि में किया जाता है। खेल आदि की वस्तुओं में भी इनका उपयोग होता है।

मटुर प्रकृति का पेड़

जैसा कि प्रचलित है, सफेदा (SAFEDA)/नीलगिरी (NILGIRI)/यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) का पौधा किसी भी तरह की जलवायु में खुद को विकसित करने में कारगर है। पथरीली, काली किसी भी तरह की मिट्टी में नीलगिरी के पौधे विकसित किए जा सकते हैं।

कृषि विज्ञान परीक्षणों के मुताबिक 6.5 से 7.5 के P.H.मध्यमान वाली जमीन यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) के पौधे के विकास में खासी मददगार होती है।

यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) से जुड़ी आशंकाएं भी

सफेदा यानी यूकेलिप्टस (EUCALYPTUS) की खेती को लेकर कुछ मतांतर भी हैं। ऐसी भी राय है कि इसके पेड़ लगाने से भूजलस्तर में गिरावट हो सकती है। हालांकि सरकारी स्तर पर इस बारे में कोई अधिसूचना आदि प्रदान नहीं की गई है। साथ ही यह भी एक और राय है कि, सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में किसानों ने इस पौधे से लाभ कमाने में कम ही रुचि दिखाई है।

एक एकड़, दस साल और लाभ एक करोड़

बहुत कम लागत में तैयार होने वाले सफेदा या फिर यूकेलिप्टस पेड़ की लकड़ी का बाजार भाव छह रुपये प्रति किलो के आसपास है। कम देखभाल वाले सफेदा के पेड़ में मतलब, हर तरह से बचत ही बचत है।

एक परिपक्व पेड़ का वजन चार सौ किलो के लगभग होता है। जबकि एक हेक्टेयर खेत में लगभग एक से डेढ़ हज़ार पौधों को पेड़ों का रूप दिया जा सकता है।

यूकेलिप्टस के पेड़ों से कमाई कर रहे किसानों की मानें, तो इस की खेती से दस सालों बाद तकरीबन एक करोड़ रूपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है।

पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए एक वरदान है कुदरत का यह वरदान मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार से यह पेड़-पौधे जड़ी बूटियां मानव शरीर और मानव जीवन काल को बेहतर बनाते हैं। पेड़ पौधे मानवी जीवन का एक महत्वपूर्ण चक्र है। विभिन्न प्रकार की ग्रीष्म कालीन जड़ी बूटियां रोग निवारण करने के लिए इन जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इन जड़ी-बूटियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती है अतः या जड़ी बूटियां मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह ग्रीष्मकालीन जड़ी बूटियां, औषधि पौधे न केवल रोगों से निवारण अपितु विभिन्न प्रकार से आय का साधन भी बनाए रखते हैं। औषधीय पौधे शरीर को निरोग बनाए रखते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधि जैसे तुलसी पीपल, और, बरगद तथा नीम आदि की पूजा-अर्चना भी की जाती है।

घर पर उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन जड़ी बूटियां

ग्रीष्मकालीन जड़ी बूटियां जिनको आप घर पर उगा सकते हैं, घर पर इनको कुछ आसान तरीकों से उगाया जा सकता है। यह जड़ी बूटियां और इनको उगाने के तरीके निम्न प्रकार हैं

नीम

नीम का पौधा गर्म जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है नीम का पेड़ बहुत ही शुष्क होता है। आप घर पर नीम के पौधे को आसानी से गमले में उगा सकते हैं। इसको आपको लगभग 35 डिग्री के तापमान पर उगाना होता है।

नीम का पौधा (NEEM PLANT)

नीम के पौधे को आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, नीम के पेड़ से गिरे हुए फल को आपको अच्छे से धोकर उनके बीच की गुणवत्ता तथा खाद मिट्टी में मिला कर पौधों को रोपड़ करना होता है। नीम के अंकुरित लगभग 1 से 3 सप्ताह का टाइम ले सकते हैं। बगीचों में बड़े छेद कर युवा नीम के पौधों को रोपण किया जाता है और पेड़ अपनी लंबाई प्राप्त कर ले तो उन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। नीम चर्म रोग, पीलिया, कैंसर आदि जैसे रोगों का निवारण करता है।

तुलसी

तुलसी के पौधे को घर पर उगाने के लिए आपको घर के किसी भी हिस्से या फिर गमले में बीज को मिट्टी में कम से कम 1 से 4 इंच लगभग गहराई में तुलसी के बीज को रोपण करना होता है। घर पर तुलसी के पौधा उगाने के लिए बस आपको अपनी उंगलियों से मिट्टी में इनको छिड़क देना होता है क्योंकि तुलसी के बीज बहुत ही छोटे होते हैं। जब तक बीच पूरी तरह से अंकुरित ना हो जाए आपको मिट्टी में नमी बनाए रखना है। यह लगभग 1 से 2 सप्ताह के बीच उगना शुरू हो जाते हैं। आपको तुलसी के पौधे में ज्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि इस वजह से पौधे सड़ सकते हैं तथा उन्हें फंगस भी लग सकते हैं। घर पर तुलसी के पौधा लगाने से पहले आपको 70% मिट्टी तथा 30 प्रतिशत रेत का इस्तेमाल करना होता है।
तुलसी की पत्तियां खांसी, सर्दी, जुखाम, लीवर की बीमारी मलेरिया, सास से संबंधित बीमारी, दांत रोग इत्यादि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है।

बेल

बेल का पौधा आप आसानी से गमले या फिर किसी जमीन पर उगा सकते हैं। इन बेल के बीजों का रोपण करते समय अच्छी खाद और मिट्टी के साथ पानी की मात्रा को नियमित रूप से देना होता है।

बेल का पौधा (BEL OR BILVA FRUIT)
बेल के पौधे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं। जैसे: लीवर की चोट, यदि आपको वजन घटाना हो या फिर बहुत जादा दस्त हो, आंतों में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी, कब्ज की समस्या तथा चिकित्सा में बेल की पत्तियों और छालों और जड़ों का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की औषधि का निर्माण किया जाता है।

आंवला

घर पर किसी भी गमले या जमीन पर आप आंवले के पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ के लिए आपको मिट्टी का गहरा और फैलाव दार गमला लेना चाहिए। इससे पौधों को फैलने में अच्छी जगह मिलती है। गमले या फिर घर के किसी भी जमीन के हिस्से में पॉटिंग मिलाकर आंवले के बीजों का रोपण करें।

आंवला (ANWLA OR AMLA OR GOOSEBERRY)
आंवले में विभिन्न प्रकार का औषधि गुण मौजूद होता है आंवले में विटामिन की मात्रा पाई जाती है। इससे विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण होता है जैसे: खांसी, सांस की समस्या, रक्त पित्त, दमा, छाती रोग, मूत्र निकास रोग, हृदय रोग, क्षय रोग आदि रोगों में आंवला सहायक होता है।

घृत कुमारी

घृतकुमारी जिसको हम एलोवेरा के नाम से पुकारते हैं। एलोवेरा के पौधे को आप किसी भी गमले या फिर जमीन पर आसानी से उगा सकते हैं। यह बहुत ही तेजी से उगने वाला पौधा है जो घर के किसी भी हिस्से में उग सकता है। एलोवेरा के पौधे आपको ज्यादातर भारत के हर घर में नजर आए होंगे, क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं।

घृतकुमारी OR एलोवेरा (ALOEVERA)
एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व त्वचा के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। त्वचा के विभिन्न प्रकार के काले धब्बे दाने, कील मुहांसों आदि समस्याओं से बचने के लिए आप एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। यह अन्य समस्याओं जैसे जलन, डैंड्रफ, खरोच, घायल स्थानों, दाद खाज खुजली, सोरायसिस, सेबोरिया, घाव इत्यादि के लिए बहुत सहायक है।

अदरक

अदरक के पौधों को घर पर या फिर गमले में उगाने के लिए आपको सबसे पहले अदरक के प्रकंद का चुनाव करना होता है, प्रकंद के उच्च कोटि को चुने करें। घर पर अदरक के पौधे लगाने के लिए आप बाजार से इनकी बीज भी ले सकते हैं। गमले में 14 से 12 इंच तक मिट्टी को भर ले, तथा खाद और कंपोस्ट दोनों को मिलाएं। गमले में अदरक के टुकड़े को डाले, गमले का जल निकास नियमित रूप से बनाए रखें।

तुलसी का पौधा स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय पौधा माना गया है। हिन्दू धर्म मे तुलसी का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह धार्मिक पौधा होने कारण घर-घर पूजा जाता है। कोई तुलसी को धर्म और आस्था से जोड़ कर देखता है, तो कोई सेहत के लाभ उठाने के लिए तुलसी का प्रयोग करता है। यही वजह है कि तुलसी का पौधा लगभग हर हिन्दू के घर में पाया जाता है।

तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के उपाय

धर्म और आस्था के साथ-साथ सेहत के लिए लाभकारी तुलसी के पौधों का प्रसाद में भी काफी महत्व है। देशी नुस्खे में सर्दी-जुकाम दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर पीने से आराम मिलता है। घर पर तुलसी के पौधा उगाने के लिए बस आपको अपनी उंगलियों से मिट्टी में इनको छिड़क देना होता है क्योंकि तुलसी के बीज बहुत ही छोटे होते हैं।

लेकिन लोगों का मानना है कि इतने उपयोगी पौधे को हरा-भरा रखना उतना ही कठिन है। तमाम लोगों का कहना है कि तुलसी का पौधा लू-गर्मी लगने के कारण सूख जाता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि अधिक सर्दी में ओस का शिकार होने से तुलसी का पौधा सूख जाता है।

तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के ये मुख्य उपाय हैं

1 – तुलसी के पौधे को 20 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी लगाएं। जिससे मॉइश्चर मिट्टी मिले।
2 – बारिश के मौसम में तुलसी के पौधे में ज्यादा पानी भरा रहना नुकसानदायक है। इसलिए पौधे के नीचे सीमित पानी ही रहना चाहिए।
3 – हर महीने 2 चम्मच नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। इससे पौधा सूखेगा नहीं।
4 – पौधे की मिट्टी को समय-समय पर खुरपी से खोदकर इधर-उधर करते रहें।
5 – तुलसी के पौधे के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रहनी चाहिए।

तुलसी के पौधे के साथ जुड़ी है धर्म और आस्था

- तुलसी के पौधे से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए अगर आप पौधे की पूजा करते हैं तो जरूर करें, मगर कोशिश करें कि रोज तुलसी के पौधे से पत्तियों को ना तोड़ें।
- यदि आप दिया या अगरबती जलाते हैं तो पौधे से इन चीजों को दूर रखने की कोशिश करें। दरअसल धुएं और तेल से भी तुलसी को नुकसान पहुंचता है।

पशुपालन-पशुचारा

डेयरी कैटल अर्थात दुधारू पशु, डेयरी उद्योग या पशुपालन की रीढ़ होती है, लेकिन इन पशुओं में आए दिन कई तरह के रोग होने का खतरा बना रहता है. इसमे सबसे अधिक खतरा थनैला रोग (THANAILA ROG) से होता है, जिसको लेकर पशुपालक हमेशा परेशान रहते हैं.

थनैला रोग केवल पशुओं को ही बीमार नहीं करता बल्कि, पशुपालकों को भी आर्थिक रूप से बीमार कर देता है. पशु के थन में सूजन, थान (अयन) का गरम होना एवं थान का रंग हल्का लाल होना आदि थनैला रोग की प्रमुख पहचान है. थनैला रोग का संक्रमण जब बढ़ जाता है तो दूध निकलने का रास्ता सिकुड़ कर पतला और बारीक हो जाता है, जिससे दूध निकलने में परेशानी होती है. साथ ही दूध का फट के आना, मवाद आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

क्यों होता है दुधारु पशुओं में थनैला रोग ?

दुधारू पशुओं को थनैला रोग थनों में चोट लगने, थन पर गोबर के लगने, मूत्र अथवा कीचड़ के संक्रमण होने से होता है. वहीं दूध दुहते समय साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देने से और पशु बाड़े की नियमित रूप से साफ-सफाई न करने से भी यह संक्रमण होता है. ज्ञात हो कि जब मौसम में नमी अधिक होती है या वर्षाकाल का मौसम होता है, तब इस रोग का प्रकोप और भी बढ़ जाता है.

थनैला रोग की रोकथाम के उपाय

दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत निकट के पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से परामर्श करनी चाहिए. थनैला रोग में होम्योपैथिक पशु दवाई भी बहुत कारगर है.

होम्योपैथिक पशु दवाई की प्रमुख कंपनी गोयल वेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने पशुओं में बढ़ते थनैला रोग के संक्रमण को रोकने के लिए टीटासूल लिक्विड स्प्रे किट का निर्माण किया है जो बेहद असरदार है.

टीटासूल लिक्विड स्प्रे किट – (TEATASULE LIQUID (SPRAY KIT)) थनेला रोग के उपचार के लिए बेहतरीन व कारगर होम्योपैथिक पशु औषधि माना जाता है. यह मादा पशुओं के थनैला रोग के सभी अवस्था के लिए असरदार होम्योपैथिक दवाई है. यह दूध के गुलाबी, दूध में खून के थक्के, दूध में मवाद के कारण पीलापन, दूध फटना, पानी जैसा दूध होना तथा थान का पत्थर जैसा सख़्त होना जैसे स्थिति में बहुत प्रभावी है.

टीटासूल लिक्विड स्प्रे कैसे किया जाता है इस्तेमाल

टीटासूल के एक पैक में टीटासूल नंबर -1 तथा टीटासूल नंबर-2 की 30 मिली स्प्रे बोतल होती है, जिसे रोगग्रस्त पशुओं को सुबह और शाम, दिए गए निर्देशों के अनुसार देना होता है या पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार देना चाहिए

- थन की सूजन व थनैला रोग में एंटीबायोटिक या इंजेक्शन या दवाओं से ज्यादा आराम टीटासूल होम्योपैथिक दवा देता है.
- जब एंटीबायोटिक दवायें काम नहीं करती हैं तब भी टीटासूल आराम देता है
- थनों की सूजन पुरानी पड़ने लगे और थनों के तनु कठोर हो जाये तो टीटासूल थनों के कड़ेपन को दूर करता है और दुग्ध ग्रंथियों को कार्यशील बनाता है.
- थनों के कड़ेपन को व थनों में चिराव आदि को भी टीटासूल ठीक करता है.
- दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के बहाव को नियमित कर कार्यशील बनाने में टीटासूल सहायक होता है.किया है जो बेहद असरदार है.

भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं. देश के किसान कृषि के साथ साथ सामान रूप से पशुपालन भी करते हैं. कहा भी जाता है कि कृषि और पशुपालन एक दुसरे का पूरक होता है. पशुपालन से जहाँ एक ओर दुग्ध उत्पादन होता है, वहीं किसानी खेती के लिए सबसे बेहतर खाद भी प्राप्त किया जाता है. गाँव में लगभग सभी किसान खेती के साथ ही पशुपालन भी करते है. दुधारू पशुओं को हर घर में देखा जा सकता है.

भैंस पालन के लिए सबसे जरूरी है की भैंसों का सही चुनाव किया जाए. जो किसान भैंस पालन करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस नस्ल की भैंस को पाला जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके.

दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान अव्वल है. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और किसानी के साथ-साथ पशुपालन भी एक मुख्य कार्य है. हजारों की संख्या में ग्रामीण, पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं. पशु विशेषज्ञों की माने तो दुधारू जानवरों में सबसे ज्यादा दूध देने की क्षमता भैस में होती है, इसी के कारण किसान कम मेहनत में ज्यादा दूध उत्पादन के लिए ज्यादातर भैंस पालन को बेहतर समझते हैं. लेकिन, यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भैंस के किन नस्लों का चुनाव किया जाए जिनकी दूध उत्पादकता की क्षमता सबसे अधिक हो.

दुग्ध उत्पादन पर ही पशुपालक के आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है. अगर दूध देने की क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक है की बिजनेस ठप हो जाएगा या फिर घाटे में चलेगा. इसी के कारण हम यहां किसान भाइयों को भैंस की नस्ल के बारे में बता रहे हैं जिनको घर लाकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

भैंस के किस नस्ल का चुनाव करें ?

मुर्रा नस्ल :
दुनिया में सबसे ज्यादा दुधारू भैंस में मुर्रा नस्ल को माना जाता है. मुर्रा नस्ल की भैंस 1 दिन में 13 से 15 लीटर तक दूध दे सकती है. लेकिन मुर्रा भैंस का पालन करने वाले पशुपालकों की उसके खानपान पर क्या ध्यान देना पड़ता है.

मेहसाना नस्ल :
मेहसाना नस्ल की भैंस भी अच्छी प्रजाति का भैंस माना जाता है. यह 20 से 30 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है. गुजरात और महाराष्ट्र में मेहसाना भैंस का बड़ी मात्रा में पालन किया जाता है.

पंढरपुरी भैंस और सुरती नस्ल की भैस :
महाराष्ट्र में पाए जाने वाली भैंस की नस्ल पंढरपुरी अपने दूध देने के क्षमता के कारण ही जानी जाती है. वही सुरती नस्ल की भैंस भी दूध क्षमता में बेहतर होती है. यह दोनों भैंस 1 साल में 1400 लीटर से 1600 लीटर दूध देती है.

जाफराबादी, संभलपुरी भैंस, नीली-रावी भैंस टोड़ा भैंस, साथकनारा भैंस :
डेयरी व्यवसाय करने वाले किसानों के लिए जाफराबादी संबलपुरी बेंड नीली-रावी भैंस, टोड़ा भैंस और साथकनारा भैंस अच्छी नस्ल की भैंसों में मानी जाती है. इन नस्ल की भैंस सालाना 1500 लीटर से 2000 लीटर तक दूध उत्पादन की क्षमता रखती है.

मिट्टी की सेहत - खाद

बाजार में लगातार नकली खाद की बिक्री बढ़ती जा रही है। किसानों को नकली खाद के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इन दिनों बुवाई का सीजन चल रहा है और किसान खाद डालकर ही बुवाई कर रहे हैं। खाद की कीमतें आसमान छू रहीं हैं। खाद की बढ़ती कीमतों के बीच किसान को नुकसान तब होता है, जब ज्यादा से ज्यादा खाद डालने के बाद भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। फसल में अच्छी पैदावार के लिए कहीं ना कहीं नकली खाद ही जिम्मेदार होता है। इस मिलावट के दौर में किसानों को हमेशा यही चिंता रहती है कि जो खाद वह अपनी फसल में डाल रहे हैं क्या वो नकली है या असली?

कैसे करें हम नकली या असली खाद की पहचान

1 – डीएपी खाद (DAP) की पहचान

– किसान भाई ध्यान दें, कि आप जो DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE) खाद खरीद रहे हैं वो असली है या नकली है, इसकी पहचान के लिए किसान भाई डीएपी के कुछ दाने अपने हाथ मे लेकर उसमें चूना मिलाकर तम्बाकू की तरह मसलें। इसको मसलनें के बाद अगर उसमें से ऐसा तेज गंध निकलने लग जाता है, जिसे सूंघना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो समझ जाइए डीएपी खाद असली है। उधर नकली डीएपी खाद सख्त, दानेदार और भूरे व काले रंग की होती है। अगर आप इसको अपने नाखूनों से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। तो आप समझ लीजिए यह कतई नकली खाद है।

2 – यूरिया खाद की पहचान

– प्रायः यूरिया (UREA) के बीज सफेद और चमकदार होते हैं। आकार में एक समान व गोल आकार के होते हैं। यह पानी मे पूरी तरह से घुल जाते हैं। असली यूरिया के घोल को छूने पर ठंडा महसूस होता है। उधर नकली यूरिया खाद के दानों को तवे पर गर्म करके देखें, यदि इसके दाने पिघलें नहीं तो समझो यह यूरिया खाद नकली है। क्योंकि असली यूरिया के दाने गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं।

3 – पोटास की करें पहचान

– असली पोटाश (POTASH) के दाने हमेशा खिले-खिले रहते हैं। पोटाश की असली पहचान इसका सफेद नमक व लाल मिर्च जैसा मिश्रण ही होता है। उधर नकली पोटाश की पहचान के लिए आप उसके दानों पर पानी की कुछ बूंदे डाल दें, इसके बाद अगर ये आपस मे चिपक जाते हैं तो समझ लेना कि ये नकली पोटाश है। क्योंकि पोटाश के दाने पानी मे डालने पर कभी भी नहीं चिपकते हैं।

*अपने खेत में खाद लगाने के लिए किसान भाई खाद खरीदने से पहले इसी तरह असली और नकली खाद की पहचान जरूर कर लें।

अब देश के किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात मे नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। अब उत्तर-प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बंद पड़े खाद कारखानों को दोबारा खोला जा रहा है। इन कारखानों में जल्दी ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रहीं हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में कारखानों में यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

हिंदुस्तान उर्वरक और रासायन लिमिटेड के जनरल कामेश्वर झा ने बताया कि प्लांट में सभी मशीनों की जांच की जा रही है। कम्पनी का प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से उत्पादन कार्य शुरू किया जाए। इसकी शुरुआत जुलाई में ही शुरू हो जाएगी। और अगस्त के महीने में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन होगा। पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू हो जाने के बाद यहां प्रतिदिन 3850 नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा।

बीस साल बाद शुरू होगा सिंदरी खाद कारखाना

बता दें कि पांच सितंबर 2002 को स्व. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वित्तीय संकट के चलते सिंदरी खाद कारखाना बंद हो गया था। करीब 20 साल बाद फिर से कारखाना शुरू होने जा रहा है। सिंदरी खाद कारखाना से देश मे हरित क्रांति लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यूरिया की कमी होगी दूर

साल 1951 में सिंदरी कारखाने की पहली यूनिट का उत्पादन शुरू हुआ था। उन दिनों प्लांट का संचालन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता था। यह कारखाना पूर्वी भारत में एफसीआई द्वारा संचालित एकमात्र यूरिया उत्पादन कारखाना था। इसके बंद होने के बाद पूर्वी राज्यों में यूरिया की भारी किल्लत हो गई थी। सभी आठ कारखाने बंद हो गए थे। और यूरिया की खपत लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थिति ऐसी बन गई है कि देश को यूरिया का आयात करना पड़ा रहा है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने गौरखपुर, सिंदरी और बरौनी में फिर से बंद पड़े यूरिया खाद कारखानों को शुरू करने की योजना बनाई है।

बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्लांट शुरू करने की योजना के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

डीएपी से अभी राहत नहीं

सरकार भले ही यूरिया की किल्लत दूर करने का दावा कर रही है। लेकिन फिलहाल डीएपी पर कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डीएपी की किल्लत और बढ़ेगी।

प्रगतिशील किसान

एक ऐसा शख्स जो की मुफ्त में किसानों को बीज देता है और धान के दुर्लभ खेती के किस्मों को बढ़ावा देता है

देश में धान की खेती की शुरुआत मानसून की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है. यह खरीफ सीजन की मुख्य फसलों में से एक है. हर वर्ष किसान नई – नई किस्मों के बीज का इस्तमाल करके फसल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे है.

लेकिन क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया की पहले के लोग आखिर कैसे धान की किस्मों की खेती करते होंगे. आखिर कौन सी किस्में थी जो कि लुप्त हो चुकी है. आखिर पुराने जमाने के लोग ज्यादा शक्तिशाली और अभी के मुकाबले ज्यादा देर तक क्यों जिंदा रहते थे. अवश्य ही वे लोग अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते होंगे और व्यायाम करते थे. आज के समय वो सब लुप्त हो रहा है. उस समय के धान में पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती थी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा उत्पादन के लिए किसानों ने उन्नत किस्म की धान की खेती करना शुरू कर दी.

परंतु एक इकोलॉजिकल साइंटिस्ट जिनका नाम देबल देब (DEBAL DEB) है, वो पुरानी किस्मों को खेतों में लाने का कार्य कर रहे है. इसकी शुरुआत 1991 में दक्षिणी बंगाल में हुई थी. जहां पर देबल देब ने देखा कि एक आदिवासी किसान की गर्भवती पत्नी उबले हुए भुटमुड़ी चावल के माड़ को पी रही थी. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भुटमुड़ी चावल के माड़ को पीने से एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है. यह देखने के बाद देबल देब इसके बारे में जानने की इच्छा हुई. जिसके बाद देबल देब ने इसके बारे में जानने दुर्लभ, स्वदेशी चावलों पर शोध करना शुरू किया. फिर उन्होंने कुछ किसानों के साथ मिलकर इस प्रकार के दुर्लभ और मूल्यवान चावलो की किस्मों को इक्कठा करना शुरू किया और साथ ही इनकी खेती करना इनका लक्ष्य था.

1994 में इन्होंने जीवित देशी किस्मों पर सर्वेक्षण करना शुरू किया. 2001 में इन्होंने बसुधा फार्म की स्थापना की और 2006 में इनका शोध आखिर कार पूरा हुआ. इन्हे पता चला कि 1970 तक भारत में चावल के लगभग 1,10,000 से अधिक विभिन्न किस्में थी. परंतु उनके शोध के बाद 90 प्रतिशत किस्में गायब हो चुकी थी. इन्होंने सरकार और कई निजी संस्थानों से मदद मांगने की कोशिश की परंतु किसी ने उनकी मदद नहीं की.

धान बीज बैंक के बारे में जानकारी

जब देबल देब को कही से भी सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए ओडिशा में धान बीज बैंक की स्थापना की. इस बैंक से कोई भी किसान चावल की पुरानी किस्म को देकर कोई भी देसी किस्म मुफ्त में ले सकता है. धान बैंक के पास कई प्रकार की किस्म है और साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसे चावल की किस्म जिसमे की चांदी के अंश भी पाए जाते है. 15 ऐसी प्रजातियां जो की समुद्र के पानी में भी उग सकते है. 12 ऐसी प्रजातियां जो की सूखे में भी उग सकती है. इसलिए देबल देब को 'राइस वारियर ऑफ़ इंडिया' और 'सीड वारियर' के रूप में भी जाना जाता है।

140 से ज्यादा किस्मों के देसी बीज बांट दिए हैं अब तक

मध्यप्रदेश के रहने वाले 44 वर्षीय किसान केदार सैनी, देश में 17 राज्यों के हजारों लोगों को मुफ्त में बीज बांट चुके हैं। वह देसी बीज लोगों तक पहुंचाकर देश और शहर में हरियाली फैलाना चाहते हैं। वह अब तक 140 से ज्यादा किस्मों के देसी बीज लोगों में बांट चुके हैं।

गुना जिले के रुठियाई गांव के केदार सैनी 2019 से गेल इंडिया और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे प्रोजेक्ट्स पर पौधे लगाने का काम भी कर चुके हैं। केदार अब तक देश के 17 राज्यों में अलग-अलग किसानों को डाक के जरिए देसी सब्जियों और औषधीय पौधों के बीच पहुंचा चुके हैं। उनका कहना है कि वह बीज बांटने का काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी देसी भोजन पर ध्यान दे। देसी किस्मों के बीज कई सालों तक सुरक्षित रहते हैं।

केदार सैनी के बारे में

जैसा कि हमने बताया कि केदार सैनी मध्यप्रदेश के गुना जिले के रुठियाई गांव रहने वाले हैं। केदार सैनी ने हिंदी विषय से एमए किया है। उनके पिताजी के जाने के बाद उनकी माँ के नाम पर केवल चार बीघा जमीन आई। शुरुआत में केदार ने अपनी जमीन के साथ-साथ दूसरों की जमीन भी किराए पर लेकर खेती-किसानी की। केदार पारंपरिक खेती से ज्यादा बागवानी में ज्यादा रुचि रखते हैं। वो हमेशा अलग किस्म की सब्जियां उगाते हैं। केदार को देसी किस्मों के बीज इकट्ठा करना अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तो वह इन देसी बीजों को बेच भी देते हैं। केदार कक्षा 7 वीं से बीज इकट्ठा करके बेचने का काम करते हैं। उनकी जेब में हमेशा बीज रखे मिलते हैं।

केदार फिलहाल इंदौर में प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत बन रहे प्रोजेक्ट में पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा वह समृद्धि पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत एक मिशन भी चला रहे हैं।

कोरोना महामारी में डाक से भेजे थे देसी बीज

केदार सैनी ने वैश्विक कोरोना महामारी के समय जरूरतमंद लोगों को डाक से देसी बीज भेजे थे। उन्होंने इन बीजों को पिछले 7 सालों में इकट्ठा किया था। और सभी को मुफ्त में डाक से भेजे थे। केवल डाक शुल्क ही लिया था।

बचपन से ही पौधों के प्रति लगाव रखते हैं केदार

केदार सैनी बचपन से ही पौधों के प्रति लगाव रखते हैं। वह दुर्लभ जड़ी-बूटियों, फलों एवं दुर्लभ सब्जियों आदि के बीज इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंद लोगों तक इन्हें पहुंचाते हैं।

देश भर में प्रति दिन लगभग १ हजार टन फूल नदियों में बहाए या फेंके जाते हैं. इन फूलों के सड़ने से हानिकारक और विषाक्त अव्यव नदियों के पानी को गंदा करते हैं और वातावरण पर भी इसका बुरा असर होता है. रोजाना बड़ी मात्र में फूल कूड़ें में भी फेकें जाते है, जो सड़कर बदबू पैदा करते हैं.

ऐसे में देश के कुछ युवाओं ने वेस्ट से बेस्ट बनाने की तरकीब निकालकर इस बदबू को खुशबु में बदल दिया है. गाँव देहात की मंदिरों से लेकर बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी मात्र में फूल चढ़ाए जाते हैं, जो एक बार उपयोग में लाने के बाद वेस्ट बन जाते हैं, मगर इन्हीं वेस्ट फूलों से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया जा सकता हैं. अगर आपके आस पास भी ऐसे वेस्ट फूल उपलब्ध हों तो शुरू कर सकते हैं, अगरबत्ती निर्माण का व्यवसाय.

जानते हैं वेस्ट फूलों से अगरबत्ती बनाने कि पूरी प्रक्रिया

आवश्यक सामग्री :

वेस्ट फूलों से अगरबत्ती बनाने के लिए कुछ सामग्रियों कि जरूरत होगी जिसमे प्रमुख है वेस्ट या ताजा फूल, लकड़ी का पतला स्टिक और एक पाउडर बनाने वाली मशीन. आप पूरी तरह से स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन का प्रयोग भी कर सकते हैं.

कैसे बनाएंगे वेस्ट फूलों से अगरबत्ती ?

सबसे पहले उपयोग में ना आने वाले अर्थात वेस्ट फूलों को एकत्रित कर लें. मंदिरो में चढ़ाए गए फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बड़े बड़े समारोह या उतसव में भी बड़ी मात्र में फूलों का उपयोग होता है, वहां से भी फूल एकत्रित कर सकते हैं.

• फूलों में जैविक घोल का छिड़काव कर लें. इससे हानिकारक कीटों को हटाने में मदद मिलती है.

• अब एकत्रित फूलों को छांटकर उसमें से खराब फूल, धागे या अन्य पत्तियों को हटा दें.

• अब साफ़ किये हुए फूलों में से पत्तियों को निकालकर धूप में सुखा लें.

• सूखे फूल को मशीन में डालकर उसका पावडर बना लें.

• अब पावडर को अच्छी तरह से गूँथ ले.

• अब लकड़ी की पतली स्टिक को गुंथे माल में रोल कर उसे अगरबत्ती का रूप दे दें, इस तरह अगरबत्ती बनकर तैयार हो जाएगी.

• लेकिन अगरबत्ती की बिक्री के लिए पैकेजिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योकि पैकेजिंग के आधार पर ही तैयार उत्पाद की बिक्री निर्भार करती है.पैकेजिंग के लिये आकर्षक और डिजाइनदार पैकेट बनवायें. इसके निश्चित मात्र में अगरबत्ती के पैकेटों का बंडल बनाकर बाज़ार में बिक्री के लिये भेज दें.

वेस्ट फूलों से बनाई गई यह अगरबत्ती आग्रेनिक तथा इको फ्रेंडली होती है. इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है. यह वेस्ट फूलों के निवारण का सबसे अच्छा उपाय है. आप इसे घर में कुटीर उद्योग केरूप में कर सकते हैं या फिर बड़े व्यवसाय का भी रूप दे सकते हैं. जिससे आप खुद के मुनाफे के साथ ही साथ अन्य लोगों के लिय रोजगार सृजन भी कर सकते हैं. वहीं वेस्ट फूलों से अगरबत्ती बनाकर जहाँ आप वेस्ट फूलों का सबसे अच्छा निवारण प्रबंधन कर सकते हैं, वही पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

1 जुलाई 2022 से भारत सरकार नें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध (SINGLE USE PLASTIC BAN) लगा दिया है, इसके कारण बाजार से प्लास्टिक की वस्तुएं गायब हो रही हैं. प्लास्टिक के इन्हीं उत्पादों में से एक “प्लास्टिक स्ट्रॉ” (PLASTIC DRINKING STRAW) है. प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का उपयोग अक्सर पेय पदार्थो के लिए किया जाता है.

प्लास्टिक की वस्तुओं पर बैन लगाने के सरकार के इस फैसले से देश में पेय पदार्थ उत्पादक कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ है, और इसी का असर है कि अब प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की जगह पर पेपर स्ट्रॉ (PAPER DRINKING STRAW) की मांग में तेजी आई है. बाजार में पेपर स्ट्रॉ की बढ़ती मांग के कारण पेपर स्ट्रॉ निर्माण एक बड़े व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है.

लेकिन प्रश्न है कि कैसे पेपर स्ट्रॉ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं ?

व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व लेनी होगी सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुमति :

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन
- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
- फर्म का रजिस्ट्रेशन
- दुकान अधिनियम लाइसेंस
- IEC कोड (THE IMPORTER -EXPORTER CODE (IEC))
- एक्सपोर्ट लाइसेंस
- आग और सुरक्षा
- ESI (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION) इ.एस.आई.
- प्रोविडेंट फंड (PROVIDENT FUND (PF))
- प्रदूषण बोर्ड से NO OBJECTION CERTIFICATE
- स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से व्यापार लाइसेंस

किसी भी होटल, रेस्तरां या उत्सव में कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी या लस्सी के लिये स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है. छोटे जूस व्यवसायियों से लेकर बड़ी बड़ी डेयरी या सॉफ्ट ड्रिंक कम्पनियां तक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करती है. अब जब सरकार ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है, तो पेपर स्ट्रॉ की मांग और ज्यादा बढ़ गयी है.

पेपर स्ट्रॉ निर्माण के लिए सामग्री

पेपर स्ट्रॉ निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमे सबसे जरूरी कागज रोल और स्ट्रॉ बनाने वाली मशीन, दूसरी पेपर कटिंग मशीन. इन चीजों से पेपर स्ट्रॉ का कारोबार प्रारंभ किया जा सकता है. इसके लिये रंग भी महत्वपूर्ण सामग्री होता है, जिससे स्ट्रॉ को रंगीन और आकर्षक बनाया जाता है

पेपर स्ट्रॉ बनाने का तरीका

1. सबसे पहले पेपर रोल व रंग अथवा स्याही को पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली मशीन में डालते हैं, जिसके बाद मशीन दोनों को मिलाकर स्ट्रॉ का निर्माण करती है.
2. पहली मशीन से तैयार हुए स्ट्रॉ के मिश्रण को दूसरी मशीन में रखा जाता है, जिसमें निश्चित आकार व नाप के अनुसार टुकड़ों में काटा जाता है, और इसके बाद पेपर स्ट्रॉ बनकर तैयार होता है.
3. अगर किसी अलग डिजाइन या नए तरीके का पेपर स्ट्रॉ बनाना चाहते हैं तो इसके लिये मशीन की सहायता लेना होता है.

पेपर स्ट्रॉ के निर्माण के बाद इसका सही ढंग से पैकेजिंग करना होता है ताकि बाज़ार तक पहुँचाया जा सके. 25, 50 या 100 की गिनती में स्ट्रॉ का एक-एक बंडल बनाया जा सकता है. पैकिंग सामग्री के क्षमतानुसार बंडल बनाया जाता है, जिसे बाजार में बिकने को भेजा जाता है.

अगर जमीन कम हो तो किसान सोच में पड़ जाता है कि कैसे खेती से ज्यादा कमाई होगी. लेकिन जमीन के छोटे टुकड़े में भी खेती करके अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है.

कम जमीन पर भी ज्यादा पैदावार प्राप्त करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. इसको लेकर लगातार प्रयोग किया जाता रहा है. भारत ही नहीं विदेशों में भी कम जमीन में अधिक उपज प्राप्त करने को लेकर प्रयास किए जाते रहे हैं. इस क्षेत्र में इजराईल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

कम भूमि में खेती कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर इजराइल ने बनाया मिसाल

इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नवीन अनुसंधानों के लिये जाना जाता है और इसी के कारण निरंतर चर्चा में रहता है. रक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इजराईल हमेशा नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है. अब कृषि के क्षेत्र में उसके प्रयोग ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आजकल इजरायल द्वारा विकसित की गई वर्टिकल फार्मिंग (VERTICAL FARMING) की आधुनिक तकनीक काफी चर्चा में है और यह तकनीक देश-विदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है.

क्या है वर्टिकल फार्मिंग की आधुनिक तकनीक ?

वर्टिकल फार्मिंग की आधुनिक तकनीक के तहत कम जगह में दीवार बनाकर खेती की जाती है. वर्टिकल फार्मिंग की आधुनिक तकनीक के तहत सबसे पहले लोहे या बांस की मदद से दीवार नुमा ढांचा खड़ा किया जाता है. ढांचे पर छोटे-छोटे गमलों को खाद, मिट्टी और बीज डालकर करीने से रखा जाता है. इसके पौधों की रोपाई नर्सरी की तरह भी गमलों में की जा सकती है.

बहुत उपयोगी है ये वर्टिकल फार्मिंग तकनीक

कम जमीन और कम संसाधनों में खेती करने के लिए यह एक बहुत उपयोगी विकल्प है. हालांकि भारत जैसे देशों में खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ जमीन मौजूद है लेकिन विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ खेती योग्य जमीन की कमी है. इजराइल के पास भी खेती योग्य जमीन कम है जिसके कारण उसे खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी को देखते हुए इजराईल नें वर्टिकल फार्मिंग की आधुनिक तकनीक का इजाद किया जो कम भूमि संसाधनों वाले देशों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है.

चीन, कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस तकनीक को सफलतापूर्वक अपना रहे हैं. बड़े शहरों में अच्छी और ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दूर दराज के गांवों से लाया जाता है. वर्टिकल फार्मिंग के द्वारा अब शहरों में ही वर्टिकल फार्मिंग द्वारा सब्जियों को उगाकर मांग की आपूर्ति करना आसान होता जा रहा है.

ड्रिप इरीगेशन से होती है पानी की बचत

इजरायल द्वारा ही सिंचाई तकनीक ड्रिप इरीगेशन या बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति इस तरह की खेती के लिये उपयोगी होता है. इससे पानी की बर्बादी भी बचती है और पौधों में जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाता है. इस तकनीक का उपयोग अब भारत में भी होने लगा है. इस तकनीक के जरिए अनाज, सब्जियां, मसाले और औषधीय फसलें सभी कुछ उत्पादित की जा रही हैं. इस तकनीक का दूसरा लाभ ये है कि इससे पौधों में कीड़े और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है.

वर्टीकल फार्मिंग रोजगार का भी है माध्यम

बहुत कम जगह में उत्पादन की क्षमता के कारण वर्टीकल फार्मिंग का यह तकनीक शहरी क्षेत्रों के लिए बेहद लाभदायक है. हांलाकि वर्टीकल फार्मिंग में खर्च परंपरागत खेती से ज्यादा है लेकिन यह भी सच है की इससे लाभ भी ज्यादा है. यही कारण है कि मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के लोग नौकरियां छोड़कर वर्टिकल फार्मिंग को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है.

इको फ्रेंडली वर्टीकल फार्मिंग

वर्टीकल फार्मिंग तकनीक जहां कम जमीन में खेती के लिए लाभदायक है, इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदुषण भी कम होता है और पानी एवं अन्य संसाधनों की भी बचत होती है. शहरों में अपनाए जाने के कारण हरियाली तो बढाती ही है साथ ही पर्यावरण को शुद्ध रखने में ये सहायक है. शहरों में उत्पादन करने से परिवहन लागत भी कम हो जाती है.

केमिस्ट्री करने वाला किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग से खेत में पैदा कर रहा मोती, कमाई में कई गुना वृद्धि!

एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम)

जिस तरह मौजूदा दौर के क्रिकेट में ऑलराउंड प्रदर्शन अनिवार्य हो गया है, ठीक उसी तरह खेती-किसानी-बागवानी में भी मौजूद विकल्पों के नियंत्रित एवं समुचित उपयोग एवं दोहन का भी चलन इन दिनों देखा जा रहा है। क्रिकेट के हरफनमौला प्रदर्शन की तरह, खेती किसानी में भी अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (INTEGRATED FARMING SYSTEM) का चलन जरूरी हो गया है।

क्या कारण है कि प्रत्येक किसान उतना नहीं कमा पाता, जितना आधुनिक तकनीक एवं जानकारियों के समन्वय से कृषि करने वाले किसान कमा रहे हैं।

सफल किसानों में से किसी ने जैविक कृषि को आधार बनाया है, तो किसी ने पारंपरिक एवं आधुनिक किसानी के सम्मिश्रण के साथ अन्य किसान मित्रों के समक्ष सफलता के आदर्श स्थापित किए हैं। ऐसी ही युक्ति है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (INTEGRATED FARMING SYSTEM) यानी 'एकीकृत कृषि प्रणाली'। यह कैसी प्रणाली है और कैसे काम करती है, जानिये।

कुछ हट कर काम किसानी करने वालों की फेहरिस्त में शामिल हैं, बिहार के बेगूसराय में रहने वाले 48 वर्षीय प्रगतिशील किसान जय शंकर कुमार भी।

पहले अपने खेत पर काम कर सामान्य कमाई करने वाले केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट जय शंकर की सालाना कमाई में अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (INTEGRATED FARMING SYSTEM) से किसानी करने के कारण आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है।

साधारण किसानी करते थे पहले

सफलता की नई इबारत लिखने वाले जय शंकर सफल होने के पहले तक पारंपरिक तरीके से पारंपरिक फसलों की पैदावार करते थे। इन फसलों के तहत वे मक्का, गेहूं, चावल और मोटे अनाज आदि की फसलें ही अपने खेत पर उगाते थे। इन फसलों से हासिल कम मुनाफे ने उन्हें परिवार के भरण-पोषण के लिए बेहतर मुनाफे के विकल्प की तलाश के लिए प्रेरित किया।

ऐसे मिली सफलता की राह

खेती से मुनाफा बढ़ाने की चाहत में जय शंकर ने कई प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बेगूसराय के वैज्ञानिकों से अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए सतत संपर्क साधे रखा।

पता चली नई युक्ति

कृषि सलाह आधारित कई सेमिनार अटैंड करने के बाद जय शंकर को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (INTEGRATED FARMING SYSTEM) के बारे में पता चला। आसान होता जा रहा है.

इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है ?

इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (INTEGRATED FARMING SYSTEM) यानी एकीकृत कृषि प्रणाली खेती की एक ऐसी पद्धति है, जिसके तहत किसान अपने खेत से सम्बंधित उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके कृषि से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है।

कृषि की इस विधि से छोटे व मझोले किसानों को अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ कृषि से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर फसल उत्पादन और अवशेषों की रीसाइकलिंग (RECYCLING) के द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन में मदद मिलती है।

इस विधि के तहत मुख्य फसलों के साथ दूसरे खेती आधारित छोटे उद्योग, पशुपालन, मछली पालन एवं बागवानी जैसे कार्यों को किया जाता है।

पकड़ ली राह

जय शंकर को किसानी का यह फंडा इतना बढ़िया लगा कि, उन्होंने इसके बाद इस विधि से खेती करने की राह पकड़ ली।

एकीकृत प्रणाली के तहत उन्होंने मुख्य फसल उगाने के साथ, बागवानी, पशु, पक्षी एवं मत्स्य पालन, वर्मीकम्पोस्ट बनाने पर एक साथ काम शुरू कर दिया। उन्हें केवीके ने भी तकनीकी रूप से बहुत सहायता प्रदान की।

मोती का उत्पादन (PEARL FARMING)
खेत पर लगभग 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालने के लिये बनाए गए तालाब के ताजे पानी में, वे मोती की भी खेती कर रहे हैं।

वर्मीकम्पोस्ट के लिए मदद
जय शंकर की वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन में रुचि और समर्पण के कारण कृषि विभाग, बिहार सरकार ने उन्हें 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वे अब हर साल 3000 मीट्रिक टन से ज्यादा वर्मीकम्पोस्ट उत्पादित कर रहे हैं।

बागवानी में भी आजमाए हाथ
बागवानी विभाग ने भी जय शंकर की लगन को देखकर पॉली हाउस और बेमौसमी सब्जियों की खेती के अलावा बाजार में जल्द आपूर्ति हेतु पौधे लगाने के लिए जरूरी मदद प्रदान की।

केवीके, बेगूसराय से भी उनको तकनीकी रूप से जरूरी मदद मिली। केवीके वैज्ञानिकों ने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल में उन्हें सुधार और अपडेशन के लिए समय-समय पर जरूरी सुझाव देकर सुधार करवाए।

कमाई में हुई वृद्धि
एक समय तक जय शंकर की पारिवारिक आय तकरीबन 27000 रुपये प्रति माह या 3.24 लाख रु प्रति वर्ष थी। अब एकीकृत कृषि प्रणाली से खेती करने के कारण यह अब कई गुना बढ़ गयी है।

मोती की खेती, मत्स्य पालन, वर्मीकम्पोस्ट, बागवानी और पक्षियों के पालन-विक्रय के समन्वय से अब उनकी यही आय प्रति माह 1 लाख रुपये या प्रति वर्ष 12 लाख से अधिक हो गई है।

खेत में मोती की चमक बिखेरने वाले जय शंकर अब दूसरों की तरक्की की राह में भी उजाला कर रहे हैं। वे अब बेगूसराय जिले के केवीके से जुड़े ग्रामीण युवाओं की मेंटर ट्रेनर के रूप में मदद करते हैं। साधारण नजर आने वाला उनका खेत अब 'रोल मॉडल' के रूप में कृषि मित्रों की राह प्रशस्त कर रहा है। उनका मानना है, दूसरे किसान भी उनकी तरह अपनी कृषि कमाई में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको, उनकी तरह समर्पण, लगन, सब्र एवं मेहनत भी करनी होगी।

जालंधर में नूरमहल के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान (DIVYA JYOTI JAGRATI SANSTHAN)ने जैविक खेती की प्रेरणा एवं प्रशिक्षण के पुनीत कार्य में मिसाल कायम की है। बीते 15 सालों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रत इस संस्थान ने कैसे अपने मिशन को दिशा दी है, कैसे यहां किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, कैसे सेवादार इसमें हाथ बंटाते हैं जानिये।

सफलता की कहानी
जैविक खेती के मामले में आदर्श नूरमहल के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जनजागृति एवं प्रशिक्षण की शुरुआत कुल 50 एकड़ की भूमि से हुई थी। अब 300 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जा रही है।

अनाज की बंपर पैदावार के लिए आदर्श रही पंजाब की मिट्टी, खेती में व्यापक एवं अनियंत्रित तरीके से हो रहे रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से लगातार उपजाऊ क्षमता खो रही है। जालंधर के नूरमहल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इस समस्या के समाधान की दिशा में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

गौसेवा एवं प्रेरणा
संस्थान में गोसेवा के साथ-साथ पिछले 15 सालों से किसानों को जैविक खेती के लाभ बताकर प्रेरित करने के साथ ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्थान की सफलता का प्रमाण यही है कि साल 2007 में 50 एकड़ भूमि पर शुरू की गई जैविक कृषि आधारित खेती का विस्तार अब 300 एकड़ से भी ज्यादा ऊर्जावान जमीन के रूप में हो गया है। यहां की जा रही जैविक खेती को पर्यावरण संवर्धन की दिशा में मिसाल माना जाता है।

सेवादार करते हैं खेती
संस्थान के सेवादार ही यहां खेती-किसानी का काम संभालते हैं। किसान एवं पर्यावरण के प्रति लगाव रखने वालों को संस्थान में विशेष कैंप की मदद से प्रशिक्षित किया जाता है। गौरतलब है कि गौसेवा, प्रशिक्षण के रूप में जनसेवा एवं जैविक कृषि के प्रसार के लिए प्रेरित कर संस्थान प्रकृति संवर्धन एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अतुलनीय योगदान प्रदान कर रहा है।

रासायनिक खाद के नुकसान
संस्थान के सेवादार शिविरों में इस बारे में जागरूक करते हैं कि रासायनिक खाद व कीटनाशक से लोग किस तरह असाध्य बीमारियों की चपेट में आते हैं। इससे होने वाली शुगर असंतुलन, ब्लड प्रेशर, जोड़ दर्द व कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में लोगों को शिविर में सावधान किया जाता है।

यहां लोगों की इस जिज्ञासा का भी समाधान किया जाता है कि जैविक खेती के कितने सारे फायदे हैं। जैविक कृषि विधि से संस्थान गेहूं, धान, दाल, तेल बीज, हल्दी, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, कद्दू, अरबी की खेती कर रहा है। साथ ही यहां फल एवं औषधीय उपयोग के पौधे भी तैयार किए जाते हैं।

गोमूत्र निर्मित देसी कीटनाशक के फायदे
संस्थान के सेवादार फसल को खरपतवार और अन्य नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाने के लिए खास तौर से तैयार देसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इस स्पेशल कीटनाशक में भांग, नीम, आक, गोमूत्र, धतूरा, लाल मिर्च, खट्टी लस्सी, फिटकरी मिश्रण शामिल रहता है। इसका घोल तैयार किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैविक कृषि के इस स्पेशल स्प्रे का इस्तेमाल समय-समय पर किया जाता है।

जैविक उत्पाद का अच्छा बाजार
जैविक उत्पादों की बिक्री में आसानी होती है, जबकि इसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। इस कारण संस्थान में प्रशिक्षित कई किसान जैविक कृषि को आदर्श मान अब अपना चुके हैं। जैविक कृषि आधारित उत्पादों की डिमांड इतनी है कि, लोग घर पर आकर फसल एवं उत्पाद खरीद लेते हैं। इससे उत्पादक कृषक को मंडी व अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ता।

पृथक मंडी की दरकार

यहां कार्यरत सेवादारों की सलाह है कि जैविक कृषि को सहारा देने के लिए सरकार को जैविक कृषि आधारित उत्पादों के लिए या तो अलग मंडी बनाना चाहिए या फिर मंडी में ही विशिष्ट व्यवस्था के तहत इसके प्रसार के लिए खास प्रबंध किए जाने चाहिए।

संस्थान की खास बात यह है कि, प्रशिक्षण व रहने-खाने की सुविधा यहां मुफ्त प्रदान की जाती है। संस्थान की 50 एकड़ भूमि पर सब्जियां जबकि 250 एकड़ जमीन पर अन्य फसलों को उगाया जाता है।

कथा, प्रवचन के साथ आधुनिक मीडिया

अधिक से अधिक लोगों तक जैविक कृषि की जरूरत, उसके तरीकों एवं लाभ आदि के बारे में उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए संस्थान धार्मिक समागमों में कथा, प्रवचन के माध्यम से प्रेरित करता है।

इसके अलावा आधुनिक संचार माध्यमों खास तौर पर इंटरनेट के प्रचलित सोशल मीडिया जैसे तरीकों से भी जैव कृषि उपयोगिता जानकारी का विस्तार किया जाता है। संस्थान के हितकार खेती प्रकल्प में पैदा ज्यादातर उत्पादों की खपत आश्रम में ही हो जाती है। कुछ उत्पादों के विक्रय के लिए संस्थान में एक पृथक केंद्र स्थापित किया गया है।

गोबर, गोमूत्र आधारित जीव अमृत

जानकारी के अनुसार संस्थान में लगभग 900 देसी नस्ल की गायों की सेवा की जाती है। इन गायों के गोबर से देसी खाद, जबकि गो-मूत्र से जीव अमृत (जीवामृत) निर्मित किया जाता है। इस मिश्रण में गोमूत्र, गुड़ व गोबर की निर्धारित मात्रा मिलाई जाती है। गौरतलब है कि गोबर के जीवाणु जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऑर्गेनिक खेती की ओर किसानों का रुझान तेज़ी से हो रहा है. ऑर्गेनिक खेती से किसानों को दोहरा लाभ है, एक तो उत्पादन का मूल्य अधिक मिलता है और वहीं खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है.

हरियाणा में भी परंपरागत कृषि की तकनीक को छोड़कर कई किसान ऑर्गेनिक खेती (Organic farming) या जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

हरियाणा के चरखी दादरी के एक किसान हैं मनोहर लाल. मनोहर लाल अपनी रेतिले जमीन पर ऑर्गेनिक खेती तकनीक से खजूर व हल्दी उगाकर सबको अचंभित कर दिया है. यह कारनामा उन्होंने अपनी लग्न और नई तकनीक के बल पर कर दिखाया है. किसान मनोहर लाल ने आधुनिक ऑर्गेनिक खेती को अपना कर जो नजीर पेश की है, उससे वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी बन गए हैं.

चरखी दादरी जिले के गोपी गाँव के किसान मनोहर लाल ने परंपरागत खेती से अलग हटकर ऑर्गेनिक खेती कर ना केवल कई फसल उगाई है, बल्कि लाखों रुपये कमाई कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर ली है. किसान मनोहर लाल के अनुसार 2016 से वह टमाटर, मिर्च, खीरा व हरी सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा पैदावार प्राप्त कर रहे हैं. इसी के साथ वह हल्दी की खेती भी करते हैं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है.

कथा, प्रवचन के साथ आधुनिक मीडिया

चरखी दादरी जिले के गोपी गाँव के किसान मनोहर लाल ने परंपरागत खेती से अलग हटकर ऑर्गेनिक खेती कर ना केवल कई फसल उगाई है, बल्कि लाखों रुपये कमाई कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर ली है. किसान मनोहर लाल के अनुसार 2016 से वह टमाटर, मिर्च, खीरा व हरी सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा पैदावार प्राप्त कर रहे हैं. इसी के साथ वह हल्दी की खेती भी करते हैं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है.

आर्गेनिक खेती करके मनोहर लाल ने कम लागत पर ज्यादा पैसे कमाए हैं. उनके अनुसार आर्गेनिक खाद भी वे स्वयं तैयार करते हैं, जिससे सब्जी के पौधों को रोगों से बचाया जा सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि आर्गेनिक खेती स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है क्योकि ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है.

किसान मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने दो एकड़ में नेट हाउस का निर्माण कराया है, जिसमें हरी मिर्च लगाई गयी है. मनोहर लाल को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली है. उन्होंने 5 एकड़ में लगाए हैं जहाँ खजूर के एक पेड़ की कीमत 2600 रुपये है. सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 1950 रुपये रह जाती है. किसान मनोहरलाल की इच्छा हैं कि अन्य किसान भी इस तकनीक को अपनाएं और ज्यादा मुनाफा कमायें.

ज्ञात हो की ऑर्गेनिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक खाद और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है. पानी के भंडारण के लिए तालाब बनाए जाते हैं, जिसमें बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है. इन तालाबों में मछली पालन भी किया जा सकता है. मनोहर लाल द्वारा किये जा रहे ऑर्गेनिक खेती से कई किसान प्रभावित होकर ऑर्गेनिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

मेरी खेती

www.merikheti.com